सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 03, अंक 212, नई दिल्ली, गुरुवार 09 अक्टूबर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता.

03 पटाखों को लेकर परम्पराओं का सम्मान बना रहे और साथ ही प्रदूषण ना बढ़े....

06 उम्र की ढलती सांझ में

08 कद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय ने महामहिम राष्ट्रपति को लिखा पत्र

दिल्ली परिवहन विभाग की दो प्रमुख शाखाओं के कार्यों की जांच अनिवार्य ?
माल रोड क्षेत्रिय कार्यालय तीन क्षेत्रिय कार्यालयों का काम एक जगह (माल रोड, वजीरपुर और रोहिणी) और आटो शाखा

संजय बाटला

दिल्ली के क्षेत्रिय कार्यालय माल रोड जहां दिल्ली के तीन क्षेत्रिय कार्यालयों का कार्यभार संभालने के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा गैर तकनीकी अधिकारी को तकनीकी पद पर अपनी पद के ताकत के बल स्वरूप लगाया हुआ है। इस कार्यालय में अन्य क्षेत्रिय कार्यालयों में होने वाले कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्य होते हैं

1. आफलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट,
2. लर्निंग लाइसेंस रिन्यूल,
3. ई रिक्शा फिटनेस
4. फैंसी और वीआईपी नंबर का पंजीकरण
5. पुराने वाहन के नबर को नए वाहन पर पंजीकरण के आदेश और पंजीकरण
6. पुराने पंजीकृत व्यवसायिक वाहन को निजी नंबर में पंजीकरण के आदेश और पंजीकरण, के साथ
7. अन्य सभी वह कार्य जो दिल्ली में आज की तारीख़ में कार्यरत क्षेत्रिय कार्यालयों में किए जाते है।

इस कार्यालय में परिवहन आयुक्त द्वारा जिस दिन से अपने प्रिय गैर तकनीकी अधिकारी को डीटीओ के पद पर नियुक्त किया है उसी दिन से यहां की कार्यशैली ही बदल गई और क्यों ना बदलती क्योंकि जिस के सिर पर आला अधिकारी का हाथ हो वो जो करे जिस तरह करे उसको रोकने टोकने और पूछने वाला कौन?

आज की तारीख़ में परिवहन विभाग के अधिकतर कार्य आनलाइन आवेदन प्रक्रिया में होते हैं अतः किसी की भी कार्यशैली को अगर सच में जांचना हो तो आसान है पर जांच के आदेश जारी हो तो?

परिवहन विभाग की आटो शाखा जहां दिल्ली की सड़को पर चल रहे तीन पहियों के व्यवसायिक वाहन और पूर्व में रहे परिवहन आयुक्त की मेहरबानी से कुछ चार पहिया वाहन पंजीकृत हो रहे हैं के साथ उनकी सभी विभागीय कार्य जैसे परमिट, हस्तांतरण, वाहन रिप्लेसमेंट, एचपी एडिशन/डिलीशन इत्यादि इसी शाखा में किए जाते हैं। इस शाखा में समय समय पर कार्यरत इंस्पेक्टर सस्पेंड होते रहते है उसके बवाजूद आने वाले इंस्पेक्टरों को कोई डर नहीं लगता और उनकी कार्यशैली ड्राइवर और मालिकों को परेशान करने की बरकरार चलती आ रही है। आज इस शाखा में दो इंस्पेक्टर कार्यरत हैं और उनको काम के देरी या ना होने की पूछने पर जवाब मिलता है मेरा ट्रांसफर करवाएगा जा करवा दे, अर्थात आला अधिकारी का पूरा समर्थन, फ़िर भी जांच नही।

कार्यवाही की संभावना तो इन दोनों शाखाओं पर की ही नही जा सकती क्योंकि स्वयं आला अधिकारी के आदेश पर डीटीओ माल रोड और इंस्पेक्टर ओटो शाखा में नियुक्त किए गए हैं।

जब जनहित के लिए बने सरकारी विभाग का आला अधिकारी स्वयं पद के बल का दुरूपयोग कर जनता के अहित में शामिल हो तो जनता का हित कैसे संभव, बड़ा सवाल?

क्या पटाखों पर बैन से दिल्ली में नहीं होता है प्रदूषण?
CPCB के आंकड़ों ने खोल दी प्रतिबंध की पोल

एक दशक के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में बिना पटाखों के भी दीवाली पर प्रदूषण कम नहीं हुआ। पर्यावरणविदों के अनुसार पटाखों के साथ-साथ अन्य प्रदूषण कारकों पर भी ध्यान देना चाहिए। वाहनों का उत्सर्जन और धूल भी प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से बेहतर हैं क्योंकि इनमें 30-35% तक कम प्रदूषक होते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। जानकर हैरानी भले ही हो, लेकिन सच यही है कि बिना पटाखों के भी राष्ट्रीय राजधानी में किसी दीवाली वायु प्रदूषण कम नहीं हुआ। पटाखों के साथ भी और इनके बिना भी हर साल दीवाली और उससे अगले दिन की हवा "बहुत खराब" या "गंभीर" श्रेणी में ही रही है। पर्यावरणविदों का कहना है कि ऐसे में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध न लगाकर प्रदूषण के अन्य कारकों की रोकथाम पर भी फोकस करना चाहिए।

गौरतलब है कि 2015 से लेकर 2024 तक एक दशक के आंकड़े बताते हैं कि हर साल दीवाली और उससे अगले दिन प्रदूषण के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई। 2018 -19 से पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन स्थितियां तब भी नहीं बदलीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पूर्व अपर निदेशक डॉ एसके त्यागी कहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी किसी एक पर नहीं, सभी पर ध्यान देना होगा। पूरे एनसीआर की एकीकृत कार्ययोजना बनानी होगी। इंडियन पल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन (आईपीसीए) की उप निदेशक डा राधा गोयल का कहना है कि दीवाली पर भी पटाखों से अधिक प्रदूषण वाहनों के उत्सर्जन से होता है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और रिश्तेदारी में जाने के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा धूल भी बड़ा फैक्टर है।

उसकी रोकथाम के लिए प्रयास होने चाहिए। सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी का कहना है कि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के अन्य कारकों की रोकथाम की कार्ययोजना भी दे देनी चाहिए।

2015 से 2024 के बीच एयर इंडेक्स

साल	दिवाली से पहले	दिवाली पर	दिवाली के अगले दिन
2024	307	328	339
2023	220	218	358
2022	259	312	303
2021	314	382	462
2020	339	414	435
2019	287	337	368
2018	338	281	390
2017	302	319	403
2016	404	431	445
2015	353	343	360

(स्रोतः सीपीसीबी)

ग्रीन पटाखों से 30-35 प्रतिशत तक कम होता प्रदूषण

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) -राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के विज्ञानियों के अनुसार ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से बेहतर हैं क्योंकि इनका कैमिकल फार्मूला ऐसा है जिससे पानी की बूंदे निकलती हैं। इससे प्रदूषण कम होता है और धूलकणों को भी पानी की यह बूंदे दबा देती हैं। इनमें प्रदूषक तत्व नाइट्रस आक्साइड व सल्फर आक्साइड 30 से 35 प्रतिशत तक कम होते हैं। मुख्य तौर पर यह पटाखे लाइट एंड साउंड शो के जैसे हैं। इन्हें जलाने पर खुशबू भी आती है।

"टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत" सेवा ही संकल्प है!

पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट

हमारा मकसद सिर्फ मदद नहीं, बदलाव लाना है।

A voice for the voiceless, and a hand for the helpless.

हमारा उद्देश्य है समाज के उन हिस्सों तक पहुँचना जो आज भी भूख, शिक्षा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम जरूरतमंदों को बिना भेदभाव के भोजन, बच्चों को मुफ़्त शिक्षा, और समाज को जागरूकता देने का कार्य कर रहे हैं।

क्या मिलेगा हमसे जुड़कर

Ground-level food distribution,

Getting children free education,

हम मानते हैं – छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है।

If you believe in humanity, equality, and service — then you're already a part of our family.

हमें सपोर्ट करें और एक आवाज़ बनें इस बदलाव की।

Together, let's serve. Together, let's change.

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फार्म भरकर जुड़े,

www.tolwa.com/member.html

स्कैनर को स्कैन कर के भी आप टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से फार्म भर कर जुड़ सकते हैं,

वेब साइट पर www.tolwa.com पर भी जाकर आप फार्म भर के टोलवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। www.tolwa.com

SCAN ME

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत
tolwaindia@gmail.com
www.tolwa.com

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ द्वारा "डीटीसी बचाओ अभियान" का तीसरा दिन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने ₹DTC बचाओ अभियान₹ की शुरुआत के चलते तीसरे दिन इस भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, तथा DTC कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर दिल्ली की विधानसभाओं के विधायक

1. कृष्णा नगर विधानसभा से विधायक श्री अनिल गोयल जी
2. रिठाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कुलवंत राणा जी
3. बवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री श्री रविंद्र इंद्रराज जी
4. नजफगढ़ विधानसभा से विधायक श्रीमती नीलम पहलवान जी
5. त्रि नगर से विधायक श्री तिलक राम गुप्ता जी

तक पहुंचें और उन्हें (DTC)दिल्ली परिवहन निगम की गंभीर समस्याओं से अवगत कराकर पत्र सौंपा1

यह अभियान दिल्ली के 70 विधायकों तथा 7 लोकसभा सांसदों को मांग पत्र सौंपे जाने तक चालू रहेगा, दिल्ली के सभी विधानसभा के विधायक तथा लोकसभा के सांसद पत्र पहुंचने के बाद मामले का संज्ञान नहीं लेने पर मजदूर संघ द्वारा पूर्व में एक चेतावनी पत्र भी जारी किया गया ₹अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो जल्द दिल्ली परिवहन मजदूर संघ बड़े आंदोलन की ओर जाएगा₹1

इस अभियान का तहत दिल्ली की जनता की जीवन रेखा डीटीसी बस सेवा को सशक्त बनाना,निगम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना तथा दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना है1

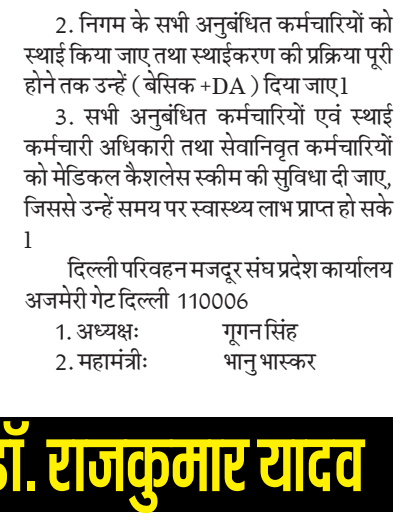

संघ के महामंत्री श्री भानु भास्कर ने कहा कि "DTC को बचाना दिल्ली की जनता के हित में है I आज जरूरत है कि सरकार निगम को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाए और कर्मचारियों की जायज मांगों को स्वीकार करें1"

संघ द्वारा विधायकों को सौंपे जाने वाले विज्ञापन में निम्नलिखित तीन प्रमुख मांगे शामिल हैं:

1. दिल्ली परिवहन निगम की अपनी 5000 बसें तुरंत उपलब्ध कराई जाए ताकि दिल्ली की जनता को सुरक्षित, सुलभ और नियमित परिवहन मिल सके1

2. निगम के सभी अनुबंधित कर्मचारियों को स्थाई किया जाए तथा स्थाईकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें (बेसिक +DA) दिया जाए1

3. सभी अनुबंधित कर्मचारियों एवं स्थाई कर्मचारी अधिकारी तथा सेवानिवृत कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस स्कीम की सुविधा दी जाए, जिससे उन्हें समय पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके 1

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय अजमेरी गेट दिल्ली 110006

1. अध्यक्षः गूगन सिंह
2. महामंत्रीः भानु भास्कर

गगनचुंबी इमारतों के कारण राउरकेला एयरपोर्ट को बंद करने की सोची समझी रणनीति के तहत साजिशः डॉ. राजकुमार यादव

- दावे का विस्तृत विश्लेषण

डॉ. राजकुमार यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी, ओड़िशा) के अध्यक्ष, ने गगनचुंबी इमारतों (स्काईस्क्रैपर्स) के निर्माण को राउरकेला एयरपोर्ट के बंद होने की सोची समझी रणनीति के तहत साजिश से जोड़कर एक विवादास्पद बयान दीया है। यह दावा शहर के शहरी विकास, विमानन सुरक्षा और आर्थिक हितों के बीच टकराव को उजागर करता है व कहीं ना कहीं शहर के आर्थिक विकास में भी रोड़ा अटकाने का काम करता है बल्कि, एयरपोर्ट की स्थिति फंडिंग, लैंड एक्विजिशन और अपग्रेडेशन की चुनौतियों से जुड़ी हुई है। मुट्ठी भर के लोग विकास की दशा और दशा निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रपंचों का वह अनैतिक रणनीति के तहत अपने फायदे के लिए जब एक एजेंडे के तहत कार्य करते हैं तो उसका नुकसान किसी बस्ती, कॉलोनी, शहर या जिला का नहीं बल्कि राज्य व को देश तक को भुगतान करना पड़ सकता है1

डॉ. राजकुमार यादव का बयान सह संदर्भ और पृष्ठभूमि

दावे का सार है कि डॉ. यादव ने आरोप लगाया है कि गगनचुंबी इमारतों के डेवलपर्स या रियल एस्टेट लॉबी एयरपोर्ट को बंद कराने की कोशिश मे लगी है, ताकि ऊंची इमारतों के निर्माण में कोई बाधा न आए। यह दावा राउरकेला के तेज शहरीकरण के संदर्भ में उठाया गया है, जहां स्टील इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स (जैसे NIT राउरकेला) ने हाई-राइज बिल्डिंग्स की मांग बढ़ाई है।

डॉ. यादव की पहचान है कि वे एनसीपी के राज्य स्तर के नेता हैं (एनसीपी अजित पवार गुट से जुड़े), जो ओडिशा में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय हैं। हालांकि, उनके इस बयान पर कोई प्रमुख मीडिया कवरेज या सोशल मीडिया (जैसे X) पर वायरल पोस्ट नहीं मिली। यह दावा स्थानीय राज्य स्तर का तो हो सकता है पर व्यापक ध्यानाकर्षण करता है1

राजनीतिक दृष्टिकोण के तहत एनसीपी जैसे दलों में ऐसे दावे अक्सर आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिए उठाए जाते हैं। यह कोशिश का दावा महत्वपूर्ण व राजनीतिक तब हो जाता है जब सिलसिलेवार रूप से घटनाक्रम जुड़कर एक निर्दिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचते हैं1

राउरकेला एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति (अक्टूबर 2025 तक)

ऑपरेशनल स्टेटस के अनुसार एयरपोर्ट उड़ानों के संदर्भ में बंद है1 यह 2C कैटेगरी में अपग्रेडेड तो है तो किंतु कमर्शियल निजी फ्लाइट्स जारी हैं। एलायंस एयर द्वारा भुवनेश्वर और कोलकाता रूट्स पर दैनिक उड़ानें भी बंद हैं (जो जनवरी 2023 से शुरू हुई थी)। कोई आधिकारिक घोषणा क्लोजर की नहीं हुई किंतु स्थिति के अनुसार निष्क्रिय स्थिति में है1

फंडिंग और समझौते के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के राउरकेला स्टील प्लांट (RSP) द्वारा संचालित, एयरपोर्ट का AAI के साथ 3 वर्षीय समझौता अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा है। SAIL सालाना करोड़ों रुपये खर्च वहन करता है। मई 2024 में रिपोर्ट्स में चिंता जताई गई कि यदि SAIL फंडिंग बंद करे या AAI टेकओवर न करे, तो ऑपरेशन्स प्रभावित हो सकते हैं1 हालांकि, अक्टूबर 2025 तक कोई क्लोजर नहीं हुआ, और अपग्रेडेशन की प्रक्रिया जारी है वहीं सेल द्वारा जमीन हस्तांतरण अभी तक लंबित है1

अपग्रेडेशन प्रयास के तहत स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम व पूर्व केंद्रीय मंत्री व कद्दावर नेता दिलीप राय सहित ओडिशा सरकार भी सक्रिय है। फरवरी 2025 में परिवहन सचिव उषा पाढ़ी ने AAI को 4C कैटेगरी-1 अपग्रेड के लिए पत्र लिखा, जो बड़े विमानों (जैसे बोइंग 737) को हैंडल करने की क्षमता देगा। मुख्यमंत्री मोहन चारण माझी ने फरवरी 2025 में अपग्रेडेशन को ₹वाजिब मांग₹ बताया और SAIL से लैंड सरेंडर करने को कहा। मार्च 2025 में लैंड हर्डल्स पर हाई-लेवल मीटिंग हुई, जहां 278 एकड़ SAIL लैंड और 44 एकड़ प्राइवेट लैंड की जरूरत पर चर्चा हुई। जनवरी 2025 से विभिन्न संगठनों सहित एन सी पी का आंदोलन अपग्रेडेशन, ILS (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) और नाइट लैंडिंग के लिए जारी है।

कोई क्लोजर का आधिकारिक संकेत नहीं किन्तु अक्टूबर 2025 तक, एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। यदि क्लोजर होता, तो मीडिया या सरकारी नोटिफिकेशन में दिखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बावजूद इसके कोई दृष्टिगोचर कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है विस्तारिकरण व अपग्रेडेशन हेतु1

गगनचुंबी इमारतों का प्रभाव प्राकृतिक रूप से इसमें रोड़ा है, अनियमिताओं के तहत एन ओ सी हासिल तो किए गए हैं इसलिये इसकी पुनः जांच आवश्यक है पुनर्वार जरूरी दिशा निर्देशों को देखते हुए यदि सर्वे किया गया तो कुछ दर्जन भर इमारतें इसकी जद में जरूर आएंगी, जरूरत है तो पारदर्शिता पूर्ण एवं तकनीकी रूप से सर्वे की1

विमानन नियम और बाधाएं के अंतर्गत एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और DGCA के नियमों के तहत, एयरपोर्ट के 20 किमी रेडियस में ऊंची इमारतों का निर्माण प्रतिबंधित है। ऑब्स्ट्रक्शन लिमिटिंग सरफेस (OLS) सर्वे (अप्रैल 2025 में शुरू) ऊंचाई का मूल्यांकन करता है। यदि कोई इमारत फ्लाइट पथ में बाधा डालती है (जैसे 150-200 फीट से अधिक), तो NOC अस्वीकृत हो सकती है या इमारत ध्वस्त। राउरकेला में एयरपोर्ट शहर केंद्र से मात्र 6 किमी दूर है किन्तु रिहाइसी इलाके से बिल्कुल सटा हुआ है इसलिए स्काईस्क्रैपर्स के लिए ऊंचाई सीमा (45-60 मीटर) एक चुनौती है।

वर्तमान प्रभाव के तहत राउरकेला में कई प्रमुख स्काईस्क्रैपर बनने के राह में है जो की हवाई अड्डे से मात्र आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, लेकिन प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स (सिविल टाउनशिप, उदीत नगर, पानपोष) OLS सर्वे से अवश्य प्रभावित हो सकते हैं। यह डेवलपर्स के लिए एक बड़ा रोड़ा है, जो एयरपोर्ट क्लोजर का कारण नहीं बनते हुए भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है वही, यदि भविष्य में एयरपोर्ट अपग्रेड होता है, तो प्रतिबंध और सख्त होंगे।

साजिश का कोई सबूत नहीं किंतु स्थितियां विपरीत होने के कारण इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता1 डेवलपर्स या पॉलिटिशियन्स एयरपोर्ट बंद कराने की लॉबिंग कर रहे हैं इसके पुख्ता सबूत तो नहीं है किंतु यह जग जाहिर है कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के पश्चात (अपग्रेडेशन की मांग मजबूत है), जो शहर की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी किंतु स्काईस्क्रैपर के रास्ते में रोड अटकाएगी1 स्काईस्क्रैपर्स का इम्पैक्ट वैश्विक है (जैसे मुंबई या बैंगलोर में), लेकिन राउरकेला में यह विकास की सामान्य चुनौती है व सीमित है।

संभावित कारण और चुनौतियां के अनुसार साजिश से परे

आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दे जो SAIL की फंडिंग अनिश्चितता (RSP की आय में कमी) क्लोजर का मुख्य रिस्क भी है1 RCS-UDAN योजना का कार्यकाल भी 2025 में खत्म हो रहा। लेकिन सरकार अपग्रेडेशन पर फोकस्ड है, जो 4C कैटेगरी में बदलाव ला सकता है किंतु अनिश्चितता बरकरार है1

लाभार्थी और विरोध के तहत अपग्रेडेशन से शहर की अर्थव्यवस्था (स्टील, टूरिज्म) बूस्ट होगी, लेकिन लैंड सरेंडर से SAIL प्रभावित हो सकता। वहीं कुछ जनसमूह व संगठन अपग्रेडेशन की लगातार मांग कर रहे हैं व विस्तारीकरण तक जारी रहेंगे1

वैकल्पिक परिदृश्य मे यदि क्लोजर हुआ (जो अभी नहीं हुआ है), तो ऊंचाई प्रतिबंध हट सकते हैं, जो स्काईस्क्रैपर्स के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा लेकिन यह अनजाने परिणाम है 1 वैकल्पिक रूप से, पारादीप में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना तेज हो सकती है1

निष्कर्ष और सिफारिशें के अनुसार डॉ. राजकुमार यादव का दावा तथ्यों के आधार से पूर्ण समर्थित नहीं लगता किंतु बदलते घटनाक्रम के तहत इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता; यह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी प्रतीत होती है। राउरकेला एयरपोर्ट क्लोजर की कगार पर अवश्य है किंतु जनमानस के आंदोलन, स्थानीय नेताओं के समर्पण के कारण अपग्रेडेशन की दिशा में बढ़ रहा है। स्काईस्क्रैपर्स का प्रभाव ऊंचाई नियमों से है, जो विमानन सुरक्षा का हिस्सा है1

सिफारिशें ये है क़ डिवेलपर्स को AAI से जरूरी NOC लेनी चाहिए। सरकार को OLS सर्वे पूरा कर अपग्रेडेशन तेज करना चाहिए। स्थानीय राज्यस्तरीय लीडर्स जैसे डॉ. यादव को जनमानस के हितों की लड़ाई में आसानी हो तो सरकारी प्रक्रिया व सरकार की नीतियों पर पूर्णतः जन नीति के राह के प्रति आश्वस्त हों जिससे शहर ही नहीं अपितु समस्त जिले व राज्य का संतुलित विकास हो। राउरकेला को स्मार्टसिटी बनाने के लिए एयरपोर्ट और हाई-राइज का सह-अस्तित्व जरूरी है क्योंकि विकास व संरचना को कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है1

मेवाड़ की मीरा बाई जन्मोत्सव

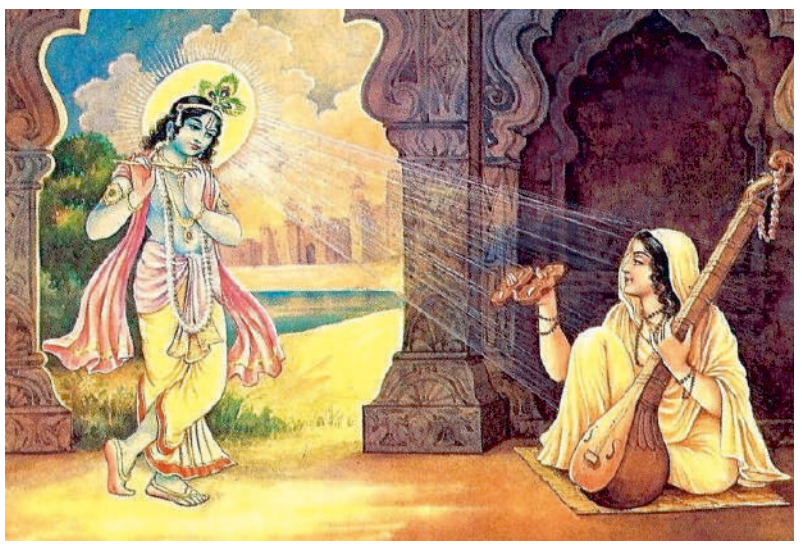

अंसुवन जू सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई।
अब तो बेल फैल गई आणँद फल होई॥
भगति देखि राजी हुई जगत देखि रोई।
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही॥

मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण-प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहां बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीरा भी बारात देखने लगीं। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है? इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर के कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। बस यह बात मीरा के बालमन में एक गांठ की तरह बंध गई।

बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई।

मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे।इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट-फूट कर रोने लगीं। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गईं, जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था।

ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निबटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जातीं और कृष्ण की पूजा करतीं, उनकी मूर्ति के सामने गाती नाचती।

ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल-देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल-देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा-भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है।

राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़ कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थीं और मस्ती में गा रही थीं। राणा मीरा पर चिल्लाया – 'मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो, उसे मेरे सामने लाओ।' मीरा ने जवाब दिया – 'वह सामने बैठा है – मेरा स्वामी – नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गईं। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया।

हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी-कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने-गाने लगती थीं। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थीं और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थीं। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना-मिलना और नारी-मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की। यहां तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटो का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया जब मीरा उस पर सोने चलीं।

जब यातनाएं बरदाश्त से बाहर हो गईं, तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गईं, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होने कृष्ण-भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थीं कि वह गोपी ललिता ही हैं, जिन्होने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थीं। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थयात्रा जारी रखी, वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती-गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रहीं। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गईं।

"इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई इसाई संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए, लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती हैं।

कुछ लोगों के लिए यह समर्पण, शरीर, मन और भावनाओं के परे, एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया, जो बिलकुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई थीं, जो कृष्ण को अपना पति मानती थीं।

जीव गोसांई वृंदावन में वैष्णव-संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसांई के दर्शन करना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेशा भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाजत नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में अपना संदेश भिजवाया कि 'वृंदावन में हर कोई औरत है। अगर यहां कोई पुरुष है तो केवल गिरिधर गोपाल।

आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी है।' इस जबाब से जीव गोसाईं बहुत शर्मिंदा हुए। वह फौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया।

मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे।

नहिं मैं पीहर सासरे, नहिं पियाजी री साथ
मीरा ने गोबिन्द मिल्या जी, गुरु मिलिया रैदास

मीरा ने अनेक पदों व गीतों की रचना की। उनके पदों में उच्च आध्यात्मिक अनुभव हैं। उनमें दिए गए संदेश और अन्य संतों की शिक्षाओं में समानता नजर आती है। उनके पद उनकी आध्यात्मिक उंचाई के अनुभवों का आईना है।

मीरा ने अन्य संतों की तरह कई भाषाओं का प्रयोग किया है, जैसे – हिंदी, गुजराती, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, अरबी, फारसी, मारवाड़ी, संस्कृत, मैथिली और पंजाबी।

मीरा के पदों में भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ-साथ प्रेम की ओजस्वी प्रवाह-धारा और प्रीतम से वियोग की पीड़ा का मर्मभेदी वर्णन मिलता है। प्रेम की साक्षात्मूर्ति मीरा के बराबर शायद ही कोई कवि हो।

मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
छांड़दिई कुल की कानि कहा करै कोई।
संतन ढिग बैठि बैठि लोक लाज खोई।
अंसुवन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई।
दधि मथि घृत काढ़लियौ डारि दई छोई।
भगत देखि राजी भई, जगत देखि रोई।
दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोई।
पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
बस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, किरपा कर अपनायो।
जनम जनम की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो।
खरचै नहिं कोई चोर न लेवै, दिन-दिन बढ़त सवायो।
सत की नाव खेवहिया सतगुरु, भवसागर तर आयो।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख-हरख जस पायो।।

सुवर्चला से ही क्यों किया हनुमान ने जी विवाह

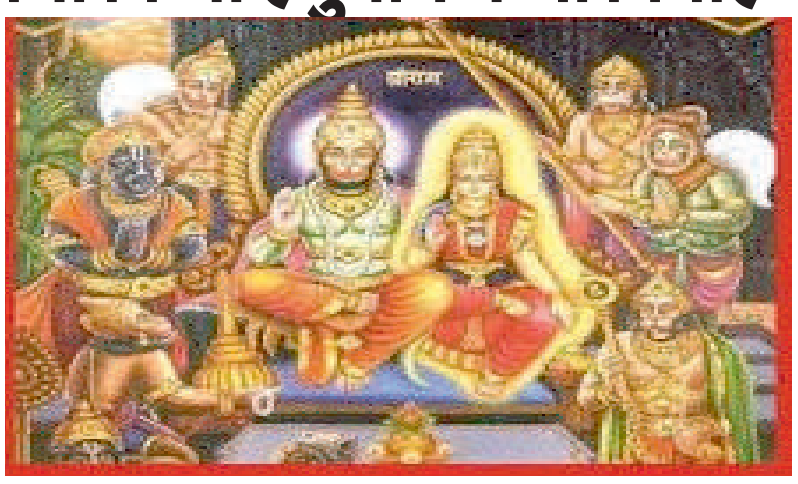

हनुमानजी और उनकी पत्नी सुवर्चला का मंदिर तेलंगाना के खम्मम जिले में है यह एक प्राचीन मंदिर है। यहां हनुमानजी और उनकी पत्नी सुवर्चला की प्रतिमा विराजमान है। यहां की मान्यता है कि जो भी हनुमानजी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उन भक्तों के वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति-पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है।

पाराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमानजी अविवाहित नहीं, विवाहित हैं। उनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से हुआ है। संहिता के अनुसार हनुमानजी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था। सूर्य देव के पास ९ दिव्य विद्याएं थीं। इन सभी विद्याओं का ज्ञान बजरंग बली प्राप्त करना चाहते थे। सूर्य देव ने इन ९ में से ५ विद्याओं का ज्ञान तो हनुमानजी को दे दिया, लेकिन शेष ४ विद्याओं के लिए सूर्य के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया।

शेष ४ दिव्य विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जा सकता था जो विवाहित हों। हनुमानजी बाल ब्रह्मचारी थे, इस कारण सूर्य देव उन्हें शेष चार विद्याओं का ज्ञान देने में असमर्थ हो गए। इस समस्या के निराकरण के लिए सूर्य देव ने हनुमानजी से विवाह करने की बात कही। पहले तो हनुमानजी विवाह के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन उन्हें शेष ४ विद्याओं का ज्ञान पाना ही था। इस कारण अंततः हनुमानजी ने विवाह के लिए हां कर दी।

जब हनुमानजी विवाह के लिए मान गए तब उनके योग्य कन्या की तलाश की गई और यह तलाश खत्म हुई सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला पर। सूर्य देव ने हनुमानजी से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष ४ दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। सूर्य देव ने यह भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। यह सब बातें जानने के बाद हनुमानजी और सुवर्चला का विवाह सूर्य देव ने करवा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गईं और हनुमानजी से अपने गुरु सूर्यदेव से शेष ४ विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमानजी ब्रह्मचारी बने हुए हैं।

श्री हनुमान जी और बाली युद्ध की कथा

कथा का आरंभ तब का है ,,
जब बाली को ब्रम्हा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ,,
की जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा,,
उसकी आधी ताक़त बाली के शरीर मे चली जायेगी,,
और इससे बाली हर युद्ध मे अजेय रहेगा,,
सुग्रीव, बाली दोनों ब्रम्हा के औरस (वरदान द्वारा प्राप्त) पुत्र हैं,,
और ब्रम्हा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है,,
बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था,,
उसका घमंड तब ओर भी बढ़ गया,,
जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूँछ से बांध कर छह महीने तक पूरी दुनिया घूमी,,
रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हरा कर बाली के घमंड का कोई सीमा न रहा,,
अब वो अपने आपको संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था,,
और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई,,
अपने ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल मे पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ फेंक रहा था,,
हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहा था,,
अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिला कर कीचड़ कर दे रहा था,,
एक तरह से अपने ताक़त के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था,,
और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था- है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो,,
है कोई जो अपने माँ का दूध पिया हो,,
जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे,,
इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था,,
संयोग वश उसी जंगल के बीच मे हनुमान जी,, राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे,,
बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न लगा,,
और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले- हे वीरों के वीर,, हे ब्रम्ह अंश,, हे राजकुमार बाली,,
(तब बाली किष्किंधा के युवराज थे) क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो,,
हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो,
फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो,,
अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी से मिला कर उन्हें नष्ट कर रहे हो,,
इससे तुम्हे क्या मिलेगा,,
तुम्हारे औरस पिता ब्रम्हा के वरदान स्वरूप कोई तुहे युद्ध मे नही हरा सकता,,
क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा,,
उसकी आधी शक्ति तुममे समाहित हो जाएगी,,
इसलिए हे कपि राजकुमार अपने बल के घमंड को शांत कर,,
और राम नाम का जाप कर,,
इससे तेरे मन में अपने बल का भान नही होगा,,
और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे,,
इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद चूर हनुमान जी से बोला- ए तुच्छ वानर,, तू हमें शिक्षा दे रहा है, राजकुमार बाली को,,
जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है,,
और जिसके एक हुंकार से बड़े से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है,,
जा तुच्छ वानर, जा और तू ही भक्ति कर अपने राम वाम के,,
और जिस राम की तू बात कर रहा है,
वो है कौन,
और केवल तू ही जानता है राम के बारे में,
मैंने आजतक किसी के मुँह से ये नाम नही सुना,
और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है,,
हनुमान जी ने कहा- प्रभु श्री राम, तीनो लोकों के स्वामी है,,
उनकी महिमा अपरंपार है,
ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भवसागर को पार कर जाए,,
बाली- इतना ही महान है राम तो बुला ज़रा,,
मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में,,
बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जो को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे,,
हनुमान- ए बल के मद में चूर बाली,,
तू क्या प्रभु राम को युद्ध मे हराएगा,,
पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा,,
बाली- तब ठीक है कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा,,
हनुमान जी ने बाली की बात मान ली,,
बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दिया कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा,,
अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे,,
तभी उनके सामने ब्रम्हा जी प्रकट हुए,,
हनुमान जी ने ब्रम्हा जी को प्रणाम किया और बोले- हे जगत पिता आज मुझ जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा,,
ब्रम्हा जी बोले- हे अंजनीसुत, हे शिवांश, हे पवनपुत्र, हे राम भक्त हनुमान,,
मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो,,
और युद्ध के लिए न जाओ,
हनुमान जी ने कहा- हे प्रभु,,
बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता,,
परन्तु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नही कर सकता,,
और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दिया है,,
जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा,,
अन्यथा सारी विश्व मे ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है जो ललकारने पर युद्ध करने इसलिए नही जाता है क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है,,
तब कुछ सोंच कर ब्रम्हा जी ने कहा- ठीक है हनुमान जी,,
पर आप अपने साथ अपनी समस्त सक्तियों को साथ न लेकर जाएं,,
केवल दसवां भाग का बल लेकर जाएं,,
बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दे,,
युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लें,,
हनुमान जी ने ब्रम्हा जी का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकले,,
उधर बाली नगर के बीच मे एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था,,
और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था,,
पूरा नगर इस अदभुत और दो महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था,,
हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुँचे,,
बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा,,
ललकार सुन कर जैसे ही हनुमान जी ने एक पावँ अखाड़े में रखा,,
उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई,,
बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई,,
बाली के शरीर मे बदलाव आने लगे,
उसके शरीर मे ताकत का सैलाब आ गया,
बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा,,
उसके शरीर फट कर खून निकलने लगा,,
बाली को कुछ समझ नही आ रहा था,,
तभी ब्रम्हा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा- पुत्र जितना जल्दी हो सके यहां से दूर अति दूर चले जाओ,
बाली को इस समय कुछ समझ नही आ रहा रहा,,
वो सिर्फ ब्रम्हा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लगा दिया,,
सौ मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया,,
कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रम्हा जी को देख कर बोला- ये सब क्या है,
हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटने की हद तक फूलना,,
फिर आपका वहां अचानक आना और ये कहना कि वहां से जितना दूर हो सके चले जाओ,
मुझे कुछ समझ नही आया,,
ब्रम्हा जी बोले-, पुत्र जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आये, तो उनका आधा बल तममे समा गया, तब तुम्हे कैसा लगा,,
बाली- मुझे ऐसा लग जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रही है,,
ऐसे लगा जैसे इस समस्त संसार मे मेरे तेज़ का सामना कोई नही कर सकता,,
पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट पड़ेगा,,,
ब्रम्हा जो बोले- हे बाली,
मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल दसवां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा,,
पर तुम तो उनके दसवें भाग के आधे बल को भी नही संभाल सके,,
सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते,,
इतना सुन कर बाली पसीना पसीना हो गया,,
और कुछ देर सोच कर बोला- प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां है तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे,,
ब्रम्हा- हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नही कर पाएंगे,,
क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के दसवें भाग को नही सह सकती,,

भीतर संपूर्ण मौन, बाहर यथयोग्य संवाद।

'चुप साधन चुप साध्य है चुपमा चुप समाय।
चुप समझ्या री समझ है समझ्या चुप दे जाय।।"
मौन साध्य है, मगर मौन साधन भी है
अखंड मौन सिद्ध होने के बाद साधन की तरह मौन की आवश्यकता नहीं रहती परंतु जब तक हमारे बाहर बेहोश चेतना वाले लोग है, हमारे भीतर संस्कारबद्ध मन बुद्धि है तब तक साधन की तरह मौन साधने की जरूरत रहती है।
इसके पर्याय है-
निस्तब्धता, मूकता, मूकभाव, मौन, तूष्णीभाव, नीरवता, अनालाप, अभाषण, नि:शब्दता, वाक् कृपणता, वर्णनाभाव, शांति, चुप्पी, चुप्पापन, सन्नाटा, अबोला, खामोशी।
यह सिर्फ बाहर चुप रहना ही नहीं है, भीतर भी चुप रहना है।
कुछ लोग बाहर नहीं बोलते मगर अपने भीतर बोलते रहते है।
हकीकत में भीतर अंत:करण बोलता है।
अंत:करण से होता है तादात्म्य इसलिए वे जैसा अंत:करण बोलता है वैसा स्वयं यंत्रवत बोलते, करते रहते है।
अत: एक साधक के रूप में अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी पडती है कि भीतर हम स्वयं मौन ही रहेंगे। कुछ भी नहीं बोलेंगे।
मनबुद्धि बोलेंगे मगर हम चुप ही रहेंगे।
साधन की तरह रखा गया मौन सत्य को जानने पर साध्य हो जाता है।
जो सर्वत्र एक सत्य का अनुभव कर लेता है वह मौन हो ही जाता है।
उसके बोलने का कारण नहीं रहता।
वह तभी होता है जब स्वयं रागद्वेष के वश में हो।
कोई हमारा प्रशंसक है तो हमारे भीतर कैसे राग पूर्ण विचार चलते है!
हम उनके साथ एक हो जाते है।
कोई हमारा निंदक है तो हमारे भीतर कैसे द्वेषपूर्ण विचार चलते है।
हम उनके साथ एक हो जाते है।
परंतु यदि हम रागद्वेष के वश में नहीं है तो भीतर रागद्वेष पूर्ण विचार तो चलेंगे मगर हम कुछ न करेंगे, कुछ न सोचेंगे-
न विरोध में, न समर्थन में।
एक साधक के रूप में यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भीतर कुछ भी नहीं सोचें, सर्वथा मौन रहें।
यह हमारा बडा साधन है।
'हमारे बारे में कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है'
ऐसे जो विचार आते है तब समझ लेना चाहिए कि यह मन ही बोल रहा है और हमें चुप रहना है, मन की हां में हां नहीं मिलानी है।
मन से तादात्म्य होता है इसलिए बाहर चुप रहना सरल है मगर भीतर चुप रहना कठिन है।
भीतर चुप रहना ही महत्वपूर्ण है।
बाहर किसी को रोकना मुश्किल है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही वह बोलता है मगर भीतर मन?
मन को भी नहीं रोका जा सकता मगर उसके प्रति विरोध, समर्थन से मुक्त रहा जा सकता है।
इसके लिए मन को, विचारों को देखने की जरूरत नहीं है।
उन्हें देखने से हम बिना जाने उसके प्रवाह में बहा लिए जा सकते है।
हमें तो स्वयं को देखना है-अपने आपको कि मैं मौन हूँ या नहीं?
मैं साधक हूँ या नहीं?
चुप साधन चुप साध्य है...
हम स्वयं अपने भीतर मौन रह सकें तो पायेंगे प्रज्ञा शक्ति जाग्रत होने लगी है।
कभी महापुरुषों को देखा हो, सुना हो, अनुभव किया हो।
वे बाहर जो भी बोलें मगर भीतर वे पूरी तरह से शांत होते है, मौन, खामोश, निस्तब्ध, निशब्द।
बोलने पर
उनके शब्द सीधे मूलस्रोत से आते है। बीच में कर्ता की तरह मन, बुद्धि, अहंकार नहीं होते।
भीतर सन्नाटा होता है।
वे कुछ भी नहीं सोच रहे होते।
मेरा आध्यात्मिक साथी भी भीतर पूरी तरह से खामोश था।
बाहर वह किसी को डांटता भी या प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलता मगर भीतर कुछ नहीं।
वह कहता-मेरे भीतर कुछ नहीं है।
लोग अनुमान लगाते यह ऐसा या वैसा सोचता होगा लेकिन मैं जानता था भीतर वह पूरी तरह से निशब्द था, मौन था।
और इसलिए उसके मुख से आध्यात्मिक सत्य की गहरी बातें सुनने को मिलती।
वह किसी भी विषय पर साधिकार, प्रामाणिक रुप से बोल सकता था, वह भी धाराप्रवाह
मगर भीतर अखंड मौन सधा हुआ।
यह थोड़ी न समझ में आने जैसी बात है।
कारण चुप रहने का न पता है, न अभ्यास है।
पता हो तो अभ्यास भी हो कि भीतर हम स्वयं कुछ भी नहीं सोचेंगे इांतरिक वार्तालाप शून्य होगा पूरी तरह से।
मन सोचेगा, अहंकार शिकायत करेगा, बुद्धि अपने पक्ष में समर्थन जुटायेगी लेकिन स्वयं मौन।
भीतर चुप रहना मुश्किल है।
बाहर तो कोई नाराज न हो इस कारण से चुप भी रह लेते है लोग मगर भीतर देखने वाला कौन है?
असली कसौटी तो भीतर है कि भीतर हम स्वयं पूरी तरह से मौन रहेंगे।
ऐसा साधक अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है।
उस पर बाहरी निंदा, प्रशंसा का असर नहीं होता।
न वह भीतर अपने रागद्वेष पूर्ण अंत:करण के झांसे में आता है।
बाहर यथायोग्य कर्म होते रहते है जैसे श्रीकृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते है मगर भीतर स्वस्थ रहने का संदेश देते है-
"स्वस्थ:"।
जो भीतर स्वस्थ है,वह भीतर मौन भी है।
लेकिन उसकी प्रज्ञा शक्ति जाग्रत होती है।
वह स्थितप्रज्ञ होता है जिसके लिए अर्जुन ने प्रश्न किया-
"स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।
स्थितधी:किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्।।"
यह जो भीतर चुप रहने की बात है यह दूसरों के भरोसे नहीं हो सकती।
थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है उससे जो उसके भीतर मौन है।
जब तक हमारे भीतर संस्कारबद्ध मनबुद्धि सक्रिय है, सतत कुछ बोल रहे है, कर रहे है तब तक हमें ही कोशिश करनी होगी।
हमें भीतर मौन रहना आगया तो बाहर की कोई फिक्र नही है।
बाहर सब तरह के लोग है।
जिसकी जैसी बुद्धि वह वैसा व्यवहार करेगा।
इसलिए सवाल उसका नहीं, सवाल हमारा है कि हम स्वयं अपने भीतर पूर्णतया स्वस्थ है या नहीं?
भीतर अंत:करण से तादात्म्य मिटने पर ही सही ढंग से कुछ हो सकता है। तब सभी विचार, दृश्य मूक पट, मूक चित्र की तरह होते है (साइलेंट फिल्म की तरह)।
कभी कभी कुछ मित्र बडे परेशान होते है।
उन्हें जानना चाहिये कि परेशान उनका मन होता है, वे स्वयं नहीं।
उन्हें तो मौन ही बने रहना चाहिए।
"मैं परेशान हूँ" ऐसा कहने वाले मन की हां में हां नहीं मिलानी चाहिए, न उसका विरोध करना चाहिए।
मन इच्छा, अनिच्छा का खेल लगातार खेलता रहता है।
हमें उस खेल को देखने की जरूरत नहीं है। हमें तो यह ध्यान रखना है कि हम स्वयं हमारे भीतर मौन रह पाते है या नहीं?
मौन ही हमारा सच्चा स्वरूप है।
"Silence is the Self."
"Silence is gold."
सबसे भली चुप।
मगर भीतर,
बाहर नहीं।
बाहर यथायोग्य संवाद किया जा सकता है।
इसलिए यह संदेश-
"भीतर संपूर्ण मौन,
(न मैं, न तुम, न यह,न वह)
बाहर यथायोग्य संवाद।"
मित्र कहता-"कभी सफाई नही देनी चाहिए।"
सफाई वही देता है जिसके भीतर शोरगुल है।

विश्व डाक दिवस: पत्र, पार्सल और पीढ़ियों के रिश्तों का

जब दुनिया की रफ्तार डिजिटल संदेशों, त्वरित सूचनाओं और स्क्रीन की चमक में उलझी हुई है, तब एक दिन ऐसा आता है जो हमें रुकने, ठहरने और उन पलों को याद करने का अवसर देता है, जब एक कागज का टुकड़ा, स्याही की कुछ बूंदें और किसी प्रियजन की लिखावट दिलों को जोड़ने का सबसे मजबूत जरिया बनती थी। 9 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस, केवल डाक सेवाओं का उत्सव नहीं है; यह उन अनकही कहानियों, भावनाओं और मानवता के उस अटूट बंधन का सम्मान है, जो समय और दूरी की सीमाओं को लांघकर हमें एक-दूसरे के करीब लाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संचार केवल शब्दों का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि दिलों का मिलन, आशा का संदेश और विश्वास का प्रतीक है। एक पत्र, जो किसी अनजान डाकिए के कंधों पर सवार होकर सुदूर गांवों, पहाड़ों या समुद्रों को पार करता है, वह केवल कागज नहीं, बल्कि एक कहानी, एक सपना और एक रिश्ता लेकर चलता है।

विश्व डाक दिवस की शुरुआत 9 अक्टूबर 1874 को हुई, जब स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यू.पी.यू.) की स्थापना हुई। इस संगठन ने विश्व भर की डाक प्रणालियों को एक सूत्र में बांधकर संचार को सरल और सुलभ बनाया। उस समय यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी। यह वैश्विक सहयोग का एक ऐसा प्रतीक था, जिसने देशों की भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरी को पाटकर एक वैश्विक डाक नेटवर्क की नींव रखी। आज यू.पी.यू. के 192 सदस्य देश इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो हर साल अरबों पत्रों और पार्सलों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। लेकिन इसकी कहानी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह उन असंख्य लोगों की कहानी है, जिनके लिए डाकघर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि आशा, अवसर और संवेदनाओं का केंद्र रहा है।

डाक सेवाओं का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का एक अनोखा दस्तावेज है। भारत में डाक व्यवस्था की जड़ें प्राचीन काल तक जाती हैं, जब राजा-महाराजा अपने संदेशवाहकों के जरिए पत्र भेजते थे। लेकिन आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत 1854 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई, जब भारत में पहली डाक टिकट जारी की गई। आज भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक प्रणालियों में से एक है, जिसमें 1.55 लाख डाकघर हैं, जिनमें से 89% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ये डाकघर उन लाखों लोगों के लिए संचार का एकमात्र साधन हैं, जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन अभी भी एक सपना हैं। भारतीय डाक ने न केवल पत्रों को पहुंचाया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के संदेशों को गुप्त रूप से प्रसारित करने, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डाक सेवाओं ने मानव इतिहास के सबसे कठिन दौर में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, डाक सेवाओं ने सैनिकों और उनके परिवारों को जोड़े रखा। एक सैनिक का पत्र, जो खाइयों में लिखा गया और मीलों की दूरी तय करके उसके परिवार तक पहुंचा, वह केवल शब्दों का संग्रह नहीं था। वह पत्र आशा, प्रेम और जीवित रहने की प्रेरणा का प्रतीक था। आज भी, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के समय, जब अन्य संचार साधन ठप हो जाते हैं, डाक सेवाएं निर्बाध रूप से काम करती हैं। 2020 की कोविड-19 महामारी के दौरान, भारतीय डाक ने दवाइयों, आवश्यक सामग्रियों और सरकारी सहायता को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया, जिसने लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा का काम किया।

विश्व डाक दिवस केवल अतीत की गौरव गाथा नहीं गाता, बल्कि डाक सेवाओं के बदलते स्वरूप को भी रेखांकित करता है। आज डाकघर केवल पत्र और पार्सल तक सीमित नहीं हैं। भारत में डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई.पी.पी.बी.) के जरिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बैंकिंग सुविधाएं दुर्लभ हैं, डाकघर बचत खाते, बीमा और डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, डाक सेवाएं ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी करके भारतीय डाक ने ग्रामीण और शहरी भारत को जोड़ा है, जिससे छोटे व्यवसायों और स्थानीय कारीगरों को वैश्विक बाजार तक पहुंचने का मौका मिला है।

डाक टिकटें भी विश्व डाक दिवस का एक अनूठा पहलू हैं। ये छोटे-छोटे कागज के टुकड़े केवल भुगतान का साधन नहीं हैं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और विज्ञान की कहानियां बयां करते हैं। भारत ने हाल के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण, अंतरिक्ष अनुसंधान, और स्वतंत्रता सेनानियों जैसे विषयों पर टिकटें जारी की हैं। ये टिकटें न केवल संग्रहकर्ताओं के लिए मूल्यवान हैं, बल्कि नई पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का एक माध्यम भी हैं। विश्व डाक दिवस पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियां और प्रतियोगिताएं बच्चों और युवाओं को डाक सेवाओं के महत्व से परिचित कराती हैं।

दूरदराज के क्षेत्रों में डाक सेवाओं की भूमिका और भी अनोखी है। अंटार्कटिक और आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में, जहां मानव जीवन की उपस्थिति सीमित है, डाक सेवाएं वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं तक आवश्यक सामग्री पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए, अंटार्कटिक में भारत के डाकघर, जो दुनिया के सबसे दुर्गम डाकघरों में से एक है, वहां कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए संचार का एकमात्र साधन है। यह दिखाता है कि डाक सेवाएं केवल सुविधा नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक आवश्यकता हैं।

विश्व डाक दिवस का सबसे गहरा संदेश भावनाओं और रिश्तों में छिपा है। एक हस्तलिखित पत्र, एक जन्मदिन कार्ड, या एक शादी का निमंत्रण—ये सभी छोटी-छोटी चीजें हमारे जीवन की सबसे कीमती यादें बन जाती हैं। डिजिटल संदेशों की दुनिया में, जहां संदेश सेकंडों में पहुंच जाते हैं, एक पत्र की प्रतीक्षा में जो मिठास और उत्साह है, वह आज भी बेजोड़ है। विश्व डाक दिवस हमें यह सिखाता है कि तकनीक भले ही हमें तेजी दे, लेकिन सच्चा संचार भावनाओं और धैर्य में बसता है।

9 अक्टूबर केवल एक तारीख नहीं है। यह एक ऐसा दिन है, जो हमें याद दिलाता है कि डाक सेवाएं केवल पत्र और पार्सल नहीं पहुंचातीं, बल्कि वे आशा, विश्वास और मानवता का संदेश भी पहुंचाती हैं। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, कुछ चीजें—जैसे एक प्रियजन का पत्र, डाकिए की घंटी, और डाकघर की वह पुरानी खुशबू—हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। विश्व डाक दिवस हमें यह एहसास दिलाता है कि संचार का असली जादू तकनीक में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में है, जो समय और दूरी को पार करके हमें एक-दूसरे के करीब लाती हैं।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी

पटाखों को लेकर परम्पराओं का सम्मान बना रहे और साथ ही प्रदूषण ना बढ़े इन दोनों का समन्वय बना रहे : वीरेन्द्र सचदेवा

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों से एक ऐसी सरकार थी जिसने हिंदुओं के त्योहारों को रोकने उनमें व्यवधान डालने और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की और आज जब भाजपा सरकार ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाने की बात कर रही है तो आम आदमी पार्टी को इसमें भी राजनीति नज़र आ रही है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि प्रमाणित ग्रीन पटाखों से ना तो दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ेगा और ना ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचेगी।

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और धार्मिक भावनाओं का सम्मान दोनों

का संतुलन बनाकर रखना जरूरी है। पिछली सरकार ने दिल्ली में ना सिर्फ़ पटाखों पर बैन लगाकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया बल्कि छठ जैसे महापर्व को नदी किनारे मनाने रोककर लाखों पूर्वांचलियों की आस्था का अपमान करने का काम किया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देने की मांग की है पर इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला देगा उसका भाजपा सरकार एवं दिल्ली की जनता सम्मान करेगी। परंपराओं का सम्मान करना और साथ ही प्रदूषण ना फैले यह दोनों भाजपा की प्राथमिकता है और हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य है कि दिल्लीवाले इस बार खुशियों से जगमगाती दीपावली, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण के साथ मनाए।

क्रॉम्पटन संपूर्ण ग्रीनप्रो सर्टि फाइड सॉल्यूशन रेंज के साथ पहली लाइटिंग कंपनी बनी

मुख्य संवाददाता

क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (CGCEL), भारत की अग्रणी उपभोक्ता विद्युत कंपनियों में से एक, ने सस्टेनेबिलिटी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी की पूरी बी2बी लाइटिंग प्रोडक्ट रेंज को ग्रीनप्रो समिट इंडिया 2025 में प्रतिष्ठित सीआईआई ग्रीनप्रो सर्टिफिकेशन (टाइप-1 इकोलेबल) से सम्मानित किया गया है। इससे क्रॉम्पटन पहली लाइटिंग कंपनी बन गई है जिसकी संपूर्ण सॉल्यूशन रेंज ग्रीनप्रो सर्टिफाइड है।

यह मान्यता ठीक एक साल बाद मिली है जब क्रॉम्पटन को उसके सीलिंग फैन के लिए पहला ग्रीनप्रो इकोलेबल सर्टिफिकेशन मिला था, जो कंपनी की उत्पाद श्रेणियों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

ग्रीनप्रो इकोलेबल सर्टिफिकेशन एक प्रतिष्ठित मान्यता है जो उत्पाद के पूरे जीवन चक्र में पर्यावरणीय प्रदर्शन को प्रमाणित करती है - कच्चे माल की खरीद और विनिर्माण प्रक्रियाओं से लेकर उपयोग के दौरान ऊर्जा दक्षता तक, और जीवन के अंत में जिम्मेदारी से निपटान या रिसाइक्लिंग करने तक। भारत में, यह सर्टिफिकेशन इंडियन इंडस्ट्री कन्फेडरेशन (सीआईआई) द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और ग्लोबल इकोलेबलिंग नेटवर्क (जीईएन) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह वैश्विक स्तर पर सामंजस्यपूर्ण इकोलेबलिंग मानकों को पूरा करता है।

अपनी प्रोफेशनल लाइटिंग रेंज के लिए यह सर्टिफिकेशन हासिल करके, क्रॉम्पटन भवन सामग्रियों, उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल सॉल्यूशंस प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

हम गलतियां क्यों करते हैं - इनसे कैसे बचें!

चंद्र मोहन

गलती हो गयी ₹ - ₹सोरी ₹. क्या इससे गलती सुधर जाती है ! या यह दूसरे के अहम का तुष्टिकरण है. अब सवाल उठता है कि हम अपने जीवन में कितनी गलतियां करते हैं ? क्या हम गलतियों को दोहराते नहीं या फिर से वैसी गलतियां दोबारा करते हैं. इनसे कैसे बचा जाये.

हम गलतियाँ इसलिए करते हैं क्योंकि भावनाएँ हावी हो जाती हैं. अति आत्मविश्वास, अनुभव की कमी, तनाव या ध्यान भटकने जैसे कारक हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं. हमारा मस्तिष्क भी अक्सर शॉर्टकट या ₹टेम्पलेट₹ का उपयोग करता है जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, जो हमें कुछ गलतियों को बार-बार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये गलतियाँ सीखना, अनुकूलन और अंततः बेहतर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं.

गुस्सा, डर, लालच या अहंकार जैसी भावनाएँ हमें सही निर्णय लेने से रोक सकती हैं. हमारा दिमाग जानकारी को संसाधित करने के लिए शॉर्टकट (ह्यूरिस्टिक्स) का उपयोग करता है, जो कभी-कभी गलतियों का कारण बनते हैं.

जब हम सोचते हैं कि हम पहले से सब जानते हैं, तो हम गलतियाँ कर सकते हैं.

बाहरी दबाव या प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं.

बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल हो सकता है और पर्याप्त अनुभव न होने के कारण हम गलतियाँ दोहरा सकते हैं.

हमारी अपनी धारणाएँ और पूर्वाग्रह हमें सही जानकारी को नजरअंदाज करने और गलतियाँ करने के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं.

निश्चित संख्या में गलतियों को नहीं गिना जा सकता है क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन और अनुभव अलग होता है, लेकिन सामान्यतः लोग अपने जीवन में कई गलतियां करते हैं, जैसे स्वास्थ्य की अनदेखी, खराब समय प्रबंधन, अवास्तविक इच्छाएँ, दूसरों से तुलना करना, और अपनी भावनाओं को दबाना. गलतियाँ सीखने और विकास के अवसर भी हैं, जिन्हें अनुभव और आत्म-जागरूकता से कम किया जा सकता है.

कुछ सामान्य गलतियाँ:

निरंतर सीखने की कमीः नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में रुचि न रखना.

खराब समय प्रबंधनः समय का सही उपयोग न करना और महत्वपूर्ण कार्यों को टालना.

स्वास्थ्य की अनदेखीः अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत पर ध्यान न देना.

वित्तीय अनुशासन की कमीः खर्चों का सही प्रबंधन न करना और निवेश को नजरअंदाज करना.

संवाद की कमीः रिश्तों में खुलकर बात न करना और गलतफहमियों को दूर न करना.

खुद से प्यार न करनाः आत्म-सम्मान की कमी और अपनी तुलना दूसरों से करना.

अधिक सोचनाः

बहुत अधिक सोचने के कारण अंदर से परेशान होना.

अवास्तविक इच्छाएं: अपनी सामर्थ्य से अधिक बड़ी-बड़ी इच्छाएँ पालना।

डर और अनिर्णयः असफलता के डर से निर्णय न लेना और नए अवसरों को खो देना.

जिम्मेदारी से भागनाः अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डालना.

एक शोध के अनुसार इंसान हर घंटे तीन से छह गलतियाँ करते हैं, चाहे कोई भी गतिविधि हो या काम, और औसतन, एक दिन में 500 गलतियाँ करते हैं.

ज्ञानात्मक गलती - यह गलती तब होती है जब हमें किसी विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है या हमें गलत जानकारी मिलती है.

व्यावहारिक गलती - यह गलती तब होती है जब हम किसी कार्य को करने में असफल होते हैं या हमें किसी कार्य को करने का तरीका नहीं पता होता है.

एक इंसान दिन भर में औसतन 30 से 50 गलतियाँ करता है, और यह संख्या गतिविधि या व्यक्ति के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है. हम जानबूझकर या अनजाने में गलतियाँ करते हैं क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण हैं, तनाव में होते हैं, या कभी-कभी सीखते हैं. गलतियों का होना सामान्य है, और इनसे सीखना और आगे बढ़ना ही महत्वपूर्ण है.

गलतियों का औसतन समयः

प्रति घंटाः आप औसतन 3 से 6 गलतियाँ कर सकते हैं.

प्रतिदिनः हर दिन लगभग 30 से 50 गलतियाँ हो सकती हैं.

हम गलतियाँ क्यों करते हैं?

शारीरिक और मानसिक स्थितियाँः हम अपनी जैविक, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के कारण स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण हैं.

भावनात्मक और बाहरी प्रभावः तनाव, दबाव, या ध्यान भटकने जैसी चीजें भी खराब प्रदर्शन का कारण बन सकती हैं.

अनजाने में: हम कई गलतियाँ अनजाने में करते हैं, जैसे कोई काम करना भूल जाना.

गलतियां आमतौर पर ₹भूलवश₹ होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे जानबूझकर नहीं की जातीं, बल्कि किसी असावधानी, अज्ञानता, या मानवीय स्वभाव के कारण होती हैं. हालांकि, यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को बार-बार दोहराता है, तो वह ₹स्वभाविकर₹ बन सकती है, या फिर जानबूझकर गलत काम करना ₹गलत₹ कहलाता है, जो नियत से जुड़ा होता है.

भूलवश गलतियाँ अक्सर गलत धारणा या असावधानी के कारण होती हैं, और इनमें मूर्खता या अज्ञानता का पुट हो सकता है.

उदाहरणः किसी काम को करते समय गलती से गलत बटन दबा देना, किसी चीज़ की सही मात्रा न जानना, या किसी को गलत नाम से पुकार देना.

ऐसी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में उन्हें दोबारा न दोहराया जाए.

स्वाभाविक गलतियाँ -

यह शब्द उन गलतियों को भी संदर्भित कर सकता है जो मानवीय स्वभाव का हिस्सा हैं, जैसे कि हर कोई गलतियाँ करता है.

जब आप अपनी किसी गलती से कोई सबक नहीं सीखते, तो वह गलती बार-बार दोहराई जा सकती है और एक तरह से स्वाभाविक आदत बन सकती है.

जानबूझकर की गई गलतियाँ -

"गलत" या ₹गलत नीयत₹ से किया गया कार्य जानबूझकर किया जाता है. यह भूलवश नहीं होता, बल्कि गलत इरादों के कारण होता है.

यह गलती एक इरादे या नीयत का परिणाम होती है, और यह किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से की जाती है.

गलतियां सबसे होती हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से परिपूर्ण नहीं होता. गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं और इनसे हमें अनुभव मिलता है. अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही आगे बढ़ने और बेहतर बनने का सबसे सही तरीका है.

गलतियाँ क्यों होती हैं?

गलतियाँ होने के कई कारण हो सकते हैंः

भावनात्मक प्रभावः गुस्सा, डर, लालच या अहंकार में गलत फैसले लेना.

आदतेंः पुरानी गलत आदतों को छोड़ पाना मुश्किल होता है.

अति आत्मविश्वासः खुद को बहुत ज़्यादा जानकार समझना और गलत निर्णय लेना.

लापरवाही या टालमटोलः सही काम न करना और बाद में पछतावा होना।

दबाव या परिस्थितियाँः सामाजिक दबाव या मजबूरी में गलत चुनाव करना.

अनुभव की कमीः ज्ञान को सही समय पर लागू न कर पाना.

गलतियों से कैसे सीखें?

स्वीकार करेंः अपनी गलती स्वीकार करना पहला कदम है.

पहचानेंः गलती के कारण को समझें और उससे सीखें.

बार-बार दोहराएँ नहींः गलती से सीख लें ताकि उसे दोबारा न दोहराएँ.

सुधार करेंः अपनी गलतियों में सुधार करने का प्रयास करें.

खुद को माफ़ करेंः हर बार गलती पर पछताने से अच्छा है कि आप खुद को माफ़ करके आगे बढ़ें.

संक्षेप में, गलतियाँ जीवन का हिस्सा हैं, इनसे डरने की बजाय उनसे सीखना ही बुद्धिमानी है.

पंचायती राज मंत्री से पंच बन गांव की सेवा करने वाले नेता का जाना

अमरपाल सिंह वर्मा

राजस्थान की राजनीति में भरत सिंह कुंदनपुर का नाम उस पीढ़ी के नेताओं में लिया जाएगा जिन्होंने सत्ता को साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना। राज्य के पंचायती राज मंत्री रहते हुए उन्होंने ग्रामीण विकास की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया, पंचायतों को नवाचार के लिए प्रेरित किया लेकिन उनके व्यक्तित्व की असली झलक तब दिखी जब इस पंचायती राज मंत्री रहे नेता ने अपने गांव लौटकर पंच का चुनाव लड़ा और जीत कर गांव के विकास में योगदान देने लगे।

भरत सिंह ने राजनीति की शुरुआत सरपंच बनकर की थी। वह अपने गांव में तीन बार सरपंच चुने गए। इसके बाद पंचायत समिति प्रधान बने। चार बार विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री रहने के बाद वर्ष 2014 में उन्होंने पंचायत चुनाव में पंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया तो राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति राज्य स्तरीय नीतियां बनाता था, वह अब गांव की चौपाल में बैठने जा रहा है लेकिन भरत सिंह ने मुस्कराते हुए कहा था कि मंत्री रहते हुए जो काम न करा सका, वे काम अब बतौर पंच कराऊंगा। उनका यह बयान सिर्फ विनम्रता नहीं, लोकतंत्र की असली भावना का प्रतीक था। भरत सिंह ने यह दिखाया कि राजनीति का असली उद्देश्य पद पाना नहीं बल्कि समाज को दिशा देना है। जब उन्होंने पुनः पंच बनने का फैसला किया तो कई लोगों ने इसे 'पद का पतन' कहा लेकिन उन्होंने इसे सेवा का अवसर माना। वे कहा करते थे कि जो काम ऊपर से नहीं हो सके, वे नीचे से जरूर हो सकते हैं। यही उनके राजनीतिक दर्शन की सबसे बड़ी सीख थी।

75 साल की उम्र में बीती रात को कांग्रेस के इस बड़े नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया मगर वह न केवल मतदाताओं के दिलों में रहेंगे बल्कि ईमानदारी और सादगी से राजनीति करने के इच्छुक लोगों को भी प्रेरणा देते रहेंगे। उनका समूचा जीवन कुछ ऐसा ही था। उन्होंने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा। सदैव भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। वह अपनी ही पार्टी की सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से नहीं चूके। विभिन्न मुद्दों पर अपनी सरकार विरोध में उन्होंने सिर मुंडवा लिया था। हमेशा जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की बात करते रहे। उन्होंने जीवन भर पंचायती राज के सशक्तीकरण की वकालत की। विधानसभा में हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाते रहे। इसी वजह से उन्हें वर्ष 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला। उनकी ईमानदारी को विपक्ष के नेता भी स्वीकार करते थे।

एक ओर जहां नेता कुर्सी से चिपके रहते हैं, वहीं दूसरी ओर भरत सिंह ने 2018-23 के दौरान विधायक रहते हुए आगामी चुनाव नहीं लडने की घोषणा कर राज्य की राजनीति में एक नई परंपरा स्थापित की। उनका यह निर्णय सत्ता के मोह से मुक्ति का प्रतीक था। आज के दौर में जहां नेता ऊंचे पदों की चाह में जनता से दूर होते जा रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने जीवन का संध्या काल गांव की गलियों में बिताने का निश्चय किया। उनका मानना था कि असली राजनीति पंचायत से शुरू होती है क्योंकि यहीं से जनता के जीवन में बदलाव आता है। जब वह मंत्री रहने के बाद पंच बने तो उन्होंने कहा था कि पंच बनना सिरफिरेपन जैसा है पर अगर गांव का भला करना है तो थोड़ा सिरफिरा होना ही पड़ेगा। यह कथन उनकी निडर सोच को दर्शाता है।

भरत सिंह की पत्नी गांव की सरपंच थीं। दोनों ने मिलकर पंचायत चलाने की अनूठी मिसाल पेश की। उनका कहना था कि विधानसभा में काम बोलने का होता है लेकिन गांव में काम सुनने का। उनकी मान्यता थी कि योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका असर जमीनी स्तर तक पहुंचे। यही कारण था कि वह पंच बनकर वे उन्हीं नीतियों को जमीन पर उतारने में जुट गए जिनका कभी मसौदा उन्होंने मंत्री रहते हुए तैयार किया था।

मोहमदी में अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन व सम्मान समारोह सम्पन्न

21 विभूतियां को मिला 'गोमती' और 'केतकी साहित्य रत्न अवार्ड 2025'

डॉ.शंभू पंवार

नई दिल्ली। देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था कथाकुंज साहित्य सेवा परिषद के तत्वावधान में ऐतिहासिक नगरी मोहमदी की पावन धरती पर अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन एवं सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन प्रोफेसर सुदीप कुमार की पावन स्मृति में समर्पित किया गया। यह समारोह साहित्य, संस्कृति और काव्य-सृजन की एक अविस्मरणीय संध्या बन गया।

समारोह के अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज, एवं नगर पालिका परिषद मोहम्मदी के चेयरमैन संदीप मेहरोत्रा ने 21 साहित्यिक विभूतियों को गोमती व केतकी साहित्य रत्न अवॉर्ड 2025 से अलंकृत किया। कार्यक्रम में देश-विदेश से चयनित कवि और कवयित्रियाँ अपनी ओजस्वी एवं भावपूर्ण रचनाओं से श्रोताओं को देर रात तक काव्य रस में डुबोते रहे। संस्था के संस्थापक गोविंद गुप्ता एवं उनकी सशक्त टीम ने आयोजन को भव्यता और अनुशासन का अद्भुत संगम बना दिया। कार्यक्रम में ब्रांड एंबेसडर डॉ. नीमा पंत की सृजनात्मक उपस्थिति और मार्गदर्शन ने वातावरण को और अधिक गरिमामय बनाया। पटना से पधारी प्रसिद्ध आरजे और ऊर्जावान मंच संचालिका श्वेता सुरभि ने अपने हाजिरजवाबी भरे फिल्मी अंदाज़ में मंच का संचालन कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कवयित्री मंजू श्रीवास्तव (अमेरिका), इति शिवहरे, राधा गुप्ता, डॉ. प्रीतम कुमार झा, पी.के. सिंह, विकास मिश्र 'सागर', रानी गुप्ता, रीमा सिन्हा, रंजना डोगरा, संध्या त्रिपाठी, सारिका सरल, मीनू वर्मा, मणि अग्रवाल, आकृति विज्ञा, अर्पण रानी, सुरभि सिंह सहित अनेक कवियों ने काव्यपाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम से पूर्व अतिथि कवियों एवं कवयित्रियों को मोहमदी नगर का भ्रमण कराया गया, जहाँ उन्होंने इस पौराणिक नगरी

की सांस्कृतिक विरासत का सजीव अनुभव किया। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में श्यामू गुप्ता, प्रशांत मिश्र, अखिलेश गुप्ता, हरेंद्र वर्मा, सचिन गुप्ता, रजनी सैनी, शिवम राठौर, राममोहन रस्तोगी, चरनजीत सिंह, मेराज खाँ, रामजी गुप्ता सहित अनेक सहयोगियों का उल्लेखनीय योगदान रहा। यह सम्मेलन अनुशासन, सकारात्मकता और काव्य-गरिमा की मिसाल बनकर साहित्यिक जगत में लंबे समय तक याद किया जाएगा।

नक़ली टाटा बनाने व बेचने वालों पर पुलिस की छापे मारी

मुख्य संवाददाता

DIU नॉर्थ पुलिस ने प्रोटेक्ट आई पी कंपनी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए नकली टाटा मोटर्स के पार्ट्स बेचने व बनाने वालो पर पुलिस की छापेमारी करते हुए कार्यवाही करते हुए मुक़दमा दर्ज किया। टाटा मोटर्स द्वारा अधिकृत प्रोटेक्ट आई.पी.कंपनी के जाँच अधिकारी ने शिकायत दर्ज करायी थी कि कुछ लोग कश्मीरिगेट एरिया में टाटा मोटर्स व अन्य ब्रांडेड कंपनियों का नकली समान बना व बेच रहे है । जिस पर पुलिस ने रेड डाल कर भारी काफी मात्रा में टाटा मोटर्स के नकली प्रोडक्ट, टाटा प्रिंटेड डब्बे व टाटा प्रिंटेड स्टिकर जब्त कर आरोपी दीपक बंसल पर केस दर्ज किया गया।

समय के साथ बदल रहा है डाक विभाग

रमेश सर्राफ धमोरा

पूरी दुनिया में 9 अक्तूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1874 में इसी दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन करने के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 1969 में जापान के टाकियो शहर में आयोजित सम्मेलन में विश्व डाक दिवस के रूप में इसी दिन को चयन किये जाने की घोषणा की गयी थी। एक जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला भारत पहला एशियाई देश था। जनसंख्या और अंतरराष्ट्रीय मेल ट्रैफिक के आधार पर भारत शुरू से ही प्रथम श्रेणी का सदस्य रहा है।

भारत में डाकघर का इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से शुरू होता है जब रॉबर्ट क्लाइव ने 1766 में पहली डाक व्यवस्था स्थापित की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कोलकाता में पहला डाकघर खोला और 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक राष्ट्रीय डाक सेवा की शुरुआत की। आज भारतीय डाक दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क में से एक है जो बैंकिंग, बीमा और अन्य सेवाओं के साथ आम आदमी का भरोसेमंद साथी है। 1 अक्टूबर 1854 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना के साथ ही भारत में पहली बार डाक टिकट भी जारी किया गया था।

विश्व डाक दिवस का मकसद देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक क्षेत्र के योगदान के बारे में जागरुकता पैदा करना है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 150 से ज्यादा देशों में विविध तरीकों से विश्व डाक दिवस आयोजित किया जाता है। भारतीय डाक प्रणाली का जो उन्नत और परिष्कृत स्वरूप आज हमारे सामने है। वह लंबे सफर की देन है। अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल पहले अलग-अलग हिस्सों में अपने तरीके से चल रही डाक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोने की पहल की थी। उन्होने भारतीय डाक को एक नया रूप और रंग दिया। पर अंग्रेजों की डाक प्रणाली उनके सामरिक और व्यापारिक हितों पर ही केंद्रित थी।

हमारे देश में पहले डाक विभाग का इतना अधिक महत्व था कि फिल्मों तक में डाकिये पर कई मशहूर गाने फिल्माये गये हैं। मगर अब नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव ने डाक विभाग के महत्व को बहुत कम कर दिया है। आज लोगों ने हाथों से चिट्ठियां लिखना छोड़ दिया है। अब ई-मेल, वाट्सएप व सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यमों से मिनटो में लोगो में संदेशों का आदान प्रदान हो जाता है।

आज डाक में लोगों की चिट्ठियां तो गिनती की ही आती है। मनीआर्डर भी बन्द से ही हो गये हैं। मगर डाक से अन्य सरकारी विभागों से सम्बन्धित कागजात, बैंको व अन्य संस्थानो के प्रपत्र काफी संख्या में आने से डाक विभाग का महत्व फिर से एक बार बढ़ गया है। डाक विभाग कई दशकों तक देश के अंदर ही नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश तक सूचना पहुंचाने का सर्वाधिक विश्वसनीय, सुगम और सस्ता साधन रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में निजी कम्पनियों के बढ़ते दबदबे और फिर सूचना तकनीक के नये माध्यमों के प्रसार के कारण डाक विभाग की भूमिका लगातार कम होती गयी है। वैसे इसकी प्रासंगिकता पूरी दुनिया में आज भी बरकरार है।

भारत में डाक विभाग के महत्व को मशहूर शायर निदा फाजली के शेर सीधा-साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान से समझा जा सकता है। शायर निदा फाजली ने जब यह शेर लिखा था उस वक्त देश में संदेश पहुंचाने का डाक विभाग ही एकमात्र साधन था। डाकिये के थैले में से निकलने वाली चिट्ठी पढ़कर कोई खुश होता था तो कोई दुखी।

कुछ वर्ष पूर्व तक डाक विभाग हमारे जनजीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। गांव में जब डाकिया आता था तो बच्चे-बूढ़े सभी उसके साथ डाक घर की तरफ इस उत्सुकता से चल पड़ते थे कि उनके भी किसी परिजन की चिट्ठी आयेगी। डाकिया जब नाम लेकर एक-एक चिट्ठी बांटना शुरू करता तो सभी लोग अपनी या अपने पड़ौसी की चिट्ठी ले लेते व उसके घर जाकर उस चिट्ठी को बड़े चाव से देते थे। उस वक्त शिक्षा का प्रसार ना होने से अक्सर महिलायें अनपढ़ होती थी। इसलिये चिट्ठी लाने वालो से ही चिट्ठियां पढ़वाती भी थी और लिखवाती भी थी। कई बार चिट्ठी पढने-लिखने वाले बच्चों को ईनाम स्वरूप कुछ पैसा या खाने को गुड़, पताशे भी मिल जाया करते थे। इसी लालच में बच्चे ज्यादा से ज्यादा घरों में चिट्ठियां पहुंचाने का प्रयास करते थे।

उस वक्त गांवो में बैक शाखा भी नहीं होती थी। इस कारण बाहर कमाने गये लोग अपने घर पैसा भी डाक में मनीआर्डर के द्वारा ही भेजते थे। मनीआर्डर देने डाकिया स्वयं प्राप्तकर्ता के घर जाता था व भुगतान के वक्त एक गवाह के भी हस्ताक्षर करवाता था। डाक विभाग अति आवश्यक संदेश को तार के माध्यम से भेजता था। तार की दर अधिक होने से उसमें संक्षिप्त व जरूरी बाते ही लिखी जाती थी। तार भी साधारण जरूरी होते थे। जरूरी तार की दर सामान्य से दुगुनी होती थी। देश में पहली बार 11 फरवरी 1855 को शुरू हुई तार सेवा को सरकार ने 15 जुलाई 2013 से बन्द कर दिया है। इसके साथ ही डाक विभाग ने रजिस्टर्ड डाक सेवा को भी एक अक्तूबर 2025 से स्पीड पोस्ट में विलय कर दिया है।

भारतीय डाक विभाग पिनकोड नम्बर (पोस्टल इंडेक्स नम्बर) के आधार पर देश में डाक वितरण का कार्य करता है। पिनकोड नम्बर का प्रारम्भ 15 अगस्त 1972 को किया गया था। इसके अन्तर्गत डाक विभाग द्वारा देश को नो भौगोलिक क्षेत्रो में बांटा गया है। संख्या 1 से 8 तक भौगोलिक क्षेत्र हैं व संख्या 9 सेना की डाक सेवा को आवंटित किया गया है। पिन कोड की पहली संख्या क्षेत्र दूसरी संख्या उपक्षेत्र, तीसरी संख्या जिले को दर्शाती है। अन्तिम तीन संख्या उस जिले के विशिष्ट डाकघर को दर्शाती है।

डाक विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) शुरू किया है। देश के हर व्यक्ति के पास बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के क्रम में यह एक बड़ा विकल्प होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश भर में बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इस के माध्यम से देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क अस्तित्व में आएगा। जिसकी हर गांव तक मौजूदगी होगी। इन सेवाओं के लिए पोस्ट विभाग के 11000 कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों को बैंकिंग सेवाएं देंगे।

बदलते हुए तकनीकी दौर में दुनिया भर की डाक व्यवस्थाओं ने मौजूदा सेवाओं में सुधार करते हुए खुद को नयी तकनीकी सेवाओं के साथ जोड़ा है। डाक, पार्सल, पत्रों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस सेवाएं शुरू की हैं। डाक घरों द्वारा मुहैया करायी जानेवाली वित्तीय सेवाओं को भी आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। दुनियाभर में इस समय 55 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार की पोस्टल ई-सेवाएं उपलब्ध हैं। भविष्य में पोस्टल ई-सेवाओं की संख्या और अधिक बढ़ायी जायेगी। डाक विभाग से 82 फीसदी वैश्विक आबादी को होम डिलीवरी का फायदा मिलता है।

भारत की आजादी के बाद हमारी डाक प्रणाली को आम आदमी की जरूरतों को केंद्र में रख कर विकसित करने का नया दौर शुरू हुआ था। नियोजित विकास प्रक्रिया ने ही भारतीय डाक को दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन डाक प्रणाली बनाया है। राष्ट्र निर्माण में भी डाक विभाग ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। जिससे इसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है। आज भी आम आदमी डाकघरों और डाकिये पर भरोसा करता है। तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद देश में आम जनता का इतना जन विश्वास कोई और संस्था नहीं अर्जित कर सकी है। यह स्थिति कुछ सालों में नहीं बनी है। इसके पीछे डाक विभाग के कार्मिको का बरसों का श्रम और लगातार प्रदान की जा रही सेवा छिपी है।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

पलवल के किसान बिजली वितरण निगम के लालफीताशाही से परेशान

परिवहन विशेष न्यूज

दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के पलवल सब-डिवीजन के पारौली गांव के लाइन मैन योगेश के द्वारा नियमित बिजली आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं से सरेआम रिश्वत के मांग किया जाता है यदि किसी ने रिश्वत नहीं दिया तो उसको बेवजह परेशान किया जाता है पारौली गांव में गौशाला चलाने वाले बिजली विभाग के लाइमैन योगेश से तंग आ चुके दुलीचंद लोहिया ने बताया यौगेश दस हजार रूपए मासिक मांग करता था नहीं देने पर उसने बिजली कटौती से लेकर अनाप शनाप बिल भेजकर मुझे परेशान करना शुरू किया जब मैं बिजली वितरण निगम पलवल सब-डिवीजन के एस डी ओ,एई जेइ और एकसीयन तक इसका शिक़ायत किया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तब हरियाणा के राजपाल, मुख्यमंत्री, विधुत मंत्री, मुख्य सचिव मुख्य अभियंता को अनेकों पत्र स्पीड पोस्ट,इमेल और ग्रिवेंनश के द्वारा शिकायत किया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है भुक्तभोगी दुलीचंद लोहिया ने बताया बीसन बार पलवल में अधिकारीयों से मिला लेकिन मेरे समस्या के समाधान के बजाय मुझे बिजली वितरण निगम के अधिकारीयों के द्वारा परेशान किया जा जा रहा है एक तरफ मुख्यमंत्री नयाव सिंह सैनी किसानों और गौशाला चलाने वाले को सुविधा देने के घोषणा करते हैं दूसरे तरफ बिजली वितरण निगम पलवल सब-डिवीजन

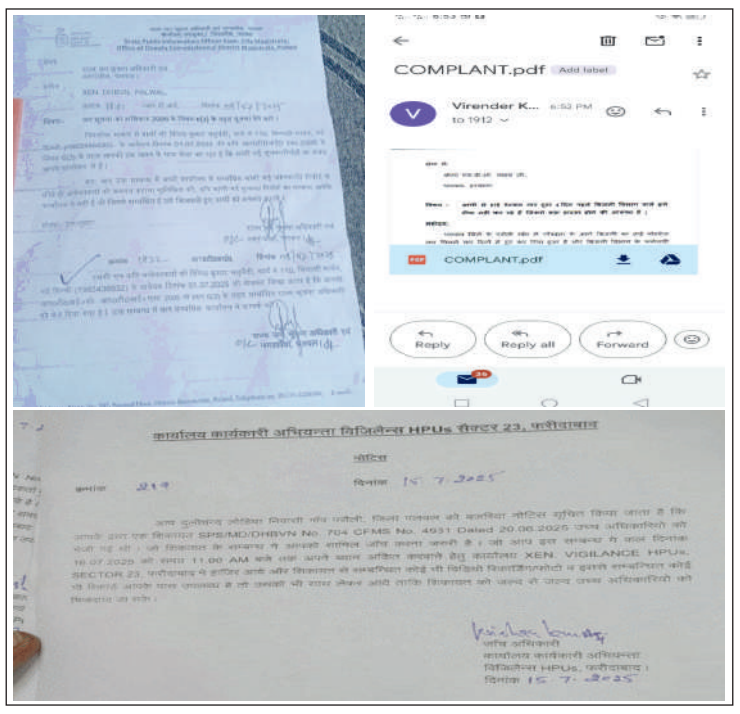

के अधिकारी अपने भ्रष्ट लाइन मैन योगेश के उपर कारवाई करने के बजाय बचा रहे हैं इस से पारौली गांव के आलावा अगल बगल के गांवों में बिजली वितरण निगम के विरुद्ध लोगों में गुस्सा है , लोहिया ने बताया हरियाणा सरकार का 8 घंटे किसानों को रोज बिजली देने के आदेश है उसके बावजूद किसानों के बिजली खेती जंगल वाली लाइट के आपूर्ति नहीं कर रहा है बिजली वितरण निगम

रिपोर्ट अंकित गुप्ता कासगंज

एटा - जलेसर तहसील के कृभको खाद केंद्र सालवाहनपुर पर एसडीएम भावना विमल ने संभाली व्यवस्था,
किसानों को डीएपी खाद की किल्लत से राहत दिलाने के लिए बुधवार को प्रशासन ने खुद संभाला मोर्चा,
किसानों की भीड़ बढ़ने और व्यवस्था बिगड़ने की सूचना पर एसडीएम भावना विमल तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचीं,
SDM ने स्थिति का जायज़ा लिया और स्वयं किसानों को पंक्तिबद्ध कर वितरण की व्यवस्था कराई,
एसडीएम के निर्देशन में खाद वितरण कार्य शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ,
किसानों को क्रमवार टोकन देकर खाद दी गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या मारामारी की स्थिति न बने-SDM

केंद्र संचालक को निर्देश दिए कि किसी भी किसान को परेशान न किया जाए-SDM भावना विमल
प्रतिदिन की सप्लाई का रिकॉर्ड पारदर्शिता के साथ रखा जाए-SDM भावना विमल
किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी-SDM

आमोद कुमार के मुक्तक संग्रह आँसू की कीमत केवल आँसू है लोकार्पित

डॉ.शंभू पंवार

नई दिल्ली। प्रगतिशील हिंदी साहित्य मंच के तत्वावधान में सरस्वती विहार स्थित कम्युनिटी सेंटर में एक गरिमामय साहित्यिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कवि श्री आमोद कुमार के मुक्तक संग्रह "आँसू की कीमत केवल आँसू है" का लोकार्पण समारोह अत्यंत भव्यता और आत्मीयता के साथ सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ओम सपरा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. महावीर सरन जैन (बुलन्दशहर) तथा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. सविता चड्ढा उपस्थित रहीं।

संचालन का दायित्व संयोजक अर्पन अग्रवाल ने अपनी सहज, रोचक और प्रभावशाली शैली में निभाया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. महावीर सरन जैन ने अपने उद्बोधन में कहा आमोद कुमार का यह मुक्तक संग्रह संवेदना की गहराइयों में उतरने का आमंत्रण है। इसमें जीवन के अनुभवों, पीड़ा और करुणा के अनेक आयाम दृष्टिगत होते हैं। अध्यक्ष ओम सपरा ने कहा आज के समय में जहाँ संवेदनाएँ क्षीण होती जा रही हैं, वहाँ 'आँसू की कीमत केवल आँसू है' जैसी कृतियाँ हमें मानवता के मूल भाव से जोड़ती हैं।अति विशिष्ट अतिथि डॉ. सविता चड्ढा ने कहा आमोद कुमार की रचनाएँ शब्दों का नहीं, हृदय का सौंदर्य हैं—इनमें सच्ची भावनाएँ और जीवन की संवेदनाएँ झलकती हैं।अंत में कवि आमोद कुमार ने अपने मुक्तक संग्रह से कुछ चुनिंदा रचनाओं का पाठ कर श्रोताओं की भरपूर प्रशंसा प्राप्त की।लोकार्पण के पश्चात कवि गोष्ठी में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से पधारे अनेक प्रसिद्ध कवि - कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साहित्यप्रेमियों की उपस्थिति में सम्पन्न यह आयोजन केवल एक पुस्तक विमोचन नहीं, बल्कि कविता, संवेदना और अभिव्यक्ति का उत्सव सिद्ध हुआ

सौभाग्यवती भवः 2025 प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन

सुनील चिंचोलकर

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शहर के प्रतिष्ठित होटल टोपाज में नवप्रभात सेवा समिति द्वारा "सौभाग्यवती भवः 2025 – प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन" का तीसरा वार्षिक आयोजन बड़े ही धूमधाम से हुआ। महिलाओं के व्यस्त जीवन एवं त्यौहार की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन करवा चौथ से पूर्व आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कविता सोनी ने की, जबकि राकेश सोनी, डॉ. पूनम सिंह, मृदुला साहू, जोतना मिश्रा, गौरी कश्यप एवं चंचल सलूजा ने आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि के रूप में शहर की पहली महिला महापौर पूजा विधानी एवं भाजपा प्रदेश सचिव हर्षिता पांडे उपस्थित रहीं।

निर्णायक मंडल में कृति बुटीक संचालिका भारती सालुंके (बिलासपुर), अंकिता कुमारी (रायगढ़), डॉ. चांदनी गुप्ता (क्वीन ऑफ छत्तीसगढ़ 2023) एवं तानी शिवहरे (सौभाग्यवती भवः 2024 सेकंड रनरअप) शामिल थीं।

कार्यक्रम में सर्व समाज की लगभग 70 महिलाओं ने 16 श्रृंगार, परिचय एवं प्रतिभा प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सौभाग्यवती भवः 2025 का ताज सरबजीत कौर ने जीता, जबकि रिया अग्रवाल द्वितीय एवं रश्मि गुप्ता तृतीय स्थान पर रहीं।

नृत्य प्रतियोगिता में स्वाती सोनी प्रथम, रिचा केसरवानी द्वितीय और मयूराक्षी तृतीय रहीं।

गायन प्रतियोगिता में चैताली साहू ने प्रथम, प्रीति गुप्ता ने द्वितीय एवं रिया अग्रवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में आकर्षक स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए दीपक, हस्तकला वस्तुएँ और आत्मनिर्भर महिलाओं के उत्पाद प्रदर्शित हुए। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच यह आयोजन महिला सशक्तिकरण और परंपरा का अद्भुत संगम बन गया।

रिपोर्ट अंकित गुप्ता कासगंज

एटा-बाइक बचाने के चलते सीएनजी टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा
नगरिया मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर सीएनजी खाली कर वापस जाते समय हुआ हादसा।
जीटी रोड पर सीएनजी टैंकर पलटने से आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी।
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची।
मलावन थाना क्षेत्र के कंगरोल गांव के पास हुआ हादसा UP Police Etah Police

बिहार राज्य विधानसभा चुनाव 2025 -आचारसंहिता प्रशासनिक शक्ति और लोकतांत्रिक शुचिता का इम्तिहान

चुनावी आचार संहिता भारतीय लोकतंत्र की वह नैतिक मर्यादा है,जो राजनीतिक दलों,नेताओं और सरकार को सत्ता के दुरुपयोग से रोकती है- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत एक ऐसा देश है, जहां लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सामाजिक आस्था है। हर चुनाव इस आस्था की परीक्षा भी होता है और लोकतंत्र की आत्मा की पुनर्पुष्टि भी। वर्ष 2025 के राज्य बिहार विधानसभा चुनाव सहित कुछ राज्यों की विधानसभाओं का उपचुनाव इस दृष्टि से बेहद अहम माने जा रहे हैं। आगामी 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में बिहार में मतदान होने जा रहा है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा करते ही आचार संहिता लागू कर दी है, और इसके साथ ही पूरा प्रशासन सक्रिय मोड में आ गया है। इस चुनावी परिदृश्य में भारत न केवल अपने भीतर लोकतांत्रिक शुचिता की परीक्षा दे रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों की प्रक्रिया कैसे सुदृढ़ होती है।साथियों बात अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की करें तो,प्रथम चरण में कुल सीटः121 नोटिफिकेशन की तारीखः10 अक्टूबर 2025 नामांकन की आखिरी तारीखः 17अक्टूबर 2025 नामांकन जांच की आखिरी तारीखः18 अक्टूबर 2025 नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीखः20 अक्टूबर 2025 मतदानः6 नवंबर 2025 चुनाव रिजल्टः14 नवंबर 2025 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 फेज- 2 शेड्यूलकुल सीटः122 नोटिफिकेशन की तारीखः13 अक्टूबर 2025 नामांकन की आखिरी तारीखः20 अक्टूबर 2025 नामांकन जांच की आखिरी तारीखः21 अक्टूबर 2025 नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीखः23 अक्टूबर 2025 मतदानः11 नवंबर 2025 चुनाव रिजल्टः14 नवंबर 2025

साथियों बात अगर हम चुनाव आचार संहिता क़े अर्थ और महत्व की करें तो,चुनावी आचार संहिता भारतीय लोकतंत्र की वह नैतिक मर्यादा है, जो राजनीतिक दलों, नेताओं और सरकार को सत्ता के दुरुपयोग से रोकती है। इसे चुनाव आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत लागू किया जाता है।इसका मूल उद्देश्य है कि सत्तारूढ़ दल चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी संसाधनों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग न करे,तथा विपक्षी दलों को समान अवसर मिले। यह संहिता न केवल प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करती है बल्कि जनविश्वास को भी बनाए रखती है। लोकतंत्र में यह "आचार" ही वह संतुलन है जो"सत्ता" को "सेवा"में परिवर्तित करता है।2025 के विधानसभा चुनावों में यह आचार संहिता पहले से अधिक सख्ती से लागू की गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई मंत्री या जनप्रतिनिधि सरकारी गाड़ी, बंगला, हेलीकॉप्टर या कोई भी सरकारी संसाधन चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।सरकारी वेबसाइटों से नेताओं की तस्वीरें हटाई जा रही हैं, नई योजनाओं की घोषणाओं पर रोक लगा दी गई है और सरकारी धन का किसी भी प्रकार से राजनीतिक प्रचार में उपयोग वर्जित कर दिया गया है। यह व्यवस्था प्रशासनिक निष्पक्षता की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

साथियों बात अगर हम प्रशासनिक सक्रियता और अनुशासन की परीक्षाकी करें तो,आचार संहिता लागू होते ही राज्य का प्रशासन भी युद्धस्तर पर सक्रिय हो गया है।जिलाधिकारियों से लेकर थानेदार तक को यह हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की राजनीतिक पक्षधरता न दिखे। पुलिस, आयकर विभाग, और निर्वाचन विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं ताकि अवैध धन, शराब, उपहार या अन्य प्रलोभनों के वितरण पर रोक लगाई जा सके। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ या झूठे प्रचार को नियंत्रित किया जाए। "ये किए तो जाना पड़ेगा जेल"- यह चेतावनी प्रशासन ने खुले रूप में दी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार के आचार संहिता उल्लंघन को अब केवल चेतावनी या जुर्माने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी।यह कठोरता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए आवश्यक है। बीते वर्षों में सोशल मीडिया के ज़रिए झूठे प्रचार, वोटरों को प्रभावित करने वाली गलत सूचनाएं और नफरत फैलाने वाले बयानों की बाढ़ देखने को मिली है। ऐसे में प्रशासनिक सख्ती लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक "टीका" की तरह है।

साथियों बात अगर हम सरकारी सुविधाओं पर रोक, सत्ता और चुनाव के बीच की दीवार की करें तो, आचार संहिता के तहत एक प्रमुख निर्णय यह लिया गया है कि मंत्री अब सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि चुनाव अवधि में सरकारी गाड़ी,सरकारी आवास,सुरक्षा व्यवस्था,या सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं निजी प्रचार में इस्तेमाल नहीं की जा सकतीं। यह प्रावधान सत्ता और चुनाव के बीच एक स्पष्ट दीवार खड़ी करता है।इतिहास साक्षी है कि जब-जब सत्ता में बैठे नेताओं ने सरकारी संसाधनों का उपयोग चुनावी लाभ के लिए किया,तब-तब लोकतंत्र की साख को चोट पहुंची। इसलिए भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इस प्रकार की रोक लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने का आवश्यक औजार है।इसके साथ ही सरकार की वेबसाइटों, विज्ञापनों और प्रचार माध्यमों से नेताओं की तस्वीरें हटाई जा रही हैं। नई योजनाओं, नीतियों या घोषणाओं पर भी रोक रहेगी ताकि जनता के बीच कोई भ्रम या अनुचित लाभ का संदेश न जाए। यही आचार संहिता का सार है -कि सरकार जनता की होती है, किसी एक दल की नहीं।

सभाओं और जुलूसों पर नियंत्रण स्वतंत्रता और अनुशासन का

संगम - लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, परंतु जब यह स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने लगे, तो इसे नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। इसी कारण से चुनाव आयोग ने यह नियम स्पष्ट किया है कि सभा और जुलूस के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।यह व्यवस्था न केवल कानून- व्यवस्था

बनाए रखने के लिए है, बल्कि हिंसा, अव्यवस्था और भीड़-प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी आवश्यकअति है। मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार पर रोक लगाना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को भय, प्रलोभन या दबाव से मुक्त वातावरण प्रदान करना है ताकि वे स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें। यह केवल चुनावी नियम नहीं बल्कि मतदाता की गरिमा और निजता की सुरक्षा है-जो किसी भी लोकतंत्र का मूल तत्व है।

साथियों बात अगर हम लोकतांत्रिक शुचिता का अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को समझने की करें तो,भारत की आचार संहिता की व्यवस्था को दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान जैसे देशों में भी चुनावों के दौरान कुछ सीमित प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, परंतु भारत की तरह व्यापक और संगठित आचार संहिता शायद ही कहीं हो।संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप ने कई बार कहा है कि भारत की चुनावी व्यवस्था "विकासशील लोकतंत्रों के लिए मॉडल" है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और उसके आदेशों की बाध्यता अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भी अत्यंत उच्च मानी जाती है।भारत में एक ही चुनाव में लाखों अधिकारी, सैकड़ों एजेंसियाँ और करोड़ों मतदाता शामिल होते हैं -इस स्तर की पारदर्शिता और संगठन क्षमता किसी भी राष्ट्र के लिए प्रशंसनीय है। यही कारण है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया वैश्विक लोकतंत्रों के लिए अध्ययन का विषय बनी रहती है।

साथियों बात अगर हम राजनीतिक मर्यादा और भाषण की सीमाओं को समझने की करें तो, 2025 के चुनावों में एक और बड़ा मुद्दा है, भड़काऊ बयानों और नफरत फैलाने वाले भाषणों पर रोक। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रचार में धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर विभाजनकारी टिप्पणियाँ न करें।यह दिशा-निर्देश सिर्फ चुनावी शालीनता के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए हैं। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया ने बयानबाजी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। एक ट्वीट या वीडियो लाखों लोगों तक तुरंत पहुँच जाता है, जिससे चुनावी माहौल बुरी तरह भड़क सकता है। इसलिए इस बार आयोग ने साइबर मॉनिटरिंग टीमों की संख्या दोगुनी कर दी है। हर जिला स्तर पर एक "सोशल मीडिया ऑब्जर्वर" नियुक्त किया गया है, जो ऑनलाइन प्रचार पर नज़र रखेगा। इस कदम से लोकतांत्रिक संवाद में संयम और मर्यादा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

साथियों बात अगर हम मतदाता जागरूकता और जिम्मेदारी को समझने की करें तो, लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति मतदाता के हाथ में होती है। प्रशासन और आचार संहिता के सभी नियम तभी प्रभावी हो सकते हैं जब मतदाता भी अपनी जिम्मेदारी समझे। 2025 के चुनावों में "मेरा वोट, मेरा अधिकार" अभियान को फिर से सशक्त रूप में लागू किया गया है। सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, और डिजिटल माध्यमों के जरिए मतदाताओं को मतदान केंद्रों की जानकारी, उम्मीदवारों के विवरण और शिकायत निवारण की सुविधा दी गई है।इसके साथ ही मतदान दर बढ़ाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं, जैसे कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष वाहन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर मतदान की सुविधा, और महिलाओं के लिए "पिंक बूथ"। यह सभी प्रयास लोकतंत्र की भागीदारी को और अधिक समावेशी बनाते हैं।आचार संहिता और राजनीति की नई परिभाषा-भारत में चुनाव अब केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं रह गए हैं, बल्कि यह लोकतांत्रिक परिपक्वता का पैमाना बन गए हैं। आचार संहिता इस प्रक्रिया में नैतिक संतुलन का प्रतीक है। यह राजनेताओं को याद दिलाती है कि सत्ता जनता की सेवा का माध्यम है, न कि निजी अधिकार।2025 का चुनाव इस लिहाज से अलग है कि जनता पहले से अधिक जागरूक है, मीडिया की पहुँच अधिक गहरी है, और चुनाव आयोग की तकनीकी क्षमताएँ भी कई गुना बढ़ी हैं। अब चुनाव का हर चरण नामांकन से लेकर मतगणना तक, डिजिटली मॉनिटर किया जा रहा है।इस पारदर्शिता ने न केवल चुनावों की विश्वसनीयता बढ़ाई है बल्कि भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण की संभावनाएँ भी घटाई हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि,बिहार राज्य विधानसभा चुनाव 2025-आचार संहिता, प्रशासनिक शक्ति और लोकतांत्रिक शुचिता का इम्तिहान"चुनावी आचार संहिता भारतीय लोकतंत्र की वह नैतिक मर्यादा है,जो राजनीतिक दलों,नेताओं और सरकार को सत्ता के दुरुपयोग से रोकती है

क्या क्रिकेट एक युद्ध है ? : जब एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी प्रासंगिकता और पवित्रता खो दी

लेस्ली ज़ेवियर, अनुवाद : संजय पराते)

पिछले एक पखवाड़े में क्रिकेट का खेल बदल गया है, और वह बदतर हुआ है। दुबई में एशिया कप के दौरान जो कुछ हुआ, उसका असर यहाँ भी दिख रहा है : श्रीलंका में आईसीसी महिला विश्व कप के दौरान, भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने 5 अक्टूबर को मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने या उनका अभिवादन करने से परहेज किया। महिलाओं ने भी अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही क्रिकेट की पवित्रता को राष्ट्रवादी उन्माद से धूमिल करने का काम किया।

स्पष्ट है कि दुबई में जो हुआ, वह दुबई तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूँज वर्षों तक रहेगी, खेल को कलंकित करेगी और उस खेल भावना को छीन लेगी, जिसे कोई भी खेल ऊंचा रखने का प्रयास करता है। कला, साहित्य और खेल — वे मानवीय गतिविधियाँ हैं, जिनके साथ एक व्यापक अस्तित्वगत अर्थ जुड़े हैं और जो आत्मनिरीक्षण के लिए लेंस का काम करती है और इतिहास को सही दिशा देने के रास्ते निकालती हैं। बहरहाल, यह चिंताजनक है, जब इन पर बुराइयों का कब्ज़ा हो जाता है और इन्हें हथिया लिया जाता है।

हम 2025 में हैं। दुनिया अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग-अलग स्तर के संघर्ष देख रही है, जिसमें गाज़ा में एक निर्लज्ज जनसंहार भी शामिल है। हमारे देश के नज़दीक, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर और मई में चार दिनों तक चला भारत-पाकिस्तान संघर्ष देखने को मिला। एक समय ऐसा था, जब युद्ध को एक खेल माना जाता था, और हर बम का जश्न ऐसे मनाया जाता था, मानो वह भारत पर किया गया गोल या लिया गया विकेट हो, और सीमा पार पाकिस्तान में भी समान रूप से ऐसा माना जाता था। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ₹जीत₹ का जश्न मनाते हुए पटाखे फूटे, तो हममें से जो लोग नैतिक और मानवीय दुविधा में फँसे थे, और खोई या नष्ट हुई ज़िंदगियों के बारे में सोच रहे थे, वे आश्चर्यचकित थे : क्या युद्ध एक खेल है ?

या फिर, क्या खेल एक युद्ध है ? यह खतरनाक बात है, जब यह संघर्ष जीवन के गैर-राजनीतिक पहलुओं, जिसमें खेल भी शामिल है, में व्याप्त हो जाता है। हालाँकि भू-राजनीतिक सत्ता के लिए खेलों के खुलेआम इस्तेमाल के अपने उदाहरण हैं, लेकिन किसी में भी खिलाड़ियों को मुख्य पात्र नहीं बनाया गया है। यह एक नया निम्न स्तर है। जो पटकथा 2025 के एशिया कप में खेली गई है, उसने क्रिकेट, उसके इतिहास और विरासत, उसके खिलाड़ियों, उसके प्रशंसकों, और उसके सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार, सभी को बदनाम कर दिया है। यह सब तीन असंतुलित भारत-पाक मैचों में हुआ, जहाँ एक पारी, या सीम गेंदबाजी का एक शानदार स्पेल, या बल्ले और गेंद के बीच बिल्ली-और-चूहे का खेल, ये सब कभी चर्चा का विषय नहीं बने।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नेतृत्व में वित्तीय अधिग्रहण के बाद, महाद्वीपीय टूर्नामेंट वैसे भी एकतरफ़ा हो गए हैं। भारत अपने को बड़े भाई के रूप में जताता है, जिससे टूर्नामेंट, प्रतीकात्मक रूप से, सबसे अच्छे गली क्रिकेट से और सबसे बुरा बदमाश बन जाता है। इसलिए, दुबई में मीडिया और व्यापक सोशल मीडिया पर जिस नाटक की व्यापक चर्चा हुई है, वह बल्ले या गेंद पर नहीं हुई है। यह चर्चा प्रतीकात्मक और प्रत्यक्ष राष्ट्रवाद से पैदा हुई थी, जिसकी शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे खेल पर हो-हल्ला मचाने से हुई थी, जबकि दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी।

खैर, अगर बात एक राष्ट्र के तौर पर रुख़ अपनाने की होती, तो जन आक्रोश और तमाशे की स्थिति पैदा करने की अनुमति देने के बजाय, सरकार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न खेलने का नीतिगत फ़ैसला ले सकती थी। उन्होंने सिर्फ़ इसलिए खेलना बंद नहीं किया, क्योंकि भारत-पाक मैच अच्छा बिज़नेस है। बहरहाल, एक बार खेलने का फ़ैसला कर लेने के बाद, उन्हें खेल भावना का पालन करना चाहिए था। न इससे ज़्यादा, न इससे कम।

लेकिन पूरे टूर्नामेंट के दौरान अंधराष्ट्रवाद ही वह व्यापक रणनीति थी, जिसका खुलकर इस्तेमाल किया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने, निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कहने पर ही, मैच के बाद पाकिस्तानी टीम के सदस्यों से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया। यह सिलसिला पूरे टूर्नामेंट में जारी रहा। यह क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए एक नाजुक मुद्दा तो बन ही गया, दुर्भाग्य से, इसके साथ ही जश्न का भी विषय बन गया।

भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, हाँ। बच्चों, आपने बहुत अच्छा खेला, लेकिन लोगों का दिल जीतने की असली बात ही भूल गए। विपक्षी खिलाड़ियों का अभिवादन करने से इंकार करके भारतीय टीम एक ऐसे रास्ते पर चली गई, जहाँ से वापसी संभव नहीं थी। तो फिर भारतीयों ने यहां क्या खोया ? सबसे पहले, उन्होंने अपनी रणनीति, खेल भावना का एक बड़ा स्कोर खो दिया, और सबसे बुरी बात यह कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया कि खेल अपनी पवित्रता खो दे।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान भी उतने ही परेशान करने वाले थे, जिनके प्रदर्शन की पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बराबरी की, या उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया। हारिस राउफ़ का 'क्रैशिंग जेट' वाला जश्न इसका उदाहरण था। जसप्रीत बुमराह ने भी बदला चुकाते हुए स्कोरबोर्ड पर बराबरी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दो मुख्य टीमें, यादव और रऊफ, का खेल बेहद खराब रहा। भारतीय कप्तान ने टूर्नामेंट के दूसरे मैच में नाबाद 47 रन बनाए थे। जी हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ। बहरहाल, बाकी मैचों में उन्होंने 7 (नाबाद), 0 (पाकिस्तान के खिलाफ), 5, 12 और 1 (फाइनल में) रन बनाए थे। वहीं, रऊफ ने फाइनल में अपने चार ओवरों में 50 रन देकर अकेले दम पर पाकिस्तान की हार सुनिश्चित कर दी थी।

क्या दोनों टूर्नामेंट की चर्चाओं में प्रासंगिक बने रहने के लिए आसान, राष्ट्रवादी रास्ता अपना रहे थे ? शायद। खिलाड़ियों ने अब प्रचलित राजनीतिक रणनीति को बड़ी खूबसूरती से अपनाया है। मुद्दा चाहे जो भी हो, भावनाओं को भड़काओ और बेमतलब की बातों पर मज़ाक करो, और इससे लोगों का ध्यान भटक जाता है। अगर बात युद्ध पर केंद्रित हो, तो और भी अच्छा। वाकई, एक बेहतरीन कवर-ड्राइव !

और फिर आया वो शर्मनाक पल। चैंपियन टीम के खिलाड़ियों ने अपनी जीत में क्षुद्रता दिखाने का रास्ता अपनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी उठाने या अपने पदक स्वीकार करने से इंकार कर दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें पाकिस्तान के संघीय गृह मंत्री, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के हाथों से इसे प्राप्त करना था।

दुबई में, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी मंत्री को जीत के लिए पुरस्कार और बधाई देने के भारी-भरकम काम से बचाने का बीड़ा उठाया। अगर ऐसा होता, तो भले ही मतभेद कम न होते, लेकिन इस टूर्नामेंट से सरहद के दोनों ओर भड़की नाराज़गी ज़रूर कुछ हद तक कम हो जाती।

राजनेता इस कथानक से खेलते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हैं, और न्यूज़रूम में इसे तूल देते हैं। ये सब आजकल भारत में आम बात है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने इस जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे से की, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि अगर प्रशंसक और खिलाड़ी खेल के जश्न में खो गए हों, तो उन्हें एक बात याद कराओ : यह एक युद्ध है, जिसका जश्न मनाने की ज़रूरत है। शतक और विकेट का जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, और निश्चित रूप से जीत की ट्रॉफी लेने की भी जरूरत नहीं है।

उम्मीद थी कि कला और साहित्य के साथ-साथ खेल भी मानवता की उम्मीद की आखिरी किरण बने रहेंगे। बहरहाल, यह खेलों की राजनीति है, जो सबसे आगे है।

सभी खेलों में, खासकर ओलंपिक खेलों में, राजनीतिक प्रभाव, किसी भी तरह का पूर्वाग्रह (प्रतीकात्मक हो या न हो) बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसमें शामिल टीमों या खिलाड़ियों को कड़ी सज़ा दी जाती है। लेकिन कम से कम क्रिकेट में तो ऐसा नहीं होगा।

इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया था, जब खेलों को केंद्र में रखने के लिए युद्ध विराम की माँग की गई थी। 1969 में नाइजीरिया में सैंटोस एफसी के दौरे के दौरान ऐसा ही एक प्रसिद्ध उदाहरण देखने को मिलता है। उस समय बियाफ्रान युद्ध चल रहा था, और लोगों को पेले का खेल देखने की अनुमति देने के लिए कथित तौर पर 48 घंटे के युद्धविराम की घोषणा की गई थी। यह ब्राज़ीलियाई क्लब और नाइजीरियाई राष्ट्रीय टीम के बीच एक प्रदर्शन मैच था, और यह घटना इतिहास में हमेशा के लिए खेलों की ताकत के प्रदर्शन के रूप में दर्ज हो गई है, जो दूरियों को पाटने में मदद करती है।

एशिया कप के दौरान दुबई में क्रिकेट की जो गिरावट देखी गई, उसे इतिहास में इसके बिल्कुल उलट के रूप में याद किया जाएगा। यह इस बात को सिद्ध करने का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है कि सत्ता में बैठे लोग खेल की क्षमता का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।

जहाँ तक भारत-पाकिस्तान के बीच की कहानी का सवाल है, इसे बदनामी की इस अकल्पनीय गहराई तक पहुँचने में कई दशक लगे हैं। 1990 के दशक में, केबल टीवी पर क्रिकेट के आगमन के शुरुआती वर्षों में, भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय श्रृंखलाओं और यहाँ तक कि बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में मुकाबलों को भी युद्ध जैसा बताया जाता था। उन दिनों, प्रशंसकों के रूप में, हम यह मान लेते थे कि यह शायद यह दर्शाने के लिए एक उदाहरण है कि खेल कितने प्रतिस्पर्धी हैं।

यहाँ पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ों का सामना करते भारतीय बल्लेबाज़ों की याद आती है, जो हर स्विंग और उछाल का कलात्मक विलो स्वोश से मुकाबला करते थे। ये कड़े मुक़ाबले थे, जो पीठ थपथपाने और पारंपरिक हाथ मिलाने के साथ समाप्त होते थे। 2004 में, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने ठीक इसी बात पर ज़ोर दिया था, जब उन्होंने खिलाड़ियों से कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान दौरे पर सिर्फ़ मैच ही नहीं, बल्कि दिल भी जीतने को कहा था।

बहरहाल, उस समय खेलों को युद्ध बताकर, मैदान पर दुश्मनी के बीज एक सहज तरीके से बो दिए गए थे। कुछ दशक आगे बढ़ते हुए, हमने इसे क्रिकेट के अब तक के सबसे बड़े अपमान के क्षणों में से एक के रूप में विकसित होते देखा, जिसकी जड़ें दोनों देशों की मानसिकता में गहराई से जमी हुई हैं।

जहाँ तक भारत का सवाल है, हो सकता है कि देश में व्याप्त व्यापक माहौल में फँसने से बचना मुश्किल हो। जैसा कि हम जानते हैं, पत्रकारिता भी इसके आगे घुटने टेक चुकी है। उन्होंने, हमेशा की तरह, एशिया कप में भी युद्ध की आग भड़काई। वे (यहाँ यदि क्रिकेट की भाषा का प्रयोग किया जाएं, तो) काफ़ी हद तक शांत पड़ गए। खैर, कला और साहित्य इस समय मुश्किल हालात में हैं। और खेल, ख़ासकर क्रिकेट, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रासंगिकता खो बैठा है : खेल के भारतीय अग्रदूतों की इस मौजूदा पीढ़ी की इस सीमित समझ के कारण कि वे किसके लिए और क्या खेल रहे हैं। इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

हालाँकि, भारतीय टीम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई है। अगले दौरे की घोषणा हो चुकी है। टीम तैयारी में जुटी है। दोनों देशों की महिला टीमें श्रीलंका में हुए विश्व कप में भिड़ीं, जिससे युद्धाभ्यास जारी रहा।

क्या दुबई में क्रिकेट की प्रतिष्ठा में आई गिरावट से क्रिकेट कभी उबर पाएगा ? क्या क्रिकेट जीत और हार की उस कड़वी कहानी से उबर पाएगा, जिसमें राजनेताओं, क्रिकेट प्रशासकों और खिलाड़ियों ने उसे घसीटा था ?

एशिया कप में जो कुछ हुआ, उससे हुए असली नुकसान का एहसास होने में हमें कुछ वक्त लग सकता है। तब तक, हम अपनी पुरानी बात से ही चिपके रहेंगे : स्कोर क्या हुआ ?

(लेखक खेल पत्रकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं)

आरएसएस के सौ वर्ष और भारतीय संविधान

(आलेख : जवरीमल्ल पारख)

भारतीय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना को सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। पिछले 11 वर्षों से आरएसएस, जो एक सांप्रदायिक-फासीवादी संगठन है, देश पर शासन कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है, जो लम्बे समय से आरएसएस का कार्यकर्ता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि नरेन्द्र मोदी का शासनकाल आज़ादी के बाद का सबसे संकटपूर्ण और चुनौती भरा काल है। धर्म के नाम पर जिस तरह एक पूरे धार्मिक समुदाय को देश के दुश्मन की तरह पेश किया जा रहा है और उन्हें संविधान में मिले नागरिक अधिकारों से वंचित कर उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक में तब्दील किया जा रहा है, वह इस राजसत्ता के फ़ासीवादी चरित्र का ही प्रमाण है। भारत का यह फ़ासीवाद अपने चरित्र में अति-दक्षिणपंथी भी है और ब्राह्मणवादी भी। मौजूदा राजसत्ता के विरुद्ध संघर्ष उन सब भारतीयों का कर्त्तव्य है, जो भारतीय संविधान में यक़ीन करते हैं और जो भारत की बहुविध धार्मिक, जातीय, भाषायी और सांस्कृतिक परंपरा को बचाये रखना चाहते हैं, क्योंकि असली भारत इसी परंपरा में निहित है, जिसे हिंदुत्वपरस्त ताक़तें ख़त्म करना चाहती हैं।

मौजूदा राजसत्ता के चरित्र को समझने के लिए आरएसएस की विचारधारा को समझना जरूरी है। वे अपनी राजनीतिक विचारधारा को हिंदुत्व नाम देते हैं। यह विचारधारा उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर से ग्रहण की थी, जिन्होंने 1923 में 'हिंदुत्व' नामक पुस्तक लिखी थी। आरएसएस ने अपने इस राजनीतिक उद्देश्यों को कभी छुपाया नहीं। इस संगठन के दूसरे सरसंघचालक एम एस गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'वी ऑर अवर नेशनहुड' में जो विचार पेश किये, उसके पीछे फासीवाद और नाज़ीवाद का प्रभाव भी था। इस पुस्तक में गोलवलकर यह प्रश्न उठाते हैं कि 'अगर निर्विवाद रूप से हिंदुस्थान हिंदुओं की भूमि है और केवल हिंदुओं के फलने-फूलने के लिए ही है, तो उन सभी लोगों की नियति क्या होनी चाहिए, जो इस धरती पर रह रहे हैं, परंतु हिंदू धर्म, नस्ल और संस्कृति से संबंध नहीं रखते' (गोलवलकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा : एक आलोचनात्मक समीक्षा, शम्सुल इस्लाम, फारोस, नयी दिल्ली, पृ. 199)। स्वयं द्वारा उठाये इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे लिखते हैं कि 'वे सभी, जो इस विचार की परिधि से बाहर हैं, राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं रख सकते। वे राष्ट्र का अंग केवल तभी बन सकते हैं, जब अपने विभेदों को पूरी तरह समाप्त कर दें। राष्ट्र का धर्म, इसकी भाषा एवं संस्कृति अपना लें और खुद को पूरी तरह राष्ट्रीय नस्ल में समाहित कर दें। जब तक वे अपने नस्ली, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अंतरों को बनाये रखते हैं, वे केवल विदेशी हो सकते हैं, जो राष्ट्र के प्रति मित्रवत हो सकते हैं या शत्रुवत' (वही, 199)। गोलवलकर की इन बातों का अर्थ यही है कि भारत केवल हिंदुओं का राष्ट्र है और बाकी सभी धार्मिक और नस्ली समुदाय विदेशी हैं। वे भारत में रह सकते हैं, लेकिन तभी जब वे 'अपने विभेदों को पूरी तरह समाप्त कर दें' और 'खुद को पूरी तरह राष्ट्रीय नस्ल में समाहित कर दें'। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि 'अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें राष्ट्र के रहमो-करम पर, सभी संहिताओं और परंपराओं से बंधकर केवल एक बाहरी की तरह रहना होगा, जिनको किसी अधिकार या सुविधा की तो छोड़िए, किसी विशेष संरक्षण का भी हक़ नहीं होगा' (वही, पृ. 201-202)। अगर वे अपने को राष्ट्रीय नस्ल में समाहित नहीं करते हैं तो 'जब तक राष्ट्रीय नस्ल उन्हें अनुमति दें, वे यहां उसकी दया पर रहें और राष्ट्रीय नस्ल की इच्छा पर यह देश छोड़कर चले जाएं'। स्पष्ट है कि आरएसएस के अनुसार हिंदू राष्ट्र में गैर-हिंदुओं, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों, को नागरिकता के वे अधिकार नहीं मिल सकते, जो हिंदुओं को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होंगे। यानी उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। यह संयोग नहीं है कि आरएसएस ने अपनी प्रेरणा फासीवाद और नाजीवाद से ग्रहण की है। इस पुस्तक में गोलवलकर ने अल्पसंख्यकों के प्रति जर्मनी और इटली ने जो रवैया अपनाया था, उसकी न केवल प्रशंसा की, बल्कि उसे अनुकरणीय भी माना।

भाजपा आरएसएस का हिस्सा है और उसी की विचारधारा इसका राजनीतिक आधार है। यह एक तथ्य है कि आरएसएस ने कभी भी आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया और इनके वैचारिक गुरु सावरकर वह पहले व्यक्ति थे, जो धर्म को राष्ट्र का आधार मानते थे और द्विराष्ट्र की धारणा को मुस्लिम लीग से पहले पेश किया था। जब संविधान बन रहा था, तब आरएसएस उसका लगातार विरोध करता रहा। संविधान की शपथ लेने और संसद की चौखट पर सिर टेकने से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं। आज की सचाई भी यही है कि आरएसएस न संविधान में यकीन करती है और न ही संघात्मक गणराज्य में। गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'विचार नवनीत' (बंच ऑफ थॉट्स) में संविधान पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था, 'हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों में से लिए गए विभिन्न अनुच्छेदों का एक भारी-भरकम तथा बेमेल अंशों का संग्रह मात्र है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, जिसको कि हम अपना कह सकें। उसके निर्देशक सिद्धांतों में क्या एक भी शब्द इस संदर्भ में दिया है कि हमारा राष्ट्रीय-जीवनोद्देश्य तथा हमारे जीवन का मूल स्वर क्या है ? नहीं' (विचार नवनीत, ज्ञानगंगा, जयपुर, 1997, पृ. 237)। संघ और भाजपा अकेले ऐसे संगठन हैं, जो संघात्मक गणराज्य में यकीन नहीं करते। गोलवलकर ने लिखा था, 'आज की संघात्मक (फेडेरल) राज्य पद्धति पृथकता की भावनाओं का निर्माण और पोषण करने वाली, एक राष्ट्र भाव के सत्य को एक प्रकार से अमान्य करने वाली एवं विच्छेद करने वाली है। इसको जड़ से ही हटा कर तदनुसार संविधान शुद्ध कर एकात्म शासन प्रस्थापित हो' (समग्र दर्शन, खंड-3, भारतीय विचार साधना, नागपुर, पृ. 128)।

भारतीय संविधान के मूल में यह मान्यता थी कि भारत विभिन्न राष्ट्रीयताओं का संघ है, क्योंकि भारत विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय भिन्नताओं और सांस्कृतिक बहुलताओं वाला देश है। इन भिन्नताओं को स्वीकार करके ही उनके बीच एकता की स्थापना की जा सकती है। इसीलिए भारत की संकल्पना संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक संघात्मक गणराज्य के रूप में की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढने से यह स्पष्ट हो जाता है। यह प्रस्तावना कहती है, 'हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढसंकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं'। इसके विपरीत आरएसएस भारत को हिंदुओं का ही देश मानता है और अन्य धर्मावलंबियों को या तो हिंदुओं में ही समाहित करता है या उन्हें विदेशी मानता है, इसलिए वह एक राष्ट्र, एक धर्म, एक नस्ल, एक जाति की बात करता है। स्वयं आरएसएस का उद्देश्य, 'एक ध्वज के नीचे, एक नेता के मार्गदर्शन में, एक ही विचार से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की प्रखर ज्योति इस विशाल भूमि के कोने-कोने में प्रज्ज्वलित कर रहा है' (समग्र दर्शन, खंड-1, पृ. 11)। नरेंद्र मोदी के शासन काल में जो बदलाव हो रहे हैं, उनको हम तभी समझ सकते हैं, जब आरएसएस की उपर्युक्त विचारधारा को ठीक से समझें।

भारतीय जनता पार्टी (जिसका पहले नाम भारतीय जनसंघ था) जब-जब सत्ता में आयी है, चाहे राज्यों में हो या केंद्र में, उसने उस दिशा में लगातार कदम उठाये, जो आरएसएस की सांप्रदायिक-फासीवादी विचारधारा के पक्ष में जाते हैं। लेकिन 2014 में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन इस काम में सफलता तभी हासिल हो सकती है, जब व्यापक हिंदू जनता का समर्थन उसे मिले। इस दिशा में तो आरएसएस और उससे संबद्ध सभी संगठन ज़मीनी स्तर पर हमेशा काम करते रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने पर वे पूरे सरकारी तंत्र का भी निर्लज्जतापूर्वक अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इनमें पाठ्यक्रमों में फेरबदल, हिंदुत्वपरस्त सांप्रदायिक इतिहास लेखन और अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए सिनेमा सहित मीडिया का इस्तेमाल शामिल हैं। लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण है कानूनों में बदलाव। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणापत्रों में तीन लक्ष्यों को बार-बार दोहराती रही है। पहला : कश्मीर से धारा 370 हटाना, दूसरा : समान नागरिक संहिता लागू करना और तीसरा : अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। नरेंद्र मोदी के शासन काल में कश्मीर से धारा-370 हटायी जा चुकी है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा चुका है और जनवरी, 2024 में मंदिर के द्वार भी खुल चुके हैं। और समान नागरिक संहिता भी कुछ भाजपा शासित राज्यों में लागू की जा चुकी है।

जिस दौर में सांप्रदायिक राजनीति का तेजी से फैलाव और उभार हो रहा था, उसी दौर में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह दक्षिणपंथी करवट ले रही थी। कह सकते हैं कि इस दौर में पूंजीवादी व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ है, उनमें पारस्परिक आदान-प्रदान बढ़ा है और जो और जिस तरह की भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं थीं, वे या तो ढह गयी हैं, या कमजोर हुई हैं। इस दौर की तीन पहचानें हैं : निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण। इसी दौर की उपज आतंकवाद भी है। आतंकवाद को विश्वव्यापी और खतरनाक बनाने में यदि अमरीका की नवसाम्राज्यवादी नीतियां जिम्मेदार हैं, तो उस प्रौद्योगिकी का भी हाथ है, जो नवीनतम हथियारों और संचार प्रौद्योगिकी के रूप में सामने आये हैं। भारत में आतंकवाद कई रूपों में सक्रिय है। लेकिन मीडिया आमतौर पर कथित रूप से जिहादी या इस्लामी आतंकवाद को ही अपने हमले का निशाना बनाता रहा है। आतंकवाद यदि एक ओर देशभक्ति की भावनाओं को भुनाने का जरिया बनता है, तो दूसरी ओर, यह मीडिया को एक बहुत ही उत्तेजनापूर्ण और रोमांचकारी विषयवस्तु भी प्रदान करता है। मीडिया दर्शकों के इस राजनीतिक दुराग्रह को मजबूत करता है कि 'सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं' जबकि हिंदुत्वपरस्त आतंकवाद भी अपने खुंखार रूप में सामने आ चुका है। यहां यह नहीं भुला जाना चाहिए कि गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार और बाबरी मस्जिद का विध्वंस, उड़ीसा, कर्नाटक आदि में ईसाइयों पर हमले भी आतंकवाद ही है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मुसलमानों की भीड़ द्वारा हत्या, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाना और उन्हें निरपराध होते हुए भी गिरफ्तार करके लंबे समय के लिए जेल भेज देना भी आतंकवाद ही है। मणिपुर में पिछले तीन साल से कुकी आदिवासी समूह और मैतेई लोगों के बीच गृह युद्ध की-सी स्थिति बनी हुई है।

2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार लगातार ऐसे कदम उठाती रही है, जिसका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है, ताकि वे एकजुट होकर भाजपा को वोट दे। उनमें और मुसलमानों में इस हद तक विभाजन पैदा करना है, जिससे न केवल हिंदू एकजुट हों, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग-थलग भी किया जा सके। चाहे मसला, गो-मांस या गो-तस्करी का हो या लव ज़िहाद का या जय श्रीराम बोलने का, मकसद यही है कि मुसलमानों में ऐसा भय पैदा किया जाए, जिससे कि वे अपने को मुख्यधारा से अलग-थलग कर लें। उनका मकसद यह भी है कि वे हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत और घृणा भर दे (और भय भी) कि वे उनका अपने आसपास होना भी बर्दाश्त न कर सके और मौका लगते ही उनके प्रति हिंसक हो जाए। हिंदू यह मानने लगे कि मुसलमान उनके लिए वैसे ही बोझ हैं, जैसे हिटलर की जर्मनी में यहूदी। उनकी समस्त परेशानियों का कारण मुसलमान ही है। इसलिए मुसलमानों के विरुद्ध किया जाने वाला कोई अपराध, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। प्रधानमंत्री ही नहीं, भाजपा और संघ का कोई नेता ऐसे हिंसक अपराधों की न तो कभी निंदा करता है और न ही इन अपराधों की रोकथाम के लिए भाजपा सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है। उनकी कोशिश यह भी है कि एक समुदाय के रूप में मुसलमानों की देशभक्ति को हिंदुओं की नज़रों में संदिग्ध बना दिया जाए। उनकी मौजूदगी को औरतों और बच्चों के लिए खतरा बताया जाये।

इन दस सालों में मनुवादी, दलितविरोधी, पितृसत्तावादी, मुस्लिम-विरोधी, हिंदुत्वपरस्त ताक़तों को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि यह राजसत्ता उनकी है। यह अकारण नहीं है कि इन दस सालों में लगातार मुसलमानों पर ही नहीं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अन्य कमज़ोर वर्गों पर हमले बढ़े हैं। शिक्षा संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण लगातार कम किया जा रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बेचने की मुहिम का नतीजा है कि इन सभी कमज़ोर वर्गों के रोज़गार के रास्ते लगातार बंद होते जा रहे हैं।

लेकिन इन सबसे अधिक खतरनाक है, कानूनों में ऐसे बदलाव, जिसके कारण जहां एक ओर मुसलमानों को संविधान में मिली समानता और स्वतंत्रता में कटौती की जा रही है, तो दूसरी ओर आम भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनमें भी कटौती की जा रही है। इसके साथ ही पिछले दस सालों में संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है।

5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक प्रक्रियाओं को धता बताते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के उन प्रावधानों को हटा दिया है, जो भारत के साथ उसके विलय के समय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किये गये थे। आर्टिकल 370 के इन प्रावधानों को हटाये जाने से पहले भी और आज भी, जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग था और है। लेकिन अब वह राज्य नहीं रह गया है, बल्कि इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। जम्मू और कश्मीर ऐसा केंद्रशासित प्रदेश होगा, जिसमें एक विधानसभा तो होगी, लेकिन जिसे वे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को प्राप्त होते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की सलाह और स्वीकृति के बिना वहां का मंत्रिमंडल कोई काम नहीं कर सकेगा। लद्दाख भी केंद्रशासित प्रदेश होगा, लेकिन उसकी कोई विधान सभा नहीं होगी और वह सीधे केंद्र द्वारा ही शासित होगा। इन छः सालों में लद्दाख की ज़मीनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है, वह सीमावर्ती राज्य होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ही खतरा नहीं पैदा कर दिया है, बल्कि वहां के पर्यावरण को भी गहरा नुकसान पहुँचाने की संभावना पैदा कर दी है। लद्दाख से राज्य के अधिकार छीने जाने का ही नतीजा है कि वहां के नागरिकों में गहरा असंतोष पैदा हो गया है। लद्दाख के सर्वाधिक सम्मानित नागरिक सोनम वांगचुक के नेतृत्व में वहां की जनता अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष कर रही है, उसे राज्य की हिंसा द्वारा कुचला जा रहा है और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया है।

इस तरह जम्मू और कश्मीर राज्य को जो स्वायत्तता प्राप्त थी, उसने सिर्फ वही नहीं खो दी है, बल्कि उसे वह स्वायत्तता भी नहीं मिली है, जो अन्य पूर्ण राज्यों को प्राप्त है। केंद्र को आज की तरह उन्हें वहां सेना, अर्धसैनिक बल तैनात करने का ही अधिकार नहीं होगा, बल्कि वहां की पुलिस भी पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में होगी। निश्चय ही यह विलय के समय हुए समझौते और संविधान सभा द्वारा किये गये प्रावधानों का उल्लंघन है। ये प्रावधान क्या है, जिसे खत्म करना इतना जरूरी समझा गया और इन्हें समाप्त करने के बाद ही यह माना जा रहा है कि अब जम्मू और कश्मीर भारत का वास्तव में अंग बना है।

कश्मीरी मुसलमानों को आतंकवादी बताने के लिए केंद्र की मोदी सरकार दो और हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक, कश्मीर के मुसलमान जो उनकी नज़र में अलगाववादी हैं और पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद के समर्थक हैं और इसी प्रचार का परिणाम है कश्मीर फाइल्स जैसी फ़िल्म। दूसरे, वे सभी मुसलमान, जिनके पास भारत की नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं हैं, उन्हें घुसपैठिए और देश के लिए खतरनाक बताकर बाहर निकालना और जब तक वे भारत से बाहर नहीं जाते, तब तक के लिए उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित करके नज़रबंदी शिविरों में रखना। इसी के लिए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लाया गया है और जिसका अगला कदम नागरिकों का राष्ट्रीय पंजीकरण (एनआरसी) होगा। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि कुछ भी क्यों न हो, उन्हें समान नागरिकता का अधिकार देता है। लेकिन अब इसमें से मुसलमानों को अलग कर दिया गया है। अगर कोई पड़ोसी राज्य का मुसलमान भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे सीएए के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। जहां तक नागरिकता के रजिस्टर का सवाल है, इससे उन सभी लोगों की नागरिकता खतरे में पड़ जायेगी, जिनके पास नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। लेकिन मुसलमानों को छोड़कर शेष समुदायों को शरणार्थी मानकर नागरिकता दे दी जायेगी।

नरेंद्र मोदी सरकार के निशाने पर भारत की लोकतांत्रिक और संघात्मक संरचना है। अभी हाल ही में संसद में जो बिल पेश किया गया है जिसके आधार पर किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और किसी भी मंत्री को एक माह तक जेल में रहने के आधार पर अपने पद से बर्खास्त किया जा सकता है। यह एक खतरनाक विधेयक है, क्योंकि इन 11 सालों में किस तरह विरोधी दल के नेताओं पर झूठे मामले चलाकर जेल में डाला गया है, इसे पूरा देश देख चुका है। इसी तरह सूचना के अधिकार कानून को कमजोर बनाया जा चुका है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाये जा रहे हैं। इसी तरह कई आपराधिक और दंडात्मक कानून बदले गये हैं। उनके केवल हिंदी नाम नहीं रखे गये हैं, बल्कि उन्हें पहले से ज्यादा कठोर बना दिया गया है, दावा भले ही इससे उलट किया गया हो। मसलन, धारा 124, जो देशद्रोह से संबंधित कानून है और जो अंगरेजों के समय से चला आ रहा था और जिसे हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, उसे हटा दिया गया है। संसद में इस कानून को समाप्त करने की घोषणा करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आजाद भारत में इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए और सबको अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन इस कानून की जगह अब जो नया कानून लाया जा रहा है, उसमें वे सभी प्रावधान हैं, जो धारा 124 में थे।

यह भी नहीं भूला जाना चाहिए कि पिछले दस साल में इसी सरकार ने धारा 124 का काफी इस्तेमाल किया है। इसी तरह यूएपीए जैसा कानून का भी इस सरकार ने सबसे अधिक इस्तेमाल किया है, जिसमें बिना कारण बताये किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भीमा कोरेगांव और 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में पांच साल से ज्यादा समय से बहुत से बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता बिना मुकदमा चलाये जेलों में बंद है। कानूनों में जो बदलाव किये जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि सरकार के निशाने पर धार्मिक अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुसलमान हैं, जिन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा आदि भाजपा शासित राज्यों में तुरत-फुरत न्याय के नाम पर मुसलमानों के घर, दुकानें और व्यवसायिक भवनों को बुलडोजर के द्वारा धराशायी किया गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले हरियाणा में नूंह में हुए दंगे के बाद बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के घर, दुकानें और कई भवन बुलडोजर से धराशायी कर दिये गये। न्याय करने का यह गैरकानूनी तरीका है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने यह टिप्पणी करते हुए इस पर रोक लगायी थी कि क्या यह जातीय नरसंहार का मामला है ? इस मामले में इन दो न्यायाधीशों द्वारा आगे सुनवाई हो, उससे पहले ही उन दोनों न्यायाधीशों से केस हटा दिया गया।

दरअसल, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई अंग ऐसा नहीं है, जो इस सांप्रदायिक-फासीवादी सरकार के निशाने से बाहर है। संसद का हाल हम देख रहे हैं, जिसकी बहसों में शामिल होना प्रधानमंत्री अपना अपमान समझते हैं। बहुत से जरूरी विधेयक बिना बहस-मुबाहिसे के पास हो जाते हैं। अगर विपक्ष का कोई सांसद ज्यादा विरोध करता है, तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। इससे कुछ भिन्न स्थिति न्यायपालिका की नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर मामलों में न्यायालय के फैसले न्याय से नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीतिक जरूरतों से तय होते हैं। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जिस तरह से अधिकतम सजा दी गयी, वह इसका ठोस प्रमाण है। अरुण गोयल को चुनाव आयोग का सदस्य नियुक्त करने का जो तरीका अपनाया गया, वह इतना अधिक पक्षपातपूर्ण था कि पांच जजों की बैंच ने यह व्यवस्था की कि जब तक संसद कानून नहीं बनाता, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जिन तीन सदस्यों द्वारा होगी उनमें प्रधानमंत्री, विपक्षी दल का नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन अब सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है, जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जिन तीन सदस्यों द्वारा होगी, उनमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केबिनेट मंत्री होगा। स्पष्ट है कि केबिनेट मंत्री कभी भी अपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं जायेगा, इसलिए भविष्य में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा होगी। विपक्ष के नेता पक्ष में रहे या विपक्ष में उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग का जो रवैया अब देखने को मिल रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि भाजपा का ही एक संगठन है।

ये सब बदलाव जो हो रहे हैं, वह लोकतंत्र को कमजोर करने वाले हैं और संविधान की मूल आत्मा का हनन है। इसका एक मकसद हिंदू राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ाते जाना है, तो दूसरी तरफ भारत के लोकतांत्रिक और संघात्मक ढांचे की बुनियाद को कमजोर करना है। ये दोनों मकसद दरअसल एक ही हैं।

मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के छीने जाने से हो सकता है कि फौरी तौर पर हिंदू आबादी का बड़ा हिस्सा इसे राष्ट्रवाद की विजय के रूप में देखे और इस बात से प्रसन्न हो कि पाकिस्तान की तरह हम भी एक धार्मिक राष्ट्र बन गये हैं, लेकिन इन सबकी आड़ में जो शोषणकारी पूंजीवादी राजसत्ता और साम्राज्यवाद का दबाव जनता के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है और आगे ये मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, उसे वे कैसे और कब तक भूल पायेंगे। देश पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और मंदी की मार से त्रस्त है और इनके पास इन समस्याओं से निपटने के जो तरीके हैं, उनसे निश्चय ही संकट और गहराता जाएगा, तब हिंदू राष्ट्र के प्रति गर्व भावना और मुसलमानों के प्रति नफ़रत उनकी कोई मदद नहीं करेगी। यही नहीं, संघ की विचारधारा केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के ही विरुद्ध नहीं है, वह दरअसल ब्राह्मणवादी विचारधारा भी है और उसका एक बड़ा हिस्सा जितनी नफरत मुसलमानों से करता है, उससे कम दलितों से नहीं करता। वे यह भी चाहते हैं कि दलितों को संविधान ने जो बराबरी का अधिकार दिया है, आरक्षण की सुविधा दी है, वह भी उनसे छीन ली जाए। सच्चाई यह है कि संघ का पूरा वैचारिक परिप्रेक्ष्य लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता और संघीय संरचना के विरोध में निर्मित हुआ है। उनके हमले का मूल निशाना यह संविधान ही है, जिसे वे खत्म न कर सकें, तो पूरी तरह से कमजोर और निष्प्रभावी जरूर बना देना चाहते हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार यही काम कर रही है। संविधान हमारे लोकतंत्र का ही नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक की आज़ादी का भी रक्षक है और उसी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।

उम्र की ढलती सांझ में

विजय गर्ग

भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को अनुभवों का खजाना माना जाता रहा है, मगर चिंताजनक है कि बुजुर्ग अब परिजनों और समाज की उपेक्षा, दुर्व्यवहार सहित कई तरह की समस्याएं झेलने को विवश हैं। भारतीय समाज में सदा सयुंक्त परिवार को अहमियत दी जाती रही है, जहां बुजुर्गों का स्थान सर्वोपरि रहा है, मगर अब एकल परिवारों के बढ़ते चलन के कारण बुजुर्गों की उपेक्षा बढ़ रही है। दरअसल, समाज में अपनी हैसियत बड़ी दिखाने की चाहत में कुछ लोगों को अपने ही परिवार के बुजुर्ग मार्ग की बड़ी रुकावट लगने लगते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक तौर पर अपनी खुशियों में बुजुर्गों को शामिल करना शान के खिलाफ लगता है। ऐसी ही रूढ़िवादी सोच के कारण उच्च वर्ग से लेकर मध्यवर्ग तक में अब वृद्धजनों के प्रति स्नेह की भावना कम हो रही है। एक गैर-सरकारी संस्था की रपट के अनुसार भारत में 47 फीसद आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर हैं, 34 फीसद पेंशन और नकद हस्तांतरण पर निर्भर हैं, जबकि सर्वेक्षण में 40 फीसद लोगों ने यथासंभव काम करने की इच्छा व्यक्त की। सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई कि 71 फीसद वरिष्ठ नागरिक काम नहीं कर रहे थे, जबकि 36 फीसद काम करने को तैयार थे। यही नहीं, 30 फीसद से ज्यादा बुजुर्ग तो विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से अपना समय देने को तैयार थे, जिससे स्पष्ट है कि अगर पुरानी पीढ़ी की ऊर्जा को पर्याप्त अवसर मिले तो भारत की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर उज्ज्वल हो सकती है। एक गैर-सरकारी संगठन की रपट के अनुसार 2022 तक दुनिया में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 110 करोड़ और कुल आबादी की लगभग 14 प्रतिशत थी। 2050 तक यह आबादी बढ़कर 210 करोड़ और कुल आबादी की लगभग 22 प्रतिशत होने की संभावना है। एशिया में बुजुर्ग आबादी 2050 तक 130 करोड़ हो जाएगी। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी अभी करीब 14.9 करोड़ है और एक रपट के मुताबिक 2026 तक यह 17 करोड़, 2036 तक 23 करोड़ तथा 2050 तक 35 करोड़ यानी कुल आबादी की 20 फीसद से भी ज्यादा होने का अनुमान है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 2036 तक दक्षिण भारत के राज्यों में हर पांचवां व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में होगा। बुजुर्ग आबादी में यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगी। ऐसे में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की उचित देखभाल के लिए उचित प्राथमिकताएं निर्धारित करना सरकार की जिम्मेदारी है। % हेल्प एज इंडिया% की नवीनतम रपट %वीमेन एंड एजिंग इनविजिबल आर एंपावर्ड ?% में मई से जून 2023 के दौरान 60-90 वर्ष की आयु वर्ग की 7911 महिलाओं को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया। संगठन ने विभिन्न सामाजिक- आर्थिक श्रेणियों को शामिल करते हुए बीस राज्यों, दो केंद्रशासित प्रदेशों और पांच महानगरों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के प्रतिभागियों के बीच यह सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सोलह प्रतिशत वृद्ध महिलाओं को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिनमें से करीब पचास फीसद महिलाओं को शारीरिक हिंसा और छियालीस फीसद बुजुर्ग महिलाओं को अपमान झेलना पड़ा। चालीस फीसद प्रतिभागियों को भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक शोषण का सामना करना पड़ा। सर्वेक्षण में शामिल कुल चालीस फीसद महिलाओं ने अपने बेटों को दोषी ठहराया, जबकि इकतीस फीसद ने अपने रिश्तेदारों और सताईस फीसद ने अपनी बहुओं को जिम्मेदार बताया। रपट में यह खुलासा भी हुआ कि दुर्व्यवहार के बावजूद अधिकांश बुजुर्ग महिलाओं ने डर के कारण पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। एक बेहतर भविष्य के लिए हम अपनी अगली पीढ़ी को निधि समझते हुए उसकी बेहतर परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते। मगर तमाम जिम्मेदारियां निभाते निभाते जब उम्र ढलने लगती और व्यक्ति शारीरिक तथा वित्तीय स्तर पर कमजोर होने लगता है, तो कई बार वह परिवार और समाज की उपेक्षा का शिकार होने लगता है। भले बड़े गर्व के साथ यह कहा जाता है कि भारत की सत्तर फीसद आबादी नौजवानों की है, जो देश के लिए एक बड़ी पूंजी है, लेकिन यहां चिंता का विषय यह भी है कि क्या यह आबादी हमेशा युवा बनी रहेगी ? उम्र बढ़ना जीवन की नियति है, जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। विभिन्न शोधों के अनुसार साठ वर्ष तथा उससे ज्यादा उम्र में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग आदि कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बढ़ती उम्र और घटती प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों का एक प्रमुख कारक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की % बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याएं % नामक एक रपट में बताया गया है कि 25 फीसद भारतीय बुजुर्ग अवसाद में जी रहे हैं, 33 फीसद गठिया या हड्डी के रोग से ग्रस्त हैं, 40 फीसद को रक्ताल्पता है, गांवों में 10 और शहरों में 40 फीसद को मधुमेह है, 10 फीसद कम सुनने संबंधी समस्या से गुजर रहे हैं। गांवों में 33 फीसद तो शहरों में 50 फीसद को हाइपरटेंशन है, करीब 50 फीसद की नजर कमजोर है, 10 फीसद भारतीय बुजुर्ग कहीं न कहीं गिरकर अपनी कोई न कोई हड्डी तुड़वा बैठते हैं, तो 33 फीसद पाचन तंत्र के विकार से जूझ रहे हैं। पीढ़ी अंतराल और जीवन-शैली में बदलाव के कारण बुजुर्ग व्यक्ति खुद अलगाव और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। आर्थिक साम्राज्यवाद, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और बढ़ते उद्योगीकरण ने भी आज बुजुर्गों को हाशिये पर धकेलने का काम किया है टूटते संयुक्त परिवारों के कारण घर के बड़े बुजुर्ग एकाकी जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वह घर स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता है। इसके बावजूद बहुत से परिवारों में बुजुर्गों को निरंतर अपने ही परिजनों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है ऐसे परिजनों को इस बात का आभास कराया जाना बेहद जरूरी है कि आज के युवा भी आने वाले समय में वृद्ध होंगे जीवन में हम आज जो भी हैं, अपने घर के बुजुर्गों की बदौलत ही हैं, जिनके व्यापक अनुभवों और शिक्षाओं से हम जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार करने में सक्षम होते हैं। ऐसे में अगर बुजुर्गों को अपनापन और उचित मान-सम्मान दिया जाए, उनकी पसंद-नापसंद का खयाल रखा जाए, तो वे घर के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। उम्र की ढलती सांझ में न केवल परिवार के सदस्यों, बल्कि समाज को भी उपेक्षित करने के बजाय उनका संबल बनने का प्रयास करना चाहिए।

संपादकीय
चिंतन-मनन

डिजिटल युग में दिवाली कैसे मनाई जाए

विजय गर्ग

दीपावली, प्रकाशों का त्योहार, हमेशा बुराई पर भलाई की जीत, अंधेरे पर रोशनी और अज्ञानता पर ज्ञान का प्रतीक रहा है। यद्यपि दिवाली का सार अपरिवर्तित है, लेकिन आज के डिजिटल युग में इसका जश्न मनाने का तरीका तेजी से विकसित हो रहा है। प्रौद्योगिकी ने त्योहार को नए तरीकों से उजागर किया है - परिवारों को करीब लाने, खुशी को तेजी से फैलाने और परंपराओं को पहले की तुलना में अधिक नवीन और समावेशी बनाने।

आभासी एकता

दूरी अब उत्सव की भावना को मंद नहीं करती। दुनिया भर में फैले परिवार अब वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ते हैं, वर्चुअल डायस साझा करते हैं और यहां तक कि ऑनलाइन गेम भी एक साथ खेलते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रियजनों को एक ही पूजा का हिस्सा बनने की अनुमति देते हैं, वही अग्निशमन प्रदर्शन देखते हैं और वास्तविक समय में हार्दिक इच्छाओं का आदान-प्रदान करते हैं - स्क्रीन साझा खुशी के खिड़कियों में बदल जाते हैं।

पर्यावरण के अनुकूल और स्मार्ट उत्सव

डिजिटल युग जागरूकता भी बढ़ा रहा है। ई-आमंत्रण रचनात्मक डिजाइनों और एनिमेशन के माध्यम से व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ते हुए पेपर्स कार्ड की जगह लेते हैं। प्रदूषित करने वाले शोरबाज के बजाय, लोग अब आभासी अग्निशमन या रोशनी देने वाली एलईडी दीपक का आनंद लेते हैं जो सुरक्षित और टिकाऊ दोनों होते हैं। प्रौद्योगिकी हमें दिवाली की चमक को कम किए बिना जिम्मेदार ढंग से मनाने में मदद करती है।

खरीदारी और उपहार ऑनलाइन जाएं

लंबी कतारें और भीड़ भरे बाजार खत्म हो गए हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उत्सव की खरीदारी को आसान और रोमांचक बना देते हैं - जातीय परिधान से लेकर आपके दरवाजे पर उपलब्ध कराई गई हस्तनिर्मित सजावट तक। डिजिटल वॉलेट और त्वरित उपहार विकल्प, जैसे कि ई-वॉचर्स या कस्टम वीडियो ग्रीटिंग्स ने उपहारों का आदान-प्रदान करना आसान और रचनात्मक बना दिया है।

डिजिटल रंगोलिस और रचनात्मक अभिव्यक्ति

रंगोली कला ने हमारे फोन और टैबलेट के लिए एक नया कैनवास पाया है। ऐप्स और सोशल मीडिया लोगों को दुनिया भर में अपने डिजिटल रंगोलिस, दीया सेल्फी और उत्सव के क्षणों को डिजाइन करने और साझा करने की अनुमति देता है। #डिजिटल दिवाली और #इकोफ्रेंडली फेस्टिवल जैसे हैशटैग ने सोशल मीडिया को उत्सव की गैलरी में बदल दिया है।

परंपरा और प्रौद्योगिकी को संतुलित करना

जैसे-जैसे हम गैजेट्स और ऐप्स को अपनाते हैं, दिवाली की भावना न खोना महत्वपूर्ण है - एकजुटता, कृतज्ञता और करुणा। एक वास्तविक दीया को उजागर करना, पड़ोसियों के साथ मिठाई साझा करना और जरूरतमंदों की मदद करना हमें याद दिलाता है कि त्योहार सभी चीजों से ऊपर मानव संबंध हैं।

एआई-रेडी स्कूल: आज कल की आदतें सिखाना

विजय गर्ग

दुनिया ऐसे युग में प्रवेश कर रही है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब एक दूरस्थ विचार नहीं बल्कि दैनिक वास्तविकता है। हमारे फोन पर ऐप से लेकर उन प्रणालियों तक जो व्यवसायों और सरकारों को शक्ति प्रदान करती हैं, ऐआई हमारा जीवन, काम और सीखने का तरीका आकार दे रही है। इस संदर्भ में, स्कूलों की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि छात्रों को ऐसी आदतें, कौशल और मानसिकता के साथ तैयार करना भी है जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर देगी। एक एआई-तैयार स्कूल ऐसा है जो इस मिशन को अपनाता है।

स्कूल को "एआई-तैयार" क्या बनाता है?

एआई के लिए तैयार होने का मतलब केवल स्मार्ट बोर्ड या कोडिंग कक्षाएं होना नहीं है। इसका अर्थ है

स्मृति के बारे में महत्वपूर्ण सोचः छात्रों को केवल तथ्यों की याद रखने के बजाय जानकारी का विश्लेषण, प्रश्न और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

डिजिटल और एआई साक्षरताः छात्रों को यह सिखाना कि एआई कैसे काम करता है, इसके लाभ और जोखिम, ताकि वे इसका बुद्धिमानी से उपयोग कर सकें।

नैतिक जागरूकताः बच्चों को प्रौद्योगिकी में निष्पक्षता, गोपनीयता और पूर्वाग्रह पर विचार करने में मदद करना। कल की दुनिया में न केवल कुशल उपयोगकर्ताओं, बल्कि नैतिक निर्णय लेने वालों की भी आवश्यकता होगी।

अनुकूलनशीलता और रचनात्मकताः तेजी से बदलती हुई दुनिया में सीखने, अनलर्निंग और नवाचार करने की क्षमता किसी भी तकनीकी कौशल से अधिक मूल्यवान होगी।

आज कल की आदतें सिखाना

स्कूल में बनने वाली आदतें जीवन भर रहती हैं। एक एआई-तैयार स्कूल इस पर केंद्रित है

दैनिक अभ्यास के रूप में जिज्ञासा - प्रश्न तैयार करना, कई दृष्टिकोणों का पता लगाना और प्रयोग को अपनाना।

मनुष्यों और मशीनों के साथ सहयोग - सहकर्मियों के बीच टीमवर्क को मजबूत करते हुए सीखने में सहायता करने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग करना।

निरंतर शिक्षण - यह मानसिकता विकसित करना कि परीक्षाओं के बाद शिक्षा रुकती नहीं है, बल्कि जीवन भर विकसित होती रहती है।

जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता - छात्रों को उनकी सीमाओं के बारे में जागरूक रहते हुए समस्या समाधान के लिए ऐआई का उपयोग करने की दिशा।

यह क्यों मायने रखता है

कल का कार्यस्थल अलग होगा, लेकिन कल के नागरिक और भी भिन्न होंगे। जो बच्चे आलोचनात्मक ढंग से सोचना सीखते हैं, एआई के साथ जिम्मेदारीपूर्वक काम करते हैं और परिवर्तन का सामना करने में लचीला रहते हैं वे केवल एआई युग को नहीं बचेंगे - वे इसका नेतृत्व करेंगे।

साझा जिम्मेदारी

एआई के लिए तैयार स्कूल बनाना केवल शिक्षकों का काम नहीं है। माता-पिता, नीति निर्माताओं और समुदायों को भी ऐसे वातावरण बनाने में शामिल होना चाहिए जहां छात्र समृद्ध हो सकें। शिक्षक प्रशिक्षण, अद्यतन पाठ्यक्रम और सुलभ प्रौद्योगिकी में निवेश महत्वपूर्ण होगा मूलतः, एआई-तैयार स्कूल शिक्षक या अंतहीन कोडिंग पाठों के लिए रोबोट नहीं है। यह बच्चों को उन मूल्यों, आदतों और कौशल के साथ तैयार करने के बारे में है जिनकी उन्हें ऐआई द्वारा आकार देने वाले भविष्य में आवश्यकता होगी। आज कल की आदतों को सिखाते हुए, हम उन्हें कल की कहानी लिखने के लिए उपकरण देते हैं - एक जो बुद्धि, जिम्मेदारी और रचनात्मकता द्वारा निर्देशित है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

कहानी:मां का घर

विजय गर्ग

'संजू ओ संजू, देखो तो तुम्हारा लाडला तुम्हारे लिए कितना रो रहा है।' दिनेश ने ड्राइंग रूम से ही आवाज लगाई। 'ओफ हो। तुम भी न बाथरूम में थी। चैन से कुछ भी नहीं कर सकती। अभी जनाब को मेरी जरूरत है, इसलिए रो रहे हैं मेरे लिए। जब इन्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तो साहबजादे पूछेंगे भी नहीं। तब मां की याद कहां आएगी।' संजू बाथरूम से निकल कर नैपकीन से हाथ पोंछते हुए सहज भाव से बोली।

दिनेश, संजू की बात सुनकर एकदम से संजीदा हो गया। उसके सामने उसकी मां का लाचार चेहरा घूम गया। उसके माता-पिता ने भी तो इतने ही कष्ट उठाए होंगे न पिताजी की पंद्रह हजार की निजी नौकरी थी। ओवरटाइम कर थके हुए पिता का चेहरा उसके सामने घूम गया उतनी कम तनख्वाह में पिताजी ने चार जनों के परिवार को कितने कष्ट पाला होगा, ये वही जानते होंगे। पिताजी के परलोक सिधारने बाद मां कितनी अकेली और लाचार" गई है। ऐसे में एक लाचार मां को अपने पास न रखने का विचार कितना गलत है। माना मेरा बड़ा भाई मां को अपने साथ य नहीं रखना चाहता, तो क्या मेरा यह फर्ज नहीं बनता कि मैं मां को प्रेम से अपने पास रखूं। मां को अपने पास रख लेने से मेरा कौन सा खजाना खाली हो जाएगा। ये तो प्रेम की बात है, श्रद्धा की बात है। फिर ये ईर्ष्या कहां से आ गई थी मेरे मन में।

दिनेश पुरानी यादों में खो गया मां बड़े भैया के घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, , फिर र भी संजू के दबाव में आकर मैंने मां को भैया के घर भेज दिया। । एक बार र फोन करके मां का हाल ले लेता हूं'। सोचते हुए वह अपने भैया को फोन लगाने लगा।

"फोन करते देख संजू ने कहा, 'मां को फिर से अपने पास रखने का इरादा है क्या ? मैं नहीं रखने वाली तुम्हारी मां को काम-धाम तो कुछ करती नहीं, ऊपर से काम बढ़ा देती हैं।' संजू खीज भरे स्वर में बोली 'संजू ये मत भूलो कि बुढ़ापा हम पर भी आएगा। अगर हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करें तो हमें कैसा लगेगा।' दिनेश बोला।

'जो भी हो, मां को रखने की जिम्मेदारी केवल हमारी है क्या। उनके एक बेटा बहू और भी तो है। अरे हमारे पास तो इतनी आमदनी भी नहीं है, उस पर पांच प्राणियों का खर्च उनको भी रखकर हम और कष्ट उठाना नहीं चाहते। हर महीने हजारों रुपए तो उनकी दवाई में खर्च हो जाते थे।' संजू चिढ़कर बोली । ! बस भी करो मां पर कितने पैसे खर्च होते थे, बड़ा हिसाब रखा है तुमने। कोई भी मां-बाप अपने बच्चों की परवरिश कितने मुश्किल से करते हैं यह अहसास तुम्हें मां बनने के बाद भी नहीं हुआ।' दिनेश क्रोध से तमतमा कर बोला। दिनेश के सामने अपनी मां का लाचार चेहरा घूम रहा था।

""संजू "मैं कहां जाऊंगी बेटा ? रमेश की बीवी तो मुझे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती। मेरे पति नहीं रहे, और तुम लोग भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं बूढ़ी कहां-कहां धक्के खाती फिरुंगी।' जाते समय मां बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। * अब मैं क्या करूं मां ? तुम्हारी और संजू के बीच पटती ही नहीं है और फिर मेरी आमदनी भी इतनी नहीं है कि तुम्हारी दवाइयों का खर्च उठा सकूं।' दिनेश थोड़ा सकुचाते हुए बोला 'वाह बेटा हमने तुम दोनों भाइयों को कितने कष्ट से पाला। खुद तकलीफ सहे, पर तुम दोनों भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने दी और आज मुझ अकेली का खर्च उठाने की ताकत तुम दोनों भाइयों में से किसी को नहीं है, अब तुम्हें मां नहीं पत्नी की जरूरत है।

करवा चौथः परंपरा, प्रेम और पितृसत्ता के बीच

(प्रेम, आस्था और समानता के बीच झूलता एक पर्व — जहाँ परंपरा भी है, और बदलाव की दस्तक भी।)

करवा चौथ भारतीय संस्कृति का एक लोकप्रिय पर्व है, जिसमें विवाहित महिलाएँ अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हालांकि इसकी परंपरा प्रेम और समर्पण से जुड़ी है, लेकिन आधुनिक समाज में यह त्यौहार समानता और साझेदारी के भाव से मनाया जाने लगा है। अब कई पुरुष भी यह व्रत रखते हैं। यह बदलाव बताता है कि करवा चौथ केवल पति की लंबी उम्र का प्रतीक नहीं, बल्कि रिश्तों में आपसी सम्मान, प्रेम और विश्वास का उत्सव भी है। परंपरा तभी सार्थक है, जब उसमें आत्मा के साथ-साथ समय की समझ भी हो।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को जब शाम का सूरज डूबता है, तो भारत के कोने-कोने में सजी-संवरी महिलाएं थाली में दीप, छलनी और करवा सजाकर चाँद के दर्शन करती हैं। उनके माथे पर लाल बिंदी, हाथों में मेंहदी, आँखों में इंतज़ार और होठों पर एक ही सवाल— "चाँद निकला क्या?" यह दृश्य भारतीय संस्कृति की सुंदरता का प्रतीक भी है और उसकी गहराई में छिपे सामाजिक अर्थों का आईना भी।

करवा चौथ का व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएँ अपने पति की दीर्घायु के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। परंपरा के अनुसार यह व्रत सुहाग की स्थिरता और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, और दिनभर की तपस्या के बाद जब चाँद निकलता है तो पत्नी छलनी से पति का चेहरा देख कर व्रत तोड़ती है।

लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह व्रत सिर्फ प्रेम और आस्था की अभिव्यक्ति है या समाज की पितृसत्तात्मक जड़ों में गहरे धंसा एक प्रतीक?

भारतीय समाज में स्त्री के जीवन को "सुहाग" से जोड़ा गया है—उसकी खुशी, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी पहचान तक। विवाह के बाद उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका पति माना गया, और उसकी मृत्यु को अभिशाप समझा गया। ऐसे में करवा चौथ जैसे व्रत स्त्री के समर्पण, त्याग और सहनशीलता का उत्सव बन गए। लेकिन क्या यह प्रेम का उत्सव है या स्त्री के अस्तित्व को पति की उम्र के साथ बाँध देने का सांस्कृतिक औचित्य?

आज की पढ़ी-लिखी स्त्री जब करवा चौथ का व्रत रखती है, तो उसके कारण परंपरागत नहीं भी हो सकते। कई महिलाओं के लिए यह पति के प्रति प्रेम का, साथ निभाने का, रिश्ते में सामंजस्य का प्रतीक बन चुका है। वहीं कई पुरुष भी अब पत्नी के साथ समान भाव से व्रत रखने लगे हैं—यह बदलाव सकारात्मक है। परंतु यह भी उतना ही सच है कि करवा चौथ आज एक "कल्चरल इवेंट" बन गया है—टीवी धारावाहिकों, फिल्मों और सोशल मीडिया पर यह व्रत जितना "ग्लैमरस" दिखाया जाता है, उतनी ही गहराई में उसका मूल अर्थ खोता जा रहा है।

कभी यह व्रत गाँव की औरतों के बीच अपनापन और सहयोग का प्रतीक था। महिलाएँ एक-दूसरे के घर जातीं, मिट्टी के करवे (घड़े) में जल भरतीं, गीत गातीं— "करवा चौथ का व्रत है भाई, करवा लाना भूली न जाई।" यह त्यौहार उनके लिए आपसी मिलन का अवसर था, जहाँ वे जीवन की तकलीफ़ों को साझा करतीं। पर अब यह व्रत सोने के करवे, महंगे साज-श्रृंगार और डिजाइनर साड़ियों का प्रदर्शन बन गया है। उपवास के बजाय अब "इंस्टा रील्स" का युग है—जहाँ सजना-संवरना ही मुख्य उद्देश्य बन गया है।

फिर भी, परंपराओं को केवल अंधविश्वास कहकर नकार देना भी उचित नहीं। हर संस्कृति की अपनी आत्मा होती है। करवा चौथ के पीछे जो भाव है—प्रेम, समर्पण और आस्था का—उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम परंपरा को आधुनिक दृष्टि से देखें। आज जब हम समानता, स्वतंत्रता और पारस्परिक सम्मान की बात करते हैं, तो यह व्रत भी एकतरफा नहीं रहना चाहिए। यदि पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो पति भी पत्नी की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए समान भाव से प्रार्थना करे—यही सच्चा प्रेम और समानता है।

दिलचस्प बात यह है कि करवा चौथ का धार्मिक या पौराणिक आधार उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि इसके लोकप्रचलन का प्रभाव। "करवा" यानी मिट्टी का घड़ा, जो प्राचीन भारत में जल का प्रतीक था, और "चौथ" यानी चतुर्थी का दिन। कुछ विद्वानों के अनुसार यह व्रत सैनिक परिवारों की परंपरा से जुड़ा था—जब पति युद्ध पर जाते थे, तो पत्नी उनकी सुरक्षित वापसी के लिए यह व्रत रखती थी। वहीं कुछ मान्यताएँ कहती हैं कि यह महिलाओं के बीच सामाजिक एकता बढ़ाने का माध्यम था। यानी इस त्यौहार का मूल भाव केवल पति की आयु से नहीं, बल्कि स्त्री के सामाजिक सहयोग से भी जुड़ा था।

आधुनिक समाज में करवा चौथ की व्याख्या के कई अर्थ हैं। एक ओर यह प्रेम का उत्सव है, तो दूसरी ओर यह स्त्री पर "आदर्श पत्नी" बनने का सामाजिक दबाव भी। यह द्वंद्व हमें सोचने पर मजबूर करता है—क्या हर प्रेम का प्रमाण त्याग से ही मापा जाएगा? क्या भूखे रहकर ही सच्ची निष्ठा सिद्ध होती है? और क्या यह परंपरा पति-पत्नी के बीच समान संबंधों का उत्सव बन पाई है या अब भी "पति-प्रधानता" का ही प्रतीक है?

2050 तक कक्षाएं क्यों गायब हो सकती हैं, और भारत को अब क्या करना चाहिए

विजय गर्ग

पारंपरिक कक्षा मॉडल 2050 तक अप्रचलित हो सकता है, ऐआई के लिए धन्यवाद। भारत में, जहां कठोर परीक्षाएं अभी भी शासन करती हैं, यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतावनी है। प्रश्न यह हैः क्या हम विकसित होंगे, या इस महान शिक्षा क्रांति में पीछे रह जाएंगे?

2050 तक, आपका बच्चा कक्षा में नहीं रहेगा। कम से कम, जिस तरह आप इसे याद करते हैं। लेकिन यह बात है, यह क्रांति उतनी बुरी नहीं हो सकती जितनी आप इसे बनाते हैं।

"कक्षा में हर किसी को एक ही बात करने की आवश्यकता, उसी तरह से मूल्यांकन किया जाना, पूरी तरह पुरानी लगती है गार्डनर ने तर्क दिया कि सीखने का भविष्य बच्चों से भरे कक्षाओं में नहीं होगा जो एक ही अध्याय को याद करते हैं और उसी गति से। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि स्कूल अपने शुरुआती वर्षों में केवल 'मूल बातें' सीखेंगे

उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में सीखने का अंत नहीं होगा, तथा यह भी कहते हैं कि कोई भी मूल्यांकन अंतिम परीक्षा नहीं होगी। उनके अनुसार, 2050 तक छात्रों को उनकी यादों पर नहीं बल्कि उन चीजों पर चिह्नित किया जाएगा जो वे कल्पना और निर्माण कर सकते हैं।

यदि आप हाल ही में औसत भारतीय स्कूल गए हैं, तो आपको पता है कि यहां शिक्षा केवल पुरानी नहीं है, यह टूट गई है। बच्चों को आज्ञाकारिता में शामिल किया जाता है, उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर याद रखना सिखाया जाता है जिन्हें वे मुश्किल से समझते हैं और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उठाया जाता है जो अब मौजूद नहीं है।

हालांकि, कक्षा के दरवाजे पर एआई की दस्तक देने से वैश्विक शिक्षा बातचीत बदल रही है। अब, भारत सुनेंगे? के रूप में मानक परीक्षाएं होती हैं? यह निश्चित रूप से गायब हो जाएगा। इसके स्थान पर अधिक व्यक्तिगत, अन्वेषणात्मक और मार्गदर्शक-निर्देशित सीखने की संभावना है।

और यह भविष्यवादी भी नहीं है। नोएडा में एक 13 वर्षीय लड़का पहले से ही यूट्यूब के निर्माता से स्पेनिश सीख रहा है, रेडडिट से एआई आर्ट टूल उठाता है और अपने टीचर की तुलना में बेहतर संकेत लिखता है। इस बीच, उत्तर प्रदेश के एक गांव स्कूल में उनका चचेरा भाई अभी भी टूटे हुए ब्लैकबोर्ड पर घटाव सीख रहा है।

यही भारत की समस्या है। कि शिक्षा प्रणाली पीछे या दोषपूर्ण नहीं है, यह द्विपक्षीय है। जबकि कुछ आगे बढ़ रहे हैं, बाकी 1980 के दशक में फंसे हुए हैं।

भारत की स्कूल अपनी समाप्ति तिथि पर पहुंच गई है इसे स्पष्ट रूप से कहने के अलावा कोई तरीका नहीं हैः भारतीय शिक्षा प्रणाली को रचनाकारों, महत्वपूर्ण विचारकों और निश्चित रूप से नवप्रवर्तनकर्ताओं का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।

हमने एक औपनिवेशिक मॉडल विरासत में लिया और इसे नौकरशाही परिशुद्धता के साथ मापा, जिसमें मानक शब्दकोश, कठोर आयु-आधारित ग्रेड, भाग्य बोर्ड शामिल हैं। प्रणाली ने अंततः रूट को पुरस्कृत करना सीखा, किसी भी प्रकार के विचलन को दंडित किया और अप्रासंगिकता से अधिक असफल होने का डर था।

और फिर भी जब छात्र वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं होते हैं, या वे वास्तविक सीखने के लिए ऑनलाइन "एडटेक" सामग्री की ओर भाग जाते हैं।

हरियाणा के एक निजी विश्वविद्यालय की अध्यक्ष अनिशा धवन कहती हैं, "शिक्षा का भविष्य सामग्री वितरण नहीं है।₹ "यह जिज्ञासा, नैतिकता, अंतर-अनुशासनात्मकता के बारे में है

धवन का मतलब यह था कि एआई यहां सिर्फ एक उपकरण नहीं है। यह एक दर्पण है, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारी वर्तमान प्रणाली कितनी पुरानी है।

हार्वर्ड का दृष्टिकोण एक जागृत कॉल है हार्वर्ड में, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चर्चा की कि कैसे कल के छात्र स्वयं "काम" नहीं करेंगे - वे एआई टीमों का प्रबंधन करेंगे, रचनात्मक परियोजनाओं को निर्देशित करेंगे और निर्णय लेंगे जहां एआई अपनी सीमा तक पहुंचती है।

"सिक्स फेसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन" के सह-लेखक एंथिया रॉबर्ट्स ने इसे खूबसूरती से कहाः "आप अभिनेता, एथलीट के कोच और लेखक का संपादक बन जाते हैं संक्षेप मेंः मनुष्य कर्ताओं से ऑर्केस्ट्रेटरों तक चले जाएंगे। नैतिक तर्क, रचनात्मक संश्लेषण और निर्णय लेने जैसी कौशल पाठ्यपुस्तकों की परिभाषाओं से अधिक महत्वपूर्ण होंगे।

क्रांति पहले से ही यहां है हार्वर्ड फोरम ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सिर्फ फेसलिफ्ट से गुजर रही नहीं है बल्कि यह तथ्य भी है कि वह पहले से ही यहां है और केवल बढ़ने वाली है।

गार्डनर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां छात्र केवल कुछ शुरुआती वर्षों को "मूल बातें" पढ़ते हैं, लिखते हैं, गणित करते हैं, शायद कोडिंग करते हैं और फिर परियोजनाओं, स्व-निर्देशित खोजों और एआई द्वारा सहायता प्राप्त सीखने के मार्गों पर केंद्रित होते हैं।

फिर एक आकार के सभी कक्षाओं के पुराने मॉडल का क्या होगा, जिसमें गेटकीपर के रूप में मानक परीक्षाएं होती हैं? यह निश्चित रूप से गायब हो जाएगा। इसके स्थान पर अधिक व्यक्तिगत, अन्वेषणात्मक और मार्गदर्शक-निर्देशित सीखने की संभावना है।

और यह भविष्यवादी भी नहीं है। नोएडा में एक 13 वर्षीय लड़का पहले से ही यूट्यूब के निर्माता से स्पेनिश सीख रहा है, रेडडिट से एआई आर्ट टूल उठाता है और अपने टीचर की तुलना में बेहतर संकेत लिखता है। इस बीच, उत्तर प्रदेश के एक गांव स्कूल में उनका चचेरा भाई अभी भी टूटे हुए ब्लैकबोर्ड पर घटाव सीख रहा है।

यही भारत की समस्या है। कि शिक्षा प्रणाली पीछे या दोषपूर्ण नहीं है, यह द्विपक्षीय है। जबकि कुछ आगे बढ़ रहे हैं, बाकी 80 के दशक में फंसे हुए हैं।

भारत की स्कूल अपनी समाप्ति तिथि पर पहुंच गई है इसे स्पष्ट रूप से कहने के अलावा कोई तरीका नहीं हैः भारतीय शिक्षा प्रणाली को रचनाकारों, महत्वपूर्ण विचारकों और निश्चित रूप से नवप्रवर्तक बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।

हमने एक औपनिवेशिक मॉडल विरासत में लिया और इसे नौकरशाही परिशुद्धता के साथ मापा, जिसमें मानक शब्दकोश, कठोर आयु-आधारित ग्रेड, भाग्य बोर्ड शामिल हैं। प्रणाली ने अंततः रूट को पुरस्कृत करना सीखा, किसी भी प्रकार के विचलन को दंडित किया और अप्रासंगिकता से अधिक असफल होने का डर था।

और फिर भी जब छात्र वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं होते हैं, या वे वास्तविक सीखने के लिए ऑनलाइन "एडटेक" सामग्री की ओर भाग जाते हैं।

हरियाणा के एक निजी विश्वविद्यालय की अध्यक्ष अनिशा धवन कहती हैं, "शिक्षा का भविष्य सामग्री वितरण नहीं है।₹ "यह जिज्ञासा, नैतिकता, अंतर-अनुशासनात्मकता के बारे में है

धवन का मतलब यह था कि ऐआई यहां सिर्फ एक उपकरण नहीं है। यह एक दर्पण है, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारी वर्तमान प्रणाली कितनी पुरानी है।

हार्वर्ड का दृष्टिकोण एक जागृत कॉल है हार्वर्ड में, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चर्चा की कि कैसे कल के छात्र स्वयं "काम" नहीं करेंगे - वे एआई टीमों का प्रबंधन करेंगे, रचनात्मक परियोजनाओं को निर्देशित करेंगे और निर्णय लेंगे जहां एआई अपनी सीमा तक पहुंचती है।

"सिक्स फेसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन" के सह-लेखक एंथिया रॉबर्ट्स ने इसे खूबसूरती से कहाः "आप अभिनेता, एथलीट के कोच और लेखक का संपादक बन जाते हैं संक्षेप मेंः मनुष्य कर्ताओं से ऑर्केस्ट्रेटरों तक चले जाएंगे। नैतिक तर्क, रचनात्मक संश्लेषण और निर्णय लेने जैसी कौशल पाठ्यपुस्तकों की परिभाषाओं से अधिक महत्वपूर्ण होंगे।

में क्या करना चाहिए यदि हम ऐसी पीढ़ी के लिए शिक्षा की पुनः कल्पना करने का संघर्ष करना चाहते हैं जो AI के साथ बढ़ेगी - इसके बाद नहीं - तो हमें मूल परिवर्तनों की आवश्यकता है जिनमें केवल नीतिगत संशोधन और समिति रिपोर्ट शामिल न हों। लेकिन वास्तविक परिवर्तन.

ए) यह सब इस बात से शुरू होता है कि हम अपने शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षित करते हैं। ऐसी क्रांति की ओर कदम उठाने के लिए हमारे शिक्षण कार्यबल को "एआई-स्विथ मोटनर" बनने के लिए पुनः प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। भविष्य के लिए तैयार शिक्षक कोई सामग्री वितरक नहीं होगा बल्कि एक जिज्ञासा कोच, नैतिकता एंकर, परियोजना गाइड होगा।

लेकिन यह रातोंरात नहीं होगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए निवेश, गरिमा और गंभीर उन्नयन की आवश्यकता होगी।

बी) हमें मूल्यांकन मॉडल के लिए वर्तमान वर्दी परीक्षाओं को छोड़ देना होगा। एक आकार के सभी बोर्ड छात्रों को उस तरह से बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हैं जैसा कि हम चाहते थे। इसके बजाय, एआई-संचालित शैक्षिक मूल्यांकन जो विकास को ट्रैक करते हैं, न कि केवल स्कोर।

ग) हमें सबसे महत्वपूर्ण बात पर लाता हैः पहले डिजिटल अंतर को ठीक करें। यदि हमारे आधे छात्र स्थिर वाई-फाई या डिवाइस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो कोई ऐआई क्रांति नहीं हो सकती। इसे कम बोझिल बनाने के लिए, सामुदायिक शिक्षण केंद्र और ऑफलाइन-प्रथम उपकरण समावेशन की आधारशिला होना चाहिए।

डी) शैक्षणिक स्तरों को समाप्त करना। क्या हम अपने छात्रों को अपनी सीखने की यात्राएं निर्धारित करने दे सकते हैं? उन्हें "कोडिंग के साथ इतिहास मिश्रण" करने की अनुमति देते हुए, "साहित्य के साथ जलवायु विज्ञान", संक्षेप में, अंतर-अनुशासनात्मक क्रेडेंशियल्स को सक्षम करें जिन पर नियोक्ता भरोसा करते हैं।

ई) आत्मनिर्भरता वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमें पश्चिम के मॉडल की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय शिक्षा को अपनी बहुलवादी, भाषाई और दार्शनिक समृद्धि का उपयोग करना चाहिए। एआई को हमारे मूल्यों का विस्तार करना चाहिए, न कि केवल दूसरों के।

क्या भारत कूद जाएगा या नहीं? यह कठिन सत्य हैः एआई भारत की सहमति के साथ या उसके बिना शिक्षा को बदल देगा। प्रश्न यह है कि क्या हम परिवर्तन को आकार देंगे - या इससे प्रेरित होंगे। भारत में जनसंख्या, डिजिटल बुनियादी ढांचा और भविष्य के लिए कूदने की सांस्कृतिक इच्छा है। हमारे पास हमें रोकने के लिए निष्क्रियता, नौकरशाही और परीक्षा की जुनून भी है।

हार्वर्ड फोरम में, हॉवर्ड गार्डनर ने निष्कर्ष निकाला, "शिक्षा को अच्छे स्कूल या नौकरी से परे एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है भारत में, हमें इसे सुनने की तत्काल आवश्यकता थी।

क्योंकि 2050 तक यह बात नहीं होगी कि किस बोर्ड की परीक्षा में कौन शीर्ष पर होगा। यह इस बारे में होगा कि किसने सोचा - एआई के साथ, ऐआई से परे और कभी-कभी इसके खिलाफ भी।

सावधानी ही सुरक्षा: मिलावट से बचाएं त्योहारों की खुशियां

दीपावली का त्योहार नजदीक है और दीपावली का (त्योहारी सीजन) त्योहार आते ही देशभर के बाजारों में बहार सी छा जाती है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों, नमकीन, सूखे मेवों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने से व्यापारिक गतिविधियों में भी अभूतपूर्व तेज़ी आती है, लेकिन इसी समय बाज़ार में बड़ी संख्या में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हुए खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट कर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। खाद्य पदार्थ मानव जीवन की मूल आवश्यकता हैं और इनमें मिलावट करना मानव स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।मिलावट आज समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गई है। खाद्य पदार्थों, दवाओं, दूध, मिठाई, तेल, मसालों यहाँ तक कि जीवन रक्षक चीज़ों में भी मिलावट का ज़हर घुल चुका है। यह न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि यह नैतिकता व मानवता की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। यह बहुत दुखद है कि आज हमारे देश में दूध, मसाले, मिठाई, तेल और घी में सबसे अधिक मिलावट पाई जाती है। त्योहारी सीजन में विशेष कर मिलावट का गंदा खेल देश में चलता है। मिलावटी खाद्य पदार्थों से अनेक बीमारियाँ फैलती हैं। अंत इस क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग को दुकानों , बाज़ार में नियमित जांच करनी चाहिए। उपभोक्ताओं को भी जागरूक होकर वस्तुएं खरीदनी चाहिए।मिलावट पर सख्त कानून और दंड से ही इस समस्या पर अंकुश लग सकता है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि यह एक सामाजिक अपराध भी है। दीपावली हिंदूओं का बड़ा और एक प्रमुख त्योहार है और दीपावली पर मिठाइयों में मिलावटी खोया, नकली घी, रंग और सुगंध का प्रयोग आम हो जाता है। दूध, पनीर, मावा और तेल में भी मिलावट के अनेक मामले सामने आते हैं। यह मिलावट कई बार इतनी खतरनाक होती है कि इससे फूड पॉइजनिंग, लीवर और किडनी से जुड़ी बीमारियाँ, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ भी हो सकती हैं। वास्तव में सच तो यह है कि मिलावट का जहर आज हर खाद्य वस्तु में घुलता जा रहा है और यह धीमे-धीमे मानव स्वास्थ्य पर कहर बरपा रहा है। नकली रंग, विभिन्न रसायन और मिलावटी तेल, घटिया सामग्री आज विभिन्न बीमारियों की जड़ बन रहे हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि लालच में की गई यह मिलावट समाज व देश के लिए बहुत ही घातक है। मिलावट रोकना हर नागरिक और प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है। दीपावली का त्योहार खुशी, उमंग, उल्लास और स्वास्थ्य का प्रतीक हैं, लेकिन मिलावटखोरी इन खुशियों पर ग्रहण लगा देती है। वास्तव में, इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। खाद्य सुरक्षा विभागों को त्योहारों से पहले विशेष अभियान चलाकर दुकानों, मिठाई बनाने वालों हलवाइयों/दुकानदारों और डेयरियों की सघन जांच करनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और जुर्माना लगाने से ही मिलावट पर अंकुश लगाया जा सकता है और समाज में डर का माहौल बनेगा। इसके साथ ही साथ बाजार में पारदर्शिता और प्रमाणित ब्रांडों को बढ़ावा देना होगा।साथ ही, उपभोक्ताओं को भी जागरूक रहना होगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी उत्पाद में मिलावट का संदेह हो तो, उसे यह चाहिए कि वह 'फूड सेफ्टी हेल्पलाइन' या स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना दें।मिलावट से बचने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि हम त्योहारों के दौरान खाद्य सामग्री घर पर ही तैयार करें। घर की बनी मिठाइयाँ और व्यंजन न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि उनमें स्नेह और आत्मीयता का स्वाद भी होता है। समाज में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मिलावट के खतरों से अवगत कराना आवश्यक है। विद्यालयों, मीडिया और सामाजिक संगठनों को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अंत में, संक्षेप में यही कहूंगा कि त्योहारों की सच्ची खुशी तभी संभव है जब हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। दीपावली की मिठास तभी सार्थक होगी जब बाजारों से मिलावट का अंधकार मिटे और शुद्धता, ईमानदारी तथा जिम्मेदारी का दीप हर दिल में जले। यही सच्चे अर्थों में 'स्वस्थ दीपावली' की कामना होगी।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर,

पीओके : गंभीर रणनीतिक भूल साबित होगी भारत में विलय

हरीश शिवनानी

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ने के साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को भारत में शामिल करने की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ रही है।कुछ उच्च-स्तरीय बयानों ने इस मुद्दे को नए सिरे से जीवंत कर दिया है।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही एक सार्वजनिक सभा में स्पष्ट कहा कि ₹पीओके हमारा है और बिना किसी आक्रामक कार्रवाई के यह भारत का हिस्सा बनेगा।₹ इसी क्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी बीकानेर में पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में दिखाया गया संयम अब दोहराया नहीं जाएगा। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या वह नक्शे में बने रहना चाहता है या नहीं। ये बयान भारतीय जनमानस को भी उद्वेलित कर रहे हैं। भारत का जनमानस आज भी 1948 में की गई उस ऐतिहासिक महाभूल को भुला नहीं पाया है जब पाकिस्तान के कश्मीर पर थोपे गए युद्ध में भारतीय सेना उसे खदेड़ रही थी पर नेहरु सरकार ने सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और भारतीय कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया, वही पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाता है। 1948 से भारतीयों का स्वप्न है कि पीओके को वापस भारत में मिलाया जाए।यह एक भावुक स्वप्न है लेकिन गहन विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि आज के दौर में पीओके को सैन्य या कूटनीतिक रूप से वापस लेना भारत के लिए एक गंभीर रणनीतिक भूल साबित होगी।

पीओके की जटिल और ख़स्ता आर्थिक परिस्थितियां, जनसांख्यिकीय,भू-राजनीतिक और सैन्य वास्तविकताएं भारत को लंबे समय तक जोख़मि में डाल सकती हैं।

पीओके की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि इसे भारत में शामिल करना देश की अर्थव्यवस्था पर एक भारी-भरकम बोझ डाल देगा।पीओके की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर है। वहाँ की जीडीपी प्रति व्यक्ति मात्र 1,200 डॉलर के आसपास है, जो भारत के राष्ट्रीय औसत (2,500 डॉलर) से भी कम है। भारत का अपना जम्मू-कश्मीर (जेएंडके) ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है।अनुमानित रूप से, पीओके के 55-60 लाख निवासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं पर प्रारंभिक निवेश ही 50,000 करोड़ रुपयए से अधिक का होगा। भारत, जो खुद वैश्विक मंदी और महंगाई से जूझ रहा है, इस क्षेत्र को संभालने में असमर्थ साबित होगा। आर्थिक पहलू के अलावा पीओके की जनसांख्यिकीय संरचना भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। 2017 की पाकिस्तानी जनगणना के अनुसार, पीओके की जनसंख्या लगभग 55 - 60लाख है। इनमें से 99 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम हैं, जिसमें पश्तून, बाल्टी और कश्मीरी समुदाय प्रमुख हैं। भारत पहले से ही कट्टरपंथी ताकतों से जूझ रहा है— नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और धारा 370 हटाने के बाद साम्प्रदायिक तनाव भी बरकरार हैं। पीओके के निवासियों को भारतीय नागरिकता देने पर वे सीमित संसाधनों वाले जेएंडके से बाहर निकलकर भारत के विभिन्न शहरों में फैल जाएंगे। इससे शहरी डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ जाएगा और वहाँ साम्प्रदायिक समस्याएं बढ़ेंगी। भारत में विलय के बाद ये समूह कट्टरपंथी राष्ट्र विरोधी संगठनों से जुड़ सकते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां बढ़ेंगी। यह न केवल हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण को तेज करेगा, बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन को भी जन्म देगा। जनसांख्यिकीय विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में भारत का जनसंख्या संतुलन 20 वर्षों में 15 प्रतिशत तक बदल सकता है, जो भविष्य में राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रीय एकता पर संकट का कारण बनेगा।

पीओके के भारत मे विलय से सैन्य और सुरक्षा जोखिम भी कम नहीं होंगे। पीओके क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ और अशांत पहाड़ी इलाका है। इसका भूभाग अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति और वर्तमान भू-राजनीतिक हालात के कारण एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बना रहेगा। इस क्षेत्र को स्थिर रखने के लिए एक स्थायी और विशाल सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता होगी। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार, पीओके को नियंत्रित करने के लिए भारत को अतिरिक्त एक लाख सैनिक तैनात करने पड़ेंगे, जिसका वार्षिक खर्च 30,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। वर्तमान में, भारत की सेना पहले से ही नियंत्रण रेखा पर तीन लाख सैनिकों के साथ व्यस्त है, और पीओके लेने पर यह एक अंतहीन आतंकवाद और युद्धक्षेत्र बन जाएगा।

बढ़ा हुआ सैन्य बोझ न केवल बजट को प्रभावित करेगा, बल्कि मानवीय हानि भी बढ़ाएगा। भारत की सैन्य क्षमता को फैलाने से पूर्वी लद्दाख (चीन सीमा) पर ध्यान कम होगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक होगा। यह मानने का भी कोई कारण नहीं है कि पीओके की आबादी का एक हिस्सा विलय का विरोध नहीं करेगा। भारतीय सेना और अर्ध-सैन्य बलों को न केवल बाहरी घुसपैठ, बल्कि एक नए आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। पीओके को लेने का सबसे बड़ा जोखिम भू-राजनीतिक है। यह क्षेत्र चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का केंद्र है, जो ग्वादर बंदरगाह से गिलगित तक फैला है। चीन ने यहां 60 बिलियन डॉलर निवेश किया है, और भारत का हस्तक्षेप बीजिंग को उकसाएगा।

पीओके लेने के लिए भारत की सैन्य कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय समुदाय आक्रामकता मानेगा। भारत की वर्तमान वैश्विक छवि—जो जी-20 और क्वाड से मजबूत हुई है—को ठेस पहुंचेगी। ज़ाहिर है, पीओके को वापस लेना भावुकता से प्रेरित है। पीओके का विलय केवल एक क्षेत्रीय विस्तार का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी गंभीर जोखिमों से भरा एक जटिल मुद्दा है। इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था पर एक नया, लंबे समय तक रहने वाला बोझ पड़ सकता है और देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक,रणनीतिक रूप से भी व्यावहारिक नहीं लगता।

मदरसे में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक जागरूकता पर ज़ोर

शम्स आगाज

नईदिल्ली: पसमांदा विकास फाउंडेशन के तत्वावधान में मदरसा अल-आफिया लिल-बनात, फिरोजपुर डहर, नगीना, नूह मेवात में एक क़ौमी तालीमी बेदारी कार्यक्रम आयोजित किया गया,जिसमें उलेमा, बुद्धिजीवी, महिला प्रतिनिधि और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

इस अवसर पर फाउंडेशन के निदेशक-मेराज राईन ने कहा कि उलेमा हमारी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि देश के उच्च धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को भी पसमांदा वर्ग को प्रतिनिधित्व का अवसर देना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है और उनमें से सबसे बड़ी संख्या पसमांदा मुसलमानों की है, लेकिन यह कड़वी सच्चाई समाज से छिपाई गई। मेराज राईन ने अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध को दलित मुसलमानों के साथ खुली नाइंसाफी बताते हुए कहा कि जितनी जातियां हिंदू समाज में हैं, लगभग उतनी ही जातियां मुसलमानों में भी हैं, लेकिन यह प्रचारित किया जाता है कि इस्लाम में जात-पात जैसी कोई बात नहीं है, (जबकि भारतीय मुसलमानों में यह जात-पात वायरस की तरह घुसा हुआ है) उन्होंने कहा कि हिंसा और भेदभाव का शिकार अधिकतर पसमांदा, ग़रीब तथा दलित मुसलमान ही होते हैं।

उन्होंने कहा कि फाउंडेशन की ₹₹क़ौमी तालीमी बेदारी₹₹ मुहिम को मदरसों से जोड़ने का उद्देश्य यह है कि मदरसों के छात्र बहुत बुद्धिमान होते हैं और अधिकतर गरीब परिवारों से आते हैं, इसलिए उनके लिए धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि वे हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकें।

उन्होंने मदरसे के जिम्मेदारों का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह मिशन तभी सफल होगा जब हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे।

फाउंडेशन की महिला निदेशक-निकहत परवीन ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि वे अपने माता-पिता की कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बनें। उन्होंने कहा कि शिक्षित महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो महिलाओं के प्रति समाज के पुराने और संकीर्ण विचारों को बदल सकती है।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों में तालीमी किट का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कारी असजद जुबैर कासमी (संरक्षक, पसमांदा विकास फाउंडेशन एवं अध्यक्ष-जामिया अरबिया शम्सुल उलूम,शाहदरा,दिल्ली) ने की, जबकि संचालन के फराइज़ मौलाना जाहिद आलम मजज़ाहिरी (अध्यक्ष-उलेमा टीम, पसमांदा विकास फाउंडेशन) ने निभाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मनोज कुमार, जिला खेल अधिकारी नूंह (हरियाणा) भी उपस्थित रहे।मनोज कुमार ने कहा कि मदरसों को धार्मिक और आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ खेल-कूद में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकें। कार्यक्रम में अशरफ खान, सैयद फ़र्रूख़ सेर, (गाइडेन्स बोर्ड) मौलाना रिज़वान क़ासमी (पूर्व शिक्षक, वक्फ़ दारुल उलूम देवबंद), मौलाना ग़ुफ़रान क़ासमी (संपादक, बसीरत ऑनलाइन, मुंबई), मुफ्ती वसीम अकरम क़ासमी (अध्यक्ष-उलेमा टीम, पीवीएफ) सहित कई अन्य उलमा-ए-कराम शामिल हुए।

काम के बाद घर लौट रही महिला के साथ रेल की पटरी पर बलात्कार

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

राउरकेला/भूबनेश्वर : राउरकेला पुलिस जिले के रघुनाथपल्ली थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 9 बजे एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। पुलिस ने इस घटना में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कोयलबैंक इलाके के काहनू चरण जेना (32) के रूप में हुई है। उसे मंगलवार शाम 7 बजे मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया जाएगहै ।पुलिस ने दो अन्य युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इसी तरह, पीड़ित महिला का बयान सुबह 11 बजे उसकी मेडिकल जांच के बाद अदालत में दर्ज किया गया। इस संबंध में रघुनाथपाली पुलिस स्टेशन में मामला (संख्या 564/25) दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, महिला पानपोस इलाके में घरेलू कामगार के रूप में काम करती है। गिरफ्तार आरोपी, हिरासत में लिए गए युवक और पीड़ित महिला एक-दूसरे को जानते हैं। सोमवार की रात, जब महिला लगभग 9 बजे काम के बाद घर लौट रही थी, आरोपी कान्हू चरण ने उसे बहला-फुसलाकर एसटीआई ओवरब्रिज, खारियाबहाल बस्ती रेलवे लाइन के पास उसके साथ बलात्कार किया। जब उसके साथियों ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, तो महिला किसी तरह वहां से भागने में सफल रही और लगभग 2:45 बजे रघुनाथपाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही। जहां एक आरोपी का अदालत में मुकदमा चलाया गया, वहीं अन्य दो से पूछताछ की जा रही है ।

बीएमसी की कुत्तों की गणना: लगभग 4.5 लाख रुपये खर्च, लेकिन कोई नतीजा नहीं

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : राज्य में पहली बार हम राजधानी भुवनेश्वर में कुत्तों की गणना करवा रहे हैं। इस पर लगभग साढ़े चार लाख रुपये खर्च हुए। लेकिन नतीजा शून्य। हालात ये हैं कि भुवनेश्वर महानगर निगम (बीएमसी) को आंकड़े देने में भी शर्म आ रही है। क्योंकि जो लोग जनगणना में लगे थे, वे कुत्तों की जनगणना ठीक से नहीं कर पाए।

बताया गया था कि राजधानी में लगभग 70,000 आवारा कुत्ते हैं। लेकिन जब गिनती हुई, तो कुत्तों की संख्या घटकर आधी रह गई। इसलिए, यह पता चलने पर कि गिनती सही ढंग से नहीं हुई, भुवनेश्वर महानगर निगम ने आंकड़े छिपाने शुरू कर दिए हैं। अधिकारी से पूछने पर उन्होंने कहा कि गिनती पूरी होने के बाद संख्याओं का मिलान किया जा रहा है, और जब यह पूरा हो जाएगा, तो वह आंकड़े दे देंगे। ऐसे में, कुत्तों की गिनती करके भुवनेश्वर महानगर निगम के अधिकारी किस खामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सवाल उठ रहा है। पिछले सितंबर में, बीएमसी ने दो चरणों में 67 वार्डों में कुत्तों की गिनती की थी।

पहले चरण में 18 से 21 सितंबर और दूसरे चरण में 22 से 25 सितंबर तक आवारा कुत्तों की गिनती की गई थी। इसके लिए प्रत्येक ज़ोन, वार्ड और वार्ड की गली के लिए 410 लोगों की एक टीम बनाई गई थी। पशु चिकित्सक की देखरेख में सफाई कर्मचारी, सफाई पर्यवेक्षक, सफाई निरीक्षक, एसएमटीए, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, सीओ, वार्ड अधिकारी आवारा कुत्तों की गणना में लगे हुए थे। सभी को इससे पहले तीन दिनों तक प्रशिक्षित किया गया था।

चूँकि कुत्ते सुबह अपनी जगह पर सोते हैं, इसलिए कुत्तों की गणना सुबह 5 बजे से 7 बजे तक की गई। कुत्तों की गणना का उद्देश्य कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करना और रेबीज, लेप्टोस्पायरोसिस, सड़क दुर्घटनाओं और पर्यावरण प्रदूषण जैसी संक्रामक बीमारियों को रोकना था। इस गणना से बीएमसी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या का एक डेटाबेस तैयार होता। महापौर और आयुक्त ने कहा कि एक स्थायी कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन कार्यक्रम विकसित किया जा सकता है और कुत्तों की नसबंदी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। इससे यह पता चल सकेगा कि किसने एंटी-रेबीज वैक्सीन ली है और किसने नहीं।

इस बीच, बुलाकुकुर की गणना पूरी हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारी जानकारी देने से कतरा रहे हैं। पूछने पर वे अलग-अलग अधिकारियों के हवाले से बता रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जब भुवनेश्वर नगर निगम ने पहले चरण में बुलाकुकुर की जनगणना की थी, तब बुलाकुकुरों की संख्या लगभग 39 हज़ार थी। लेकिन दूसरे चरण में यह संख्या काफ़ी कम हो गई थी। हालाँकि सटीक आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि यह संख्या लगभग 25 हज़ार रह गई थी। इसलिए, भुवनेश्वर नगर निगम के अधिकारी जानबूझकर यह जानकारी देने से बच रहे हैं। इस बीच, कहीं से बड़ाबाबू की ओर से एक अलिखित निर्देश है कि यह जानकारी मीडिया को न दी जाए। इसलिए, कोई भी यह जानकारी नहीं दे रहा है।

शीर्षक - ओ चंदा !

छुप करके बादलों की ओट में देखो तुम मत सताना,
ओ चंदा ! सुनो आज तुम थोड़ी जल्दी निकल आना ।

सजधज कर प्रियतमा मेरी बैठी हैं तुम्हारे इंतजार में,
रखा है करवा चौथ का निर्जल व्रत आज मेरे प्यार में,
सुबह से ही उसने कर रखी हैं धूमधाम से सारी तैयारी,
लाल चूड़ा पहना और हाथों में लगाई है मेहंदी प्यारी,
सांझ हो रही अमृत किरणों को तुम हम पर बरसाना,
ओ चंदा ! सुनो आज तुम थोड़ी जल्दी निकल आना ।

देखकर सजनी के चेहरे की चमक मैं इठला रहा हूँ,
ईश का धन्यवाद मैं ख़ुशी से ये जीवन बीता रहा हूँ,
ऑच मेरे इस जीवन पर तनिक कभी भी ना आएँ,
उसकी उम्र मुझे लग जाएँ माँगती वो कितनी दुआएँ,
दीप की लौ संग चालनी के बीच में प्रेम रंग छलकाना,
ओ चंदा ! सुनो आज तुम थोड़ी जल्दी निकल आना ।

तन-मन जीवन में मेरे "आनंद" प्रेम संगीत भर जाती,
पायल की छनछन और सिंदूर की लाली मुझको भाँति,
आशाओं के ऑगन में मधुबन सा सजा परिवार हमारा,
विश्वास सत्य सहयोग की नींव पर टिका गठबंधन
प्यारा,
सप्तपदी के इस अटूट बंधन को और भी सुंदर सजाना,
ओ चंदा ! सुनो आज तुम थोड़ी जल्दी निकल आना ।

- मोनिका डागा "आनंद", चेन्नई, तमिलनाडु
आपके स्नेह और प्यार का धन्यवाद !
रचना (स्वरचित व सर्वाधिकार सुरक्षित)

साहित्य की कसौटी पर "प्रेमचंद" साहित्य के उद्देश्य एवं सामाजिक प्रतिबद्धता

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह सहज

हरदा मध्य प्रदेश

"मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन उनके साहित्यिक योगदान और सामाजिक विचारों को सम्मानित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में "उपन्यास सम्राट" के रूप में भी जाना जाता है और उनकी कहानियां व उपन्यास आज भी प्रासंगिक और अमूल्य हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में मुंशी प्रेमचंद्र एक ऐसी प्रखर प्रतिभा हैं, जिनके साहित्यिक योगदान ने भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष को स्पर्श किया। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही गाँव में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव ने 'प्रेमचंद' नाम से हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लेखन किया। उनके बाल्यकाल की कठिनाइयाँ, गरीबी, माता-पिता की असामयिक मृत्यु और जीवन के संघर्षों ने उनकी लेखनी को समाज के यथार्थ से जोड़ दिया। वे प्रारंभिक शिक्षा के बाद अध्यापन एवं अन्य नौकरियों में लगे, पर अंततः साहित्यिक रचनाओं की ओर उनका लगाव उन्हें 'उपन्यास सम्राट' की ऊँचाई तक ले गया। प्रेमचंद का साहित्य सन-1900 के दशक के आरंभ में उर्दू भाषा से शुरू हुआ, आगे चलकर उन्होंने हिंदी को अपना माध्यम बनाया। उनका प्रथम हिंदी उपन्यास 'सेवासदन' (1918) वेश्यावृत्ति और महिला उत्पीड़न की

सामाजिक चुनौतियों को उजागर करता है वहीं 'प्रेमाश्रम' (1922) किसान आन्दोलनों और जमींदारों के शोषण पर केंद्रित है। ''रंगभूमि'' में सूरदास जैसे अंधे पात्र के माध्यम से समाज के विरोधाभासों को दर्शाया गया है, जबकि 'गोदान' भारतीय ग्राम्य जीवन का यथार्थवादी दस्तावेज है और 'गबन', 'कर्मभूमि', 'निर्मला' आदि उपन्यासों ने दहेज, अनमेल विवाह, जातिभेद, छुआछूत, विधवा जीवन, सामाजिक भेदभाव, और आर्थिक शोषण पर करारी चोट की। तीन सौ से अधिक कहानियाँ, अनगिनत निबंध, आलोचनात्मक लेख, संपादकीय, और पत्र लेखन में अपनी लेखनी की धार को परखने वाले प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन स्वाधीनता संग्राम, समाज सुधार आन्दोलनों और प्रगतिशील लेखन की मिसाल बन गया। उन्होंने 'हंस' पत्रिका एवं 'जागरण' समाचार पत्र का संपादन किया, फिल्मों के लिये कथा लेखन किया और प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष बने। उनकी मुख्य रचनाएँ जैसे 'कफन', 'पूस की रात', 'पंच परमेश्वर', 'बड़े घर की बेटी', 'महाजनी सभ्यता', 'बूढ़ी काकी', 'दो बैलों की कथा' आदि हिंदी साहित्य को अमूल्य भेंट हैं, जिनमें जीवन की सच्चाई, संघर्ष, सहानुभूति तथा संवेदनशीलता का ताना-बाना है। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन न होकर सामाजिक परिवर्तन और सुधार भी है, अतः उन्होंने अपनी रचनाओं में वंचित, शोषित, पीड़ित और दलितों को स्वर दिया। प्रेमचंद प्रभावशाली वक्ता, जागरूक नागरिक और गंभीर विचारक भी थे, उनका विश्वास समाज को बेहतर बनाने में साहित्य की भूमिका को लेकर अटल था। प्रेमचंद ने भारतीय समाज की जड़ताओं, समस्याओं और अंतर्विरोधों को कलम के माध्यम से उजागर कर साहित्य को जनजागरण का माध्यम बनाया तथा समत्व, करुणा और परिवर्तन की प्रेरणा दी। उनकी पुण्यतिथि पर उनके साहित्यिक, सामाजिक और वैचारिक योगदान को स्मरण करना केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्व का पुनः बोध है, क्योंकि 'प्रेमचंद युग' बना रहना हिंदी साहित्य के लिए प्रगतिशील चेतना का अमूल्य स्रोत है।

सारंडा अभ्यारण मामले मे झारखंड सरकार को आंशिक राहत , 31468 हेक्टेयर में हो सकता है

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सारंडा क्षेत्र को 31,468.25 हेक्टेयर में सेंक्चुअरी घोषित करने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल और वैध खनन कार्यों को सेंक्चुअरी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने हेमंत सरकार को एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश की तुलना में क्षेत्रफल बढ़ने का कारण पूछा। राज्य सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अध्ययन के बाद 5,519.41 हेक्टेयर को सेंक्चुअरी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव डीएफओ से लेकर पीसीसीएफ तक पहुंचा, लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं थी। वन सचिव ने शपथ पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी थी। राज्य सरकार ने कहा कि वह के निर्देशों के आधार पर 31,468.25 हेक्टेयर को सेंक्चुअरी घोषित करने के लिए तैयार है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की मांग की कि इससे खनन कार्य प्रभावित न हों।

Amicus Curiae ने क्षेत्रफल फिर से चिह्नित करने की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही 31,468.25 हेक्टेयर को चिह्नित कर चुकी है, जिसमें 126 कंपार्टमेंट हैं और वहां कोई खनन नहीं हो रहा। इसलिए दोबारा चिह्नांकन का समय नहीं देना चाहिए। सेल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सेंक्चुअरी घोषित करने से उनके खनन कार्य प्रभावित न हों, क्योंकि सेंक्चुअरी के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन पर प्रतिबंध रहता है। कोर्ट ने स्टील उत्पादन और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए सेल और वैध खनन को प्रभावित न होने देने का निर्देश दिया।

विक्की वशिष्ठ लगातार दूसरी बार आम आदमी पार्टी ब्लॉक लोंगोवाल के अध्यक्ष नियुक्त

परिवहन विशेष न्यूज

लोंगोवाल, (जगसीर सिंह) - आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा के नेतृत्व में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी ब्लॉक लोंगोवाल के अध्यक्ष श्री विक्की वशिष्ठ को लगातार दूसरी बार ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान, आप के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा और पूरी पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करते हुए श्री विक्की वशिष्ठ ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसे पूरी ईमानदारी और लगन से निभाऊँगा और पार्टी की मजबूती के लिए दिन-रात मेहनत करूँगा। श्री विक्की वशिष्ठ को लगातार दूसरी बार ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर नगर परिषद लोंगोवाल अध्यक्ष श्रीमती परमिंदर कौर बराड़, परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा रानी, पार्षद श्रीमती रीना रानी, आप के वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह ढिल्लों, आप बीसी विंग के राज्य सचिव राज सिंह राजू, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद मेला सिंह सूबेदार, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल बराड़, आप के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह तकीपुर, मास्टर नरिंदर शर्मा, सरपंच भीम दास बावा, सरपंच निहाल सिंह, सरपंच जगराज सिंह, जीवन सिंह आप सोशल मीडिया प्रभारी हलका सुनाम, हवलदार प्रीतम सिंह, सुखपाल सिंह बाजवा, गुरजंट खान, संजय गर्ग, नरेश जिंदल, सुखपाल तोची, बलकार सिंह, सरपंच लखवीर सिंह, सरपंच दर्शन सिंह, प्रधान भोला सिंह आदि ने खुशी जताई है।

ट्रक ट्रांसपोर्टर्स और सारथी: बिहार चुनाव की धड़कन, वोट की ताकत और विकास की कुंजी – डॉ. राजकुमार यादव

परिवहन विशेष न्यूज

पटना, बिहार : "बिहार की सड़कों पर दौड़ते ट्रक नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रगों में बहता खून हैं हम ! चुनावी समर में हमारी नैया पार लगाने वाले सारथी हैं, और अब समय आ गया है कि हमारी आवाज़ चुनावी गणित को हिला दे !₹ – ये शब्द हैं उफ्तत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव के, जो आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और चालकों की महत्ता पर जोर दे रहे हैं। विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को जोड़ते हुए, डॉ. यादव ने इस समुदाय की ताकत को उजागर किया, जो न केवल चुनावी लॉजिस्टिक्स की रीढ़ है, बल्कि वोट बैंक के रूप में भी निर्णायक साबित हो सकती है।

ट्रक ट्रांसपोर्टर्स: अर्थव्यवस्था के योद्धा ही नहीं बल्कि चुनाव के सेनापति है

बिहार की जीवंत अर्थव्यवस्था को गति देने वाले ट्रक ट्रांसपोर्टर्स और सारथी ऐसे योद्धा हैं, जो दिन-रात कीचड़ भरी सड़कों पर संघर्ष करते हुए माल ढोते हैं। भारत में करीब 1.4 करोड़ ट्रकों का विशाल बेड़ा है, जिसमें बिहार का हिस्सा लगभग 8 लाख ट्रक है – एक ऐसा आंकड़ा जो राज्य की सड़कों को जीवंत ही नहीं बनाता है बल्कि जीवन प्रदान करता है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी न केवल कृषि उत्पादों, उद्योग सामग्री, दवाइयां, किताबें और दैनिक आवश्यकताओं को गांव-गांव व शहर दर शहर पहुंचाते हैं, बल्कि चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की रैलियों, प्रचार सामग्री और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने का जिम्मा भी संभालते हैं। बिहार परिवहन विभाग के हालिया आदेश के अनुसार, चुनाव में उपयोग होने वाले वाहनों के लिए दैनिक दरें निर्धारित की गई हैं, जो दर्शाता है कि बिना इन सारथियों के, चुनावी मशीनरी थम सी जाती है !

डॉ. यादव कहते हैं, "हमारे ट्रक चुनावी अभियान की धुरी हैं। पटना से पूर्णिया तक, मुजफ्फरपुर से भागलपुर तक, हमारे सारथी रात-दिन दौड़ते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक दल हमारी मांगों – बेहतर सड़कें, ईंधन सब्सिडी, रात्रि विश्राम स्थल,टोल मुक्ति और सड़कों पर सुरक्षा – को सुनते हैं? हमारी भूमिका सिर्फ ढुलाई नहीं, बल्कि बिहार के विकास की नींव है !"

सारथी समुदाय वह है जो सामाजिक ताने-बाने का मजबूत धागा है सामाजिक संदर्भ में देखें तो ट्रक चालक और मालिक अधिकांशतः पिछड़े वर्गों, यादव समुदाय और अन्य ओबीसी से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये सारथी न केवल परिवार चलाते हैं, बल्कि गांवों में विभिन्न मदों से रोजगार सृजन भी करते हैं। भारत में ट्रक ड्राइवरों की संख्या करीब 1.9 करोड़ है, जिसमें बिहार के लगभग 6 लाख चालक और मालिक शामिल हैं। ये लोग कठिन जीवन जीते हैं – हिट एंड रन कानून के खिलाफ हालिया हड़तालों ने पूरे राज्य को ही नहीं देश को भी ठप कर दिया था, जो दर्शाता है कि उनकी एकजुटता कितनी

ताकतवर है। चुनाव में, ये सारथी मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे विभिन्न समुदायों के बीच पुल का काम करते हैं।

"हमारे सारथी बारिश में भीगते, धूप में झुलसते, लेकिन कभी रुकते नहीं। वे लोकतंत्र के असली पहरेदार हैं, जो चुनावी उत्साह को जीवंत रखते हैं," डॉ. यादव ने जोरदार अंदाज में कहा।

वोट का गणित के तहत निर्णायक ताकत जो चुनावी नतीजे पलट सकती है--अब बात वोट के गणित की। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 8 करोड़ है, और 243 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। ट्रक ट्रांसपोर्टर्स और सारथी समुदाय के लगभग 9 लाख सदस्य हैं, लेकिन उनके परिवारों को जोड़ें तो यह आंकड़ा 30-35 लाख वोटर्स तक पहुंच जाता है – यानी प्रति सीट औसतन 10000 हजार वोट ! पिछले चुनावों में कई सीटें 5 हजार से कम अंतर से जीती गईं, ऐसे में यह समुदाय किसी भी गठबंधन की किस्मत बदल सकता है। ओबीसी व अन्य समुदाय, जो बिहार में 22% वोट बैंक रखता है, में ट्रकर्स की बड़ी हिस्सेदारी है, जो एनडीए या महागठबंधन को झुका सकती है।

डॉ. यादव ने जीवंत भाषा में समझाया, "कल्पना कीजिए, अगर हमारे सारथी एकजुट हो जाएं, तो चुनावी मैदान में तूफान आ जाएगा ! हमारा वोट नदी की धारा है – जो दिशा में बह जाए, उसी की नैया पार लगेगी। राजनीतिक दल हमें नजरअंदाज करेंगे, तो हमारी ताकत उन्हें सबक सिखाएगी !"

राजनीतिक संदर्भ के तहत मांगें और अपील –

राजनीतिक रूप से, उफ्तत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सम्मान करता है, लेकिन मांग करता है कि ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं को एजेंडे में शामिल किया जाए। हिट एंड रन कानून, ड्राइवरों की सुरक्षा और आर्थिक पैकेज जैसी मुद्दों पर ध्यान दें। डॉ. यादव की अपील है, "ट्रकर्स को सम्मान दो, बिहार को मजबूत बनाओ ! हम चुनावी नैया के सारथी हैं, हमें इग्नोर मत करो – वरना वोट की चाबी हमारे हाथ में है !"

उफ्तत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा इस समुदाय की एकता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बिहार का ही नहीं पूरे देश का लोकतंत्र और मजबूत हो व देश विकसित एवं समृद्धशाली बने व वैभव से परिपूर्ण हो।

कद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय ने महामहिम राष्ट्रपति को लिखा पत्र

भारतीय सेना में "कलिंग रेजिमेंट" गठन हेतु मांग

राउरकेला: (8/10) — ओड़िशा राजनीती के कद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय ने भारतीय सेना में "कलिंग रेजिमेंट" के गठन की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है।

उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि भारतीय सेना में ओड़ीशा के जवानों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। ओड़ीया सैनिक देशभर की विभिन्न रेजिमेंटों में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा दे रहे हैं। फिर भी, ओड़ीशा के गौरवशाली इतिहास और निरंतर योगदान के बावजूद "कलिंग" नाम की कोई रेजिमेंट अब तक गठित नहीं की गई है, यह बात उन्होंने अपने पत्र में रेखांकित की।

श्री राय ने बताया कि भारतीय सेना में पहले से ही आसाम, पंजाब, मराठा,

डोगरा, गोरखा, राजपूत और नागालैंड आदि कई नामों पर रेजिमेंटें स्थापित हैं। ये रेजिमेंटें क्षेत्रीयता को नहीं बढ़ातीं, बल्कि भारतीय सेना की विविधता और एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करती हैं।

उन्होंने कहा कि "कलिंग रेजिमेंट" के गठन के पीछे चार मुख्य तर्क हैं —

कलिंग का ऐतिहासिक महत्व साहस, बलिदान और सभ्यतागत गौरव से जुड़ा है।

ऐसी रेजिमेंट युवाओं को प्रेरित करेगी और ओडिशा से सेना में भर्ती को और मज़बूती देगी।

यह कदम राष्ट्रीय एकता और समरसता को सुदृढ़ करेगा।

ओडिशा में पहले से ही कई प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठान हैं — जैसे गोपालपुर स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, आईएनएस चिलिका, और अब्दुल कलाम द्वीप पर मिसाइल परीक्षण केंद्र — जो इस दिशा में उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

श्री राय ने कहा कि राष्ट्रपति के नेतृत्व ने पहले ही लाखों लोगों को प्रेरित किया है, और उन्होंने आशा जताई कि उनके कार्यकाल के दौरान "कलिंग रेजिमेंट" के गठन की दिशा में ठोस कदम शीघ्र उठाए जाएंगे।

पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा एक भव्य खून दान कैंप का आयोजन किया

अमृतसर, 8 अक्टूबर साहिल बेरी

केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ अजय गुप्ता ने आज गुरुपर्व के पावन अवसर पर पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा एक भव्य खून दान कैंप का आयोजन में मुख्य तौर पर भाग लिया। विधायक डॉ गुप्ता ने बताया कि इस सेवा अभियान को सफल बनाने में पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ शर्मा, उपाध्यक्ष विशाल, चेयरमैन विवेक और सचिव रूपेश ने अपना योगदान दिया।

इस अवसर पर डिप्टी मेयर अनीता रानी के पुत्र तरुण बीर कैंडी, वार्ड प्रभारी विशाल गिल, समाजसेवी विक्की चीदा, एससी विंग संयोजक राजेश मल्होत्रा,

सुनील पहलवान, ब्लॉक प्रभारी अजय नोएल और चिराग ने भी शिविर की प्रतीकात्मक सफलता में अपना योगदान दिया।

विधायक डॉ गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से रक्तदान का संदेश हर कदम तक पहुँचाया गया और लोगों को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि आपको विश्वास दिलाते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार हमेशा आपके साथ है।

पंजाब में 5000 करोड़ की लागत से 'रोशन पंजाब' राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट के अभियान का शुभारंभ

करमजीत सिंह रिंटू ने 132 के.वी पावर कालोनी मजीठा रोड में बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण करने का किया शुभारंभ

अमृतसर, 8 अक्टूबर (साहिल बेरी)

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन एवं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज कर्मजीत सिंह रिंटू ने आज 132 के.वी पावर कालोनी मजीठा रोड में बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण करने का शुभारंभ किया। करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय ऊर्जा मंत्री श्री संजीव अरोड़ा जी के सक्रिय सहयोग से, आज 8 अक्टूबर 2025 पंजाब में 5000 करोड़ की लागत से ₹ रोशन पंजाब ₹ राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट के अभियान का शुभारंभ किया गया है। जिसके तहत

अमृतसर ज़िले में 307 करोड़ रुपये की लागत से बिजली के बुनियादी ढाँचे के निर्माण, विस्तार और नवीनीकरण का उद्घाटन किया जा रहा है।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत, अमृतसर शहर और अमृतसर ज़िले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रमुख कस्बों जैसे बाबा बकाला, जंडियाला गुरु, मजीठा, राजा सांसी, अजनाला और रमदास में बिजली क्षेत्र से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा किअमृतसर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 54 कुल 11 केवी फीडरों से बिजली का भार कम किया जाएगा और नए फीडर बनाए जाएँगे। इन 54 में से 8 फीडरों का कार्य पूरा हो चुका है।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि अमृतसर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे ओवरलोडेड वितरण ट्रांसफार्मर हैं। इन ट्रांसफार्मरों को डी-लोड करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 94 नए ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है और 19 ट्रांसफार्मरों का निर्माण 30/09/2025 तक पूरा हो चुका है।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि पुराने फोकल प्वाइंट अमृतसर में औद्योगिक उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा एक नया 66 केवी सबस्टेशन स्वीकृत किया गया है। इस सबस्टेशन का कार्य वर्ष 2026 के दौरान पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए उपर्युक्त कार्यों के पूरा होने से अमृतसर जिले के उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति मिल सकेगी। इस अवसर पर सीनियर डिप्टी में प्रियंका शर्मा,साही सगगर, बलविंदर काला, गुलज़ार सिंह, अनेक सिंह, अंकुश गुप्ता और पीएसपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

आठ अक्तूबर से माओवादी प्रतिरोध सप्ताह पर झारखंड पुलिस सतर्क

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने बुधवार यानी 8 अक्टूबर से झारखंड में 'प्रतिरोध सप्ताह' की घोषणा की है. संगठन की ओर से 15 अक्टूबर को बंद भी बुलाया गया है. इस बंद के मद्देनजर पुलिस ने संवेदनशील स्थानों और यातायात मार्गों पर सशस्त्र बलों की तैनाती के साथ राज्य भर में सुरक्षा कड़ी कर दी है. पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है.

महानिरीक्षक (संचालन) माइकल राज ने बताया कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सप्ताहभर के विरोध और बंद के दौरान सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं. इसके लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 12 बटालियन और झारखंड सशस्त्र पुलिस (जेएपी) व भारतीय आरक्षित वाहिनी (आईआरबी) की 20 टीमें तैनात की गई हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ''राज्य भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. हमने सामान्य आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील स्थानों, सरकारी कार्यालयों और रेल तथा सड़क नेटवर्क सहित यातायात मार्गों पर अतिरिक्त बल तैनात किए हैं.'' राज ने कहा कि पुलिस बिहार, छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिलों में संभावित प्रभावों से निपटने के लिए भी

तैयार है. राज्य पुलिस ने मंगलवार को जारी एक बयान में जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और बिना किसी डर के अपनी दैनिक गतिविधियां जारी रखने का आग्रह किया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि लगातार तलाशी अभियान और वांछित माओवादियों के खात्मे और आत्मसमर्पण के रूप में हालिया सफलता ने वामपंथी चरमपंथियों पर लगाम लगायी है. एक अधिकारी ने कहा, ''उनकी मौजूदगी सारंडा जंगल के कुछ इलाकों और झारखंड के लातेहार एवं चतरा के कुछ हिस्सों तक ही।

झारखंड विधानसभा सरकारी उपक्रम समिति का पश्चिमी सिंहभूम दौरा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला। आज पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत परिसदन- चाईबासा के सभागार में झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति निरल पूरती, विधायक- मझगांव विधानसभा क्षेत्र की अध्यक्षता एवं समिति सदस्य जगत माझी, विधायक- मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र की मौजूदगी तथा उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, वन प्रमंडल पदाधिकारी- चाईबासा आदित्य नारायण, परियोजना निदेशक-आईटीडीए जयदीप तिग्गा, सिविल सर्जन डॉ.सुशांत माझी, अपर उपायुक्त प्रवीण केरकेट्टा, सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो सहित जिला स्तरीय पदाधिकारियों, कार्यकारी विभाग के कार्यपालक अभियंताओं व अन्य की मौजूदगी में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। परिसदन आगमन पर समिति के सभापति व सदस्य का उप विकास

आयुक्त के द्वारा पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया।

बैठक उपरांत समिति के सभापति पूरती ने बताया कि झारखंड विधानसभा सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का प्रमुख उद्देश्य सरकारी उपक्रमों के संचालन, उन पर किए गए खर्च, योजनाओं की प्रगति और आम जनता को दी जा रही सेवाओं की निगरानी करना है। इसी के परिपेक्ष्य में आज समिति के द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले के 29 विभागों के पदाधिकारियों एवं कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया है तथा इस दौरान वन निगम, विद्युत विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उत्पाद विभाग, लघु सिंचाई विभाग, जलपथ प्रमंडल, खनन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन का जायजा लिया गया है। समिति के सभापति ने बताया कि समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों व अभियंताओं को समिति के समक्ष उपस्थापित मामलों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने तथा संबंधित प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है।

अशोक कुमार को मिला शिक्षकों का सम्मान

▪प्रधान शिक्षक प्रकोष्ठ, परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को शिक्षकों ने किया सम्मानित।

परिवहन विशेष न्यूज

अररिया। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ, बिहार के प्रधान शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक कुमार को अररिया जिला के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने शिक्षा विभाग द्वारा विशिष्ट शिक्षकों एवं प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण से संबंधित प्रेस नोट जारी करने के उपरांत इनके अथक प्रयास से लिए सराहना किया। इस पहल से राज्य के सभी विशिष्ट एवं प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर शिक्षकों ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर श्री अशोक कुमार का भव्य स्वागत किया तथा मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक कुमार ने कहा कि—"शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों की सुनिश्चितता ही हमारे महासंघ का प्रमुख लक्ष्य है। आने वाले समय में भी हम शिक्षक हित में ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे।"

इसकी जानकारी देते हुए परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ,बिहार के प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर ने बताया कि— "श्री अशोक कुमार के नेतृत्व में प्रधान शिक्षक प्रकोष्ठ ने निरंतर शिक्षक हित में सार्थक पहल की है। वेतन संरक्षण से जुड़े इस प्रयास ने अररिया सहित प्रदेश के अन्य जिलों के शिक्षकों को भी नई उम्मीद दी है।" महासंघ आगे भी सदैव इसी तरह शिक्षक हित में बेहतर कार्य करने के लिए कृतसंकल्पित है।

अभिवादन करने वालों में महासंघ के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर, चंदन कुमार, रवि कुमार, शैलेश मिश्र, शालिनी कुमारी, सोनी कुमारी, माहेनिगार सुल्तान, प्रवेश अहमद, अब्दुल मोबीन, सोनू कुमार शास्त्री, सुनीता कुमारी, अजराना खातून समेत दर्जनों शिक्षक शामिल थे।

(रूस और यूक्रेन के विनाशकारी युद्ध से उपजा कवि "प्राण" के मन का अन्तर्नाद)

अन्तर्नाद

======

हा त्राहिमाम ! हा त्राहिमाम ! हा त्राहिमाम ! की सुन पुकार।
क्रन्दन कर उठा हृदय कवि का, शिशुओं का सुनकर चीत्कार।।

ख़ाकीन कर दिया पतनों ने, दे दी पछाड़ उत्थानों को।।
आ रहा पसीना पथरीली, काँपती हुई चट्टानों को।

हिल उठे कलेजे शिखरों के, घाटियाँ फफक कर कीक उठीं।
संवेदनशील मानवों की, धड़कनें विह्वल हो चीख उठीं।।

मौतें हो उठीं मुखर मौनी, लाशों पर नर्तन दिखते हैं।
लग रहा प्रेम का पटाक्षेप, कवियों को असगुन दिखते हैं।।

आ गया ज्वार उन लहरों में, जो कभी आज तक उठीं न थीं।
गुँथ गईं युद्ध में वे कड़ियाँ, जो एक सूत में गठीं न थीं।।

लग रहा अधकटे रुण्डों की, कर उठी भैरवी खेती हो।
या मुण्डमाल के लिए पुनः, काली- रणचण्डी चेती हो।।

या महाकाल की खुली आँख, तीसरी ध्वंस की बेला है।
या स्वयं कालभैरव ने आ, जग को इस ओर धकेला है।।

धरती की छाती छेद उठे, धरती पर बने बनाए बम।
दहला दी दुनिया दहशत से, हो रही बमों की बम-बम-बम।।

टी वी की छाती से निकले, परिदृश्य दिखाई देते हैं।
कुछ सत्य और कुछ भ्रमकारी, सन्देश सुनाई देते हैं।।

इस ओर विवश यूक्रेन खड़ा, उस ओर रूस की लाचारी।
हर ओर गुरिल्ला वारों से, हर ओर दनादन बमबारी।।

हर ओर कराहें दबी-दबी, हर ओर गर्जना गर्वीली।
हर ओर आह तक पीली है, हर ओर वाह तक रौबीली।।

हर ओर चतुर्मुख धुआँ-धुआँ, हर ओर रक्त के फव्वारे।
हर ओर जो उठा ध्वंस राग, हर ओर मृत्यु द्वारे-द्वारे।।

हर ओर ध्वस्त हो रहा सृजन, हर ओर अहम् है मस्तक पर।
हर ओर भुखमरी पेटों की, हर ओर दम्भ है दस्तक पर।।

हर ओर थम रही किलकारी, हर ओर लग रहे अट्टहास।
हर ओर झर चुके पारिजात, हर ओर सुर्ख होता पलास।।

क्या नई भूख के प्यासों को, पानी न मिला पाताल तलक।
जो माँस चबा पी उठे खून, छोड़ी न नरों में खाल तलक।।

आखिर किसने जीवन्त देश, शमशान बना कर छोड़ दिया।
किसने मदमाते सिंहों के, सामने मेमना मोड़ दिया।।

किसके बल पर यह मेष-पुत्र, किसकी बातों में बहक गया।
वे कहाँ गए हित के रक्षक, जिनके कारण सब दहक गया।।

सबसे ताकतवर मैं ही हूँ, बस यही सिद्ध कर पाने को।
हिंसक पशुओं में सदा युद्ध, होते हैं भूख मिटाने को।

मानव-मानव को मारेगा, जग को विनाश समझायेगा ?
जंगली सभ्यता पनपेगी, क्या यह विकास कहलायेगा ??

जिस मानवता की जड़ें त्याग, सहयोग दया पर जमी रहीं।
वीरता विनय के साथ क्षमा, की भाव-भूमि पर टिकी रहीं।।

जिस बुद्ध जीव की अण्डज क्या, पिण्डज पर पहरेदारी थी।
स्वेदज-उद्भिज-जड़-जंगम की, रक्षा की जिम्मेदारी थी।।

असहाय लगा वह नरपुंगव, नैतिकता नीति विहीन लगी।
हो उठी बली फिर दानवता, ऐसी मानवता दीन लगी।।

रो रही धरा रो रहा गगन, रो उठा नर्क का द्वार-द्वार।
आँखों से झरने फूट पड़े, हा - हा खा - खा कर बार-बार।।

रोको !रोको-यह महायुद्ध, यह महानाश का कारण है।
यह द्वन्द्व नहीं है बातों का, यह प्रलय भयंकर भीषण है।।

यदि रुका नहीं यह महानाश, युग को कलंक लग जायेगा।
हर धवल कीर्ति की काया पर, मल भरा पंक लग जायेगा।।

गिर पड़ी कहीं बारूदों के, ढेरों पर जीती चिनगारी।
स्वाहा कर देगी सकल सृष्टि, बदला लेने की बीमारी।।

फिर कौन बचेगा महफ़िल में, क्या "प्राण" बिना तन डोलेंगे ?
कोयलें कहाँ पर कूकेंगीं, किस तरह पपीहे बोलेंगे ??

बेला-गुलाब-रजनीगन्धा, चम्पा-कनेर मिट जायेंगे ?
होगी दुर्गन्धित दिशा-दिशा, क्या सभी पुष्प मर जायेंगे ??

पेड़ों से लिपटीं बल्लरियाँ, कोपलें उमगती शाखों से।
हर ओर चटकती कली-कली, क्या देख सकोगे आँखों से ??

ये खिले बगीचे रंग-भवन, रम्भा सी इठलाती परियाँ।
मद भरी जवानी तरुणों की, मद बिन मदिराती सुन्दरियाँ।।

क्या रूप रूठ कर बैठेगा, क्या रंग मनाने आयेगा ?
क्या किलक सकेगी किलकारी, क्या जीवन राग सुनायेगा ??

वह बनक-ठनक प्रेमानुराग, रुतबा रुआब किसका होगा ?
फिर कौन करेगा प्रश्न यहाँ, कैसा जवाब किसका होगा ??

क्या मौत ठहाके मार-मार,जीवन को और चिढ़ायेगी ?
क्या कटुता इतनी कटु होगी, करुणा को मार भगायेगी ??

लहराती नदियों की कल-कल, फिर कौन सुनेगा दुनिया में ?
झरनों से झरते सपनों को, फिर कौन बुनेगा दुनिया में ??

क्या कमी आज आ गई कहो, सोचो समझो फिर यह तय हो।
हो किसी तरह यह युद्ध बन्द, हर ओर शान्ति का निर्णय हो।।

हाँ वही शान्ति ! जो जीवन में, प्राणों का मूल्य बताती है।
हाँ वही शान्ति ! निष्प्राणों में, जो जीवन भाव जगाती है।।

आती आँधी हो शमित दमित, हों शान्त अग्नि चारों आकर।
हों धरा गगन जल शान्त पवन, भूकम्प मेघ नदियाँ सागर।।

ज्वाला मुख गिरि हों शान्त-शान्त, नग शान्त शक्तियाँ औषधियाँ।
मन के विकार हों शान्त-शान्त, ब्रह्माण्ड "प्राण" बहती नदियाँ।।

ॐ शान्तिः।।ॐ शान्तिः।।ॐ शान्तिः।।

गिरेन्द्रसिंह भदौरिया ₹प्राण₹ इन्दौर,

इंडियन आइडल सीज़न 16 से पहले विशाल ददलानी ने बताया कि उन्हें कहां से मिलती है प्रेरणा

परिवहन विशेष न्यूज, मुंबई: भारत का सबसे प्रतिष्ठित सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर एक नए सीज़न के साथ लौट रहा है, जो यादों और सुरों की अनोखी दुनिया लेकर आएगा। इस बार का थीम है — यादों की प्लेलिस्ट: जहाँ आवाज़ें आज वाली और गाने आप वाले। यह सीज़न वादा करता है कि नए टैलेंट को पुराने सुनहरे गीतों के साथ मिलाकर एक संगीतमय सफ़र पेश किया जाएगा, जो भावनाओं, यादों और अद्भुत गायकी का जश्न होगा। इंडियन आइडल के नए सीज़न से पहले, विशाल ददलानी ने भावुक कहानी साझा की और बताया कि संगीत में उनकी प्रेरणा कहां से मिली— जो बचपन की प्यारी याद से और उनकी माँ की आवाज़ से जुड़ी है। उन्होंने बताया, "मेरी ज़िंदगी संगीत से बनी यादों से भरी हुई है। सबसे पहला गीत जो मुझे याद है, वह वही है जो मेरी माँ मुझे गाकर सुनाती थीं — 'फूलों का तारों का'। उसमें 'बहना' शब्द की जगह वे मेरा नाम लेती थीं। मेरे लिए, आज भी वह गीत सिर्फ़ उनकी आवाज़ में गूंजता है। मेरे माता-पिता का संगीत प्रेम ही मेरी प्रेरणा बना और धीरे-धीरे मुझे संगीत की ओर ले आया।" देखिए इंडियन आइडल का नया सीज़न 18 अक्टूबर 2025 से, हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे, केवल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सोनीलिव पर।

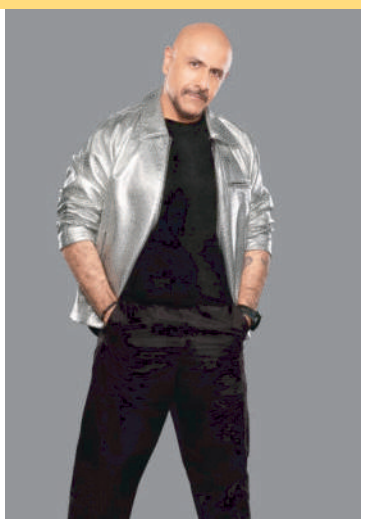

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023